

For All Competitive Exams

• LIVE

RNA[®]

By Ankit Avasthi Sir

THE HINDU

THE TIMES OF INDIA

HT Hindustan Times

The Indian EXPRESS

09:00Am 25 June 2024

REAL NEWS & ANALYSIS



If you find that people
are trying to put you
down, realize that there
is something about you
that makes them scared.







क्यों नीतीश-नायडू ने नहीं ली शपथ ? PM मोदी समेत 71 मंत्रियों ने ली शपथ...by...

2.2M views • 2 weeks ago >100x



शपथ से पहले संसद के सेंट्रल हॉल में NDA ने कैसे की मीटिंग ? उठे सवाल...by Anki...

1M views • 2 weeks ago 55x



बीजेपी ने स्पीकर पद के लिए ढूंढ लिया TDP का तोड़...विपक्ष हैरान..by Ankit...

2.1M views • 12 days ago >100x



सहयोगियों के सामने नहीं झुकी बीजेपी..क्या सच हो जाएगी 2026 की भविष्यवाणी ?by...

1.1M views • 13 days ago 64x

काँग्रेस से बन सकता हैं प्रोटेम स्पीकर ! क्या धरी रह जाएगी BJP की रणनीति ?



काँग्रेस से बन सकता है प्रोटेम स्पीकर ! क्या धरी रह जाएगी BJP की रणनीति ?..by Ankit Avasthi Sir
709K views • 5 days ago

Ankit Inspires India ✓ 3.85M subscribers

काँग्रेस से बन सकता है प्रोटेम स्पीकर ! क्या धरी रह जाएगी BJP की रणनीति ...

New

ankit sir

ankit avasthi sir

ankit inspires india

ankit avasthi

ankit sir current affairs

☰ Top stories ⋮

News about tem Speaker >



N NDTV

BJP's B Mahtab Now Pro-tem Speaker, Opposition Has Said Won't Assist Him ✓

22 hours ago

TH The Hindu

Mahtab takes oath as Pro-tem Speaker of 18th Lok Sabha ✓



51 minutes ago

in India Today

BJP's Bhartruhari Mahtab sworn in as Lok Sabha pro tem Speaker ✓

21 hours ago



HT Hindustan Times

Row over appointment of Bhartruhari Mahtab as pro-tem Speaker explained ✓

21 hours ago



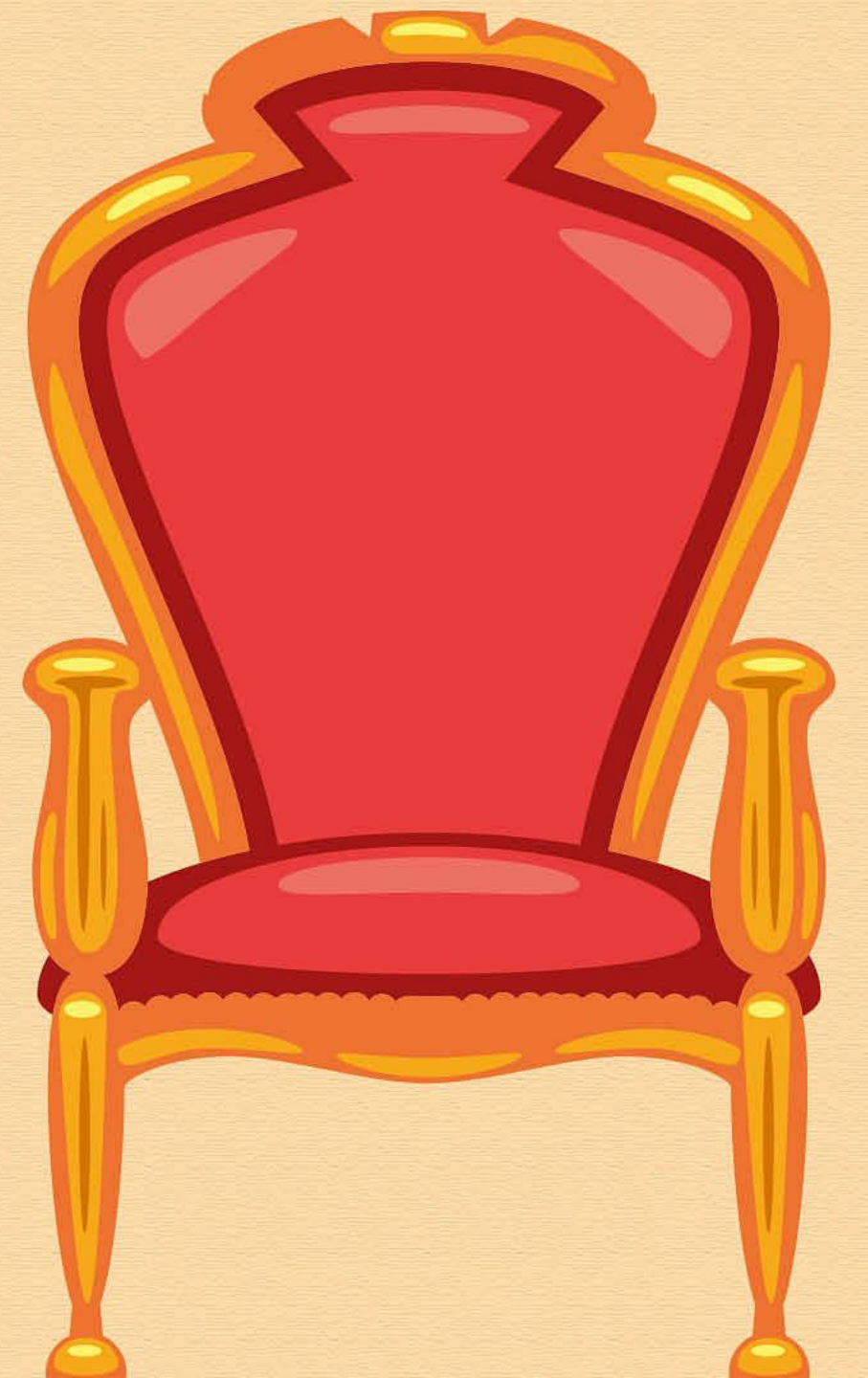
bt Business Today

Amid massive BJP vs Congress row, BJP MP Bhartruhari Mahtab takes...

21 hours ago



कौन होते हैं प्रोटेम स्पीकर...







भर्तृहरि महताब

लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर

- भर्तृहरि महताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब के बेटे हैं
- शुरुआत में बीजद से सांसद थे, 28 मार्च को भाजपा का दामन थामा था
- महताब 1998 से बीजद के टिकट पर कटक सीट से छह बार जीते
- 2024 कटक से फिर से जीते, इस बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर





Office of Kiren Rijiju

@RijijuOffice

Hon'ble Union Minister of Parliamentary Affairs & Minority Affairs Shri @KirenRijiju ji attended the swearing-in ceremony of Shri Bhartruhari Mahtab ji as the Protem Speaker of the Lok Sabha at Rashtrapati Bhavan. The ceremony was graced by Hon'ble President Smt. Droupadi Murmu ji, Hon'ble @VPIndia Shri Jagdeep Dhankhar ji & Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, Hon'ble MoS Shri @arjunrammeghwal ji & Hon'ble MoS Shri @Murugan_MoS ji.



10:19 AM · Jun 24, 2024 · 563 Views

ये देश संविधान से चलेगा



Pro-tem speaker appointment row: INDIA bloc leaders protest holding copy of Constitution

ANI - Last Updated: Jun 24, 2024, 06:01:00 PM IST

FOLLOW US SHARE FONT SIZE SAVE PRINT COMMENT

Synopsis

Pro-tem Speaker Appointment Row: Leaders from the INDIA bloc protested inside the Parliament premises against the appointment of Bhartruhari Mahtab as pro-tem speaker. Congress and other party members criticised the ruling BJP for neglecting key issues and the Dalit community. Samajwadi Party and Trinamool Congress MPs also joined the protest, accusing the Modi government of violating the Constitution. In response, Union Minister Sukanta Majumdar defended Mahtab's appointment and criticised the opposition for breaching conventions.



Pro-tem Speaker appointment row: 'NDA govt insulting opposition', says Congress Lok Sabha MP K Suresh

RELATED

Govt, opposition face-off on protem Speaker issue ahead of first Lok Sabha session

Congress upset over pro-tem speaker election, will not assist during oath-taking of MPs

Amid the row over the appointment of [Bhartruhari Mahtab](#) as [pro-tem speaker](#), [INDIA bloc leaders](#) on Monday carried out a protest holding copies of the [Constitution](#) inside the [Parliament](#) premises in the national capital.

Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, party leader Rahul Gandhi, and party chief Mallikarjun Kharge took part in the protest.

Congress MP Gaurav Gogoi said, " The ruling party hasn't forgotten their

haughtiness...we can see that they are ignoring the key subjects of the country...the whole Dalit community in India could witness a historic seen if K Suresh were appointed as Pro-tem Speaker...today, BJP has not just neglected Congress, INDIA alliance and K Suresh but the whole Dalit community."

Videos



US senators grill Boeing CEO David Calhoun over hefty paychecks



Delhi BJP MPs take oath as Lok Sabha member



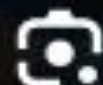
NEWS
24
Think First

कांग्रेस सांसद के सुरेश

"बीजेपी सांसद महताब को प्रोटेम
स्पीकर बनाया जाना संदन की परंपरा
के खिलाफ है, मैं सदन में 8 बार का
सांसद हूं, महताब 7 बार के सांसद हैं,
NDA ने विपक्ष का अपमान किया है"

“

Protem Speaker



As per the second proviso to article 94 of the Constitution, the office of the Speaker becomes vacant immediately before the first meeting of the new Lok Sabha. In that case, the duties of the Speaker are to be performed by a Member of the House appointed for this purpose by the President as Speaker pro tem.



Ministry of Parliamentary Affairs

<https://www.mpa.gov.in> › default › files › parlia2 PDF ⋮

2 Ushering in a New Lok Sabha ✓

क्या है भर्तृहरि महताब के नाम पर विवाद

जैसे ही संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने भर्तृहरि महताब के नाम का एलान किया था, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि **उनकी पार्टी के आठ बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि महताब सात बार के ही सांसद हैं।** कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि **परंपरा के अनुसार, जिस सांसद ने संसद में अधिकतम कार्यकाल पूरा किया है, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए।**



सरकार का जवाब

संसदीय कार्य मंत्री किरें रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार कर कहा कि महताब लगातार सात बार के लोकसभा सदस्य हैं, जिससे वह इस पद के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश 1998 और 2004 में चुनाव हार गए थे, जिस कारण उनका मौजूदा कार्यकाल निचले सदन में लगातार चौथा कार्यकाल है। इससे पहले, वह 1989, 1991, 1996 और 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए थे।



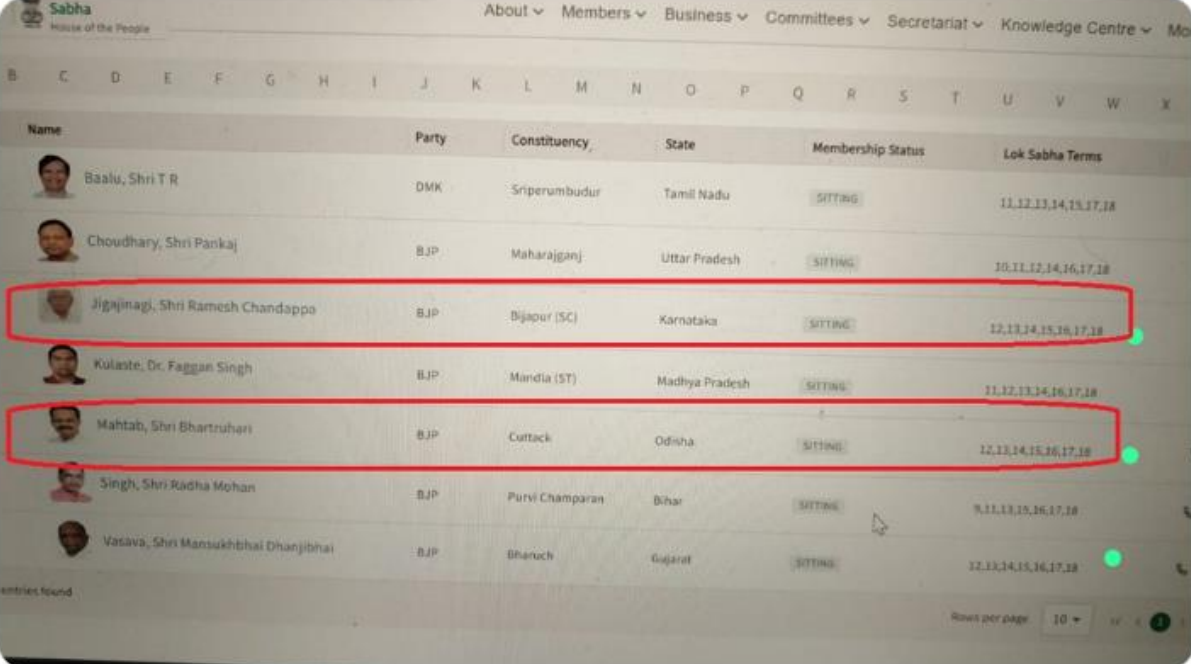
Kodikunnil Suresh of the INC, who is in his 8th term, should have been Speaker Protem.

But Bhartruhari Mahtab of the BJP has been appointed on the flimsy grounds that he has greater claim because this is his 7th consecutive term.


If this argument is adopted, then why has Ramesh Chandappa Jigajinagi, a BJP MP who is also in his 7th consecutive term, not been considered? Is it because he is a Dalit like Suresh?

श्री सुरेश कुडीकुनल जी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का विषय आपके मन में सुरेश जी की वरिष्ठता या उनके प्रति अनुराग से प्रेरित है या [@BJP4India](#) और प्रधानमंत्री श्री [@narendramodi](#) जी के प्रति द्वेष से प्रेरित है यदि आप उनकी वरिष्ठता के प्रति इतने भाव विभोर हो रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी दृष्टि में आपके इतने वरिष्ठ और योग्य साथी श्री सुरेश कुडीकुनल नेता प्रतिपक्ष बनेंगे अथवा आगामी केरल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे। यदि वे इसमें से कुछ भी नहीं बनेंगे और इस अस्थायी पद के लिए केवल आपकी राजनीति के मोहरे बनेंगे। साफ़ लगता है कि सुरेश जी तो बहाना हैं बस किसी न किसी मुद्दे पर क्लेश करवाना है

[Translate post](#)



Name	Party	Constituency	State	Membership Status	Lok Sabha Terms
Baalu, Shri T R	DMK	Sriperumbudur	Tamil Nadu	SITTING	11,12,13,14,15,17,18
Choudhary, Shri Pankaj	BJP	Maharajanj	Uttar Pradesh	SITTING	10,11,12,14,16,17,18
Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa	BJP	Bijapur (SC)	Karnataka	SITTING	12,13,14,15,16,17,18
Kulaste, Dr. Fagga Singh	BJP	Mandla (ST)	Madhya Pradesh	SITTING	11,12,13,14,16,17,18
Mahtab, Shri Bhartruhari	BJP	Cuttack	Odisha	SITTING	12,13,14,15,16,17,18
Singh, Shri Radha Mohan	BJP	Purni Champaran	Bihar	SITTING	9,11,13,15,16,17,18
Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai	BJP	Bhanoch	Gujarat	SITTING	12,13,14,15,16,17,18

 **Jairam Ramesh** ✓ @Jairam_Ramesh · Jun 23

Kodikunnil Suresh of the INC, who is in his 8th term, should have been Speaker Protem.

But Bhartruhari Mahtab of the BJP has been appointed on the flimsy grounds that he has greater claim because this is his 7th consecutive term. ...

[Show more](#)

वरिष्ठता को किया गया दरकिनार?

अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्या ऐसा होना जरूरी है कि अगर किसी शख्स को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए तो उसे लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होना चाहिए। तो इतिहास के पन्ने पलटने पर देख सकते हैं कि **प्रोटेम नियम को लेकर दो अपवाद हैं।**

- 1. लोकसभा में सबसे वरिष्ठ नहीं होने वाले सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में दो बार नियुक्त किया जा चुका है।**
2. सबसे पहले सन् 1956 में ऐसा हुआ था। तब सरदार हुकम सिंह को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1977 में डी.एन. तिवारी को अस्थायी स्पीकर बनाया था।

राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ

प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाती है। इसके बाद मंत्री राष्ट्रपति को एक नोट सौंपते हैं, जिसमें प्रो-टेम स्पीकर और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति मांगी जाती है। वे शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय भी तय करते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद मंत्रालय प्रोटेम स्पीकर और अन्य सदस्यों को उनकी नियुक्तियों के बारे में सूचित करता है, और अंत में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य तीन सदस्यों को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं।

Protem Speaker

कांग्रेस से बन सकता है प्रोटेम स्पीकर ! क्या धरी रह जाएगी BJP की रणनीति ?..by Ankit Avasthi Sir



Ankit Ins...
3.85M...

Join



Subscribed

16K



Share

Download



710K views 5 days ago #electionresults2024 #protemspeaker #AnkitSir

हंगामेदार आगाज • पीएम मोदी शपथ लेने आए तो विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लहराईं



संविधान इमरजेंसी में कुचला गया : मोदी 10 साल से अघोषित इमरजेंसी है : कांग्रेस

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज काफी हंगामेदार रहा। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और संविधान की प्रतियां लहराने लगे। पीएम ने कहा, संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। इमरजेंसी को लेकर मोदी ने कहा, '25 जून न भूलने वाला दिन है। 50 साल पहले इसी दिन संविधान को कुचल दिया गया था। भारत को जेलखाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। नई पीढ़ी इसे कभी नहीं भूलेगी।' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'देश में पिछले 10 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है।' वहीं, सोमवार को 280 सांसदों ने शपथ ली। इससे पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। उधर, राज्यसभा में जेपी नड्डा नेता सदन बनाए गए। बता दें कि नड्डा भाजपा अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं।

राहुल का पलटवार... संविधान पर हमले स्वीकार नहीं करेंगे; सरकार के पहले 15 दिन की कमियां भी गिनाईं



सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने संविधान की प्रतियां लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

स्पीकर पैनल: 3 सांसदों ने नहीं ली शपथ

8 बार के कांग्रेस सांसद के, सुरेश को प्रोटेम स्पीकर न बनाने पर 3 विपक्षी सांसदों सुरेश, केटी बालू, सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर पद की शपथ नहीं ली। राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए इन्हें स्पीकर पैनल का सदस्य नामित किया था।

राहुल ने कहा, मोदी व उनकी सरकार द्वारा संविधान पर हो रहे हमले इंडिया ब्लॉक स्वीकार नहीं करेगा। पीएम को जवाबदेही के बिना भागने नहीं देंगे। राहुल ने सोशल मीडिया पर सरकार के पहले 15 दिनों में ट्रेन हादसा व नीट पचां लीक जैसी कमियां गिनाईं। फैजाबाद (अयोध्या) के सांसद को तरजीह; सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी आगे खड़े ये शख्स अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। 9 बार के विधायक अवधेश पहली बार संसद पहुंचे हैं। विपक्ष की दीर्घा में पहली सीट पर राहुल थे। उनके बगल में अखिलेश और उनके पास अवधेश बैठे थे। विधानसभा में भी वे अखिलेश के बगल बैठते थे।

शिक्षा मंत्री पर तंज... नीट-नीट, शेम-शेम

संसद में जब शपथ ग्रहण करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का नाम बुलाया गया तो विपक्ष ने 'नीट-नीट, शेम-शेम' का नारा लगाना शुरू कर दिया। विपक्ष इस्तीफे का दबाव बना रहा है। 10 दिन में 4 पेपर रद्द या स्थगित हो चुके हैं।

स्पीकर पैनल: 3 सांसदों ने नहीं ली शपथ

8 बार के कांग्रेस सांसद के, सुरेश को प्रोटेम स्पीकर न बनाने पर 3 विपक्षी सांसदों सुरेश, केटी बालू, सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर पद की शपथ नहीं ली। राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए इन्हें स्पीकर पैनल का सदस्य नामित किया था।

18TH LOK SABHA STARTS



☰ Top stories ⋮

News about 18th Lok Sabha >



 The Indian Express

18th Lok Sabha session begins today: How do MPs take oath? What happens if an M...


21 hours ago

 News18

Parliament Highlights: Lok Sabha Adjourned For The Day, To Reconvene On...



5 hours ago

 Hindustan Times

Oaths and protests: 18th Lok Sabha off to combative start ✓

9 minutes ago




 Times of India

Lok Sabha Session 2024 Live Updates: President Murmu hosts dinner for P...

6 hours ago



 India Today

PM Modi, his ministers take oath as MPs, Opposition gears up for NEET fight ✓

20 hours ago







संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया।
दरअसल, 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं।

PM ने कहा- 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेलखाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था।

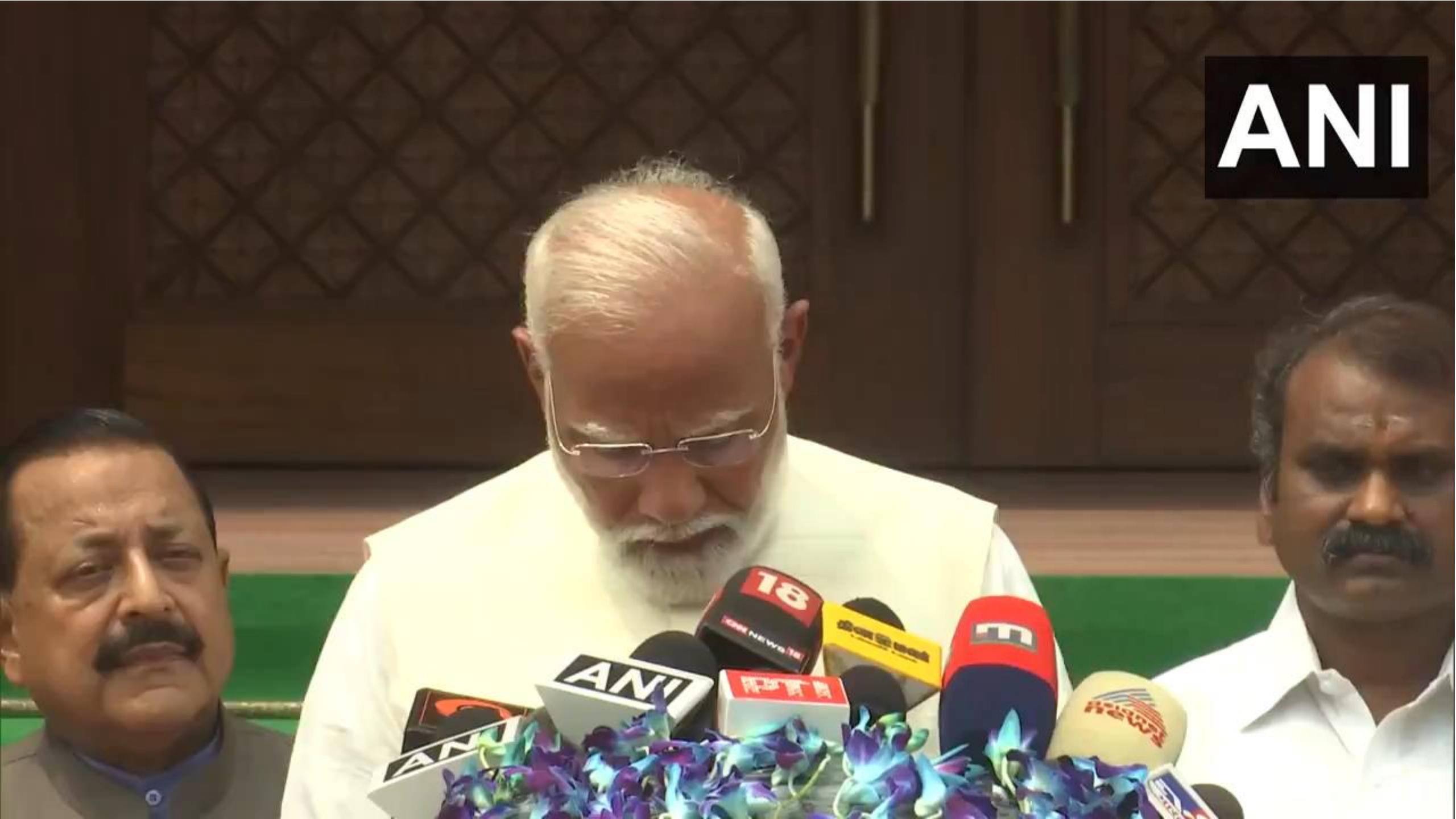
उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, जो 50 साल पहले की गई थी।

प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकेंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा, नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी।

ANI



ANI





Mallikarjun Kharge

@kharge



प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने customary शब्द आज ज़रूरत से ज़्यादा बोले। इसे कहते हैं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया।

देश को आशा थी कि मोदी जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे।

- ◆ NEET व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, पर उन्होंने अपनी सरकार की धाँधली व भ्रष्टाचार के बारे में कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली।
- ◆ हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में भी मोदी जी मौन साधे रहे।
- ◆ मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है, पर मोदी जी न वहाँ गए और ना ही उन्होंने आज के अपने भाषण में ताज़ा हिंसा के बारे में कोई चिंता व्यक्त की है।
- ◆ असम व पूर्वोत्तर में बाढ़ हो, कमरतोड़ महँगाई हो, रूपया का गिरना हो, Exit Poll-Stock Market घोटाला हो;
- ◆ अगली जनगणना लंबे समय से मोदी सरकार ने लंबित रखी है, जातिगत जनगणना पर भी मोदी जी बिलकुल चुप थे।

@narendramodi जी, आप विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। 50 साल पुरानी Emergency की याद दिला रहे हैं, पिछले 10 साल के Undeclared Emergency को भूल गए जिसका जनता ने अंत कर दिया।

लोगों ने मोदी जी के खिलाफ़ जनमत दिया है। इसके बावजूद अगर वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें काम करना चाहिए।

"जनता को substance चाहिए slogan नहीं" - ये खुद याद रखें।

विपक्ष व INDIA जनबंधन संसद में Consensus चाहता है, हम जनता की आवाज़ सदन, सड़क और सभी के समक्ष उठाते रहेंगे।

संविधान की रक्षा हम करेंगे!

लोकतंत्र ज़िंदाबाद!

[Translate post](#)



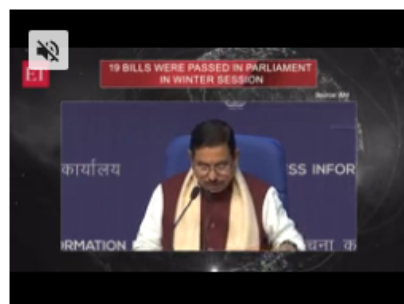
11:58 AM · Jun 24, 2024 · 169K Views

Half of bills passed by 17th Lok Sabha discussed for less than two hours each: Report

PTI - Last Updated: Dec 23, 2023, 03:34:00 PM IST

FOLLOW US
 SHARE
 FONT SIZE
 SAVE
 PRINT
 COMMENT ²

Synopsis
 Data compiled by think tank PRS Legislative Research reveals that half of the bills passed by the 17th Lok Sabha were discussed for less than two hours each, with only 16% referred to parliamentary standing committees. During the term, 172 bills were discussed and passed, of which 86 in the Lok Sabha and 103 in the Rajya Sabha had discussions of less than two hours each.



Total 19 bills were passed in Parliament in winter session: P. Chidambaram

Half of the [bills](#) passed by the 17th [Lok Sabha](#) so far were discussed for less than two hours each and only 16 per cent of them were referred to parliamentary standing committees, data compiled by think tank PRS Legislative Research shows. According to an analysis by PRS Legislative Research, 172 bills were discussed and passed during the term of 17th Lok

Sabha, of which 86 bills in the Lok Sabha and 103 bills in the [Rajya Sabha](#) were discussed for less than two hours each.

Similarly, of the 172 bills, only 16 bills in the Lok Sabha and 11 in the Rajya Sabha saw more than 30 members taking part in the debate.

The report came a day after the conclusion of the [Winter session](#) - the last full-fledged session of the 17th Lok Sabha.

Speaker

Ajay Sahai
 DG & CEO, FIEO

Videos

US senators grill Boeing CEO David Calhoun over...
 Delhi BJP MPs take oath as Lok Sabha member

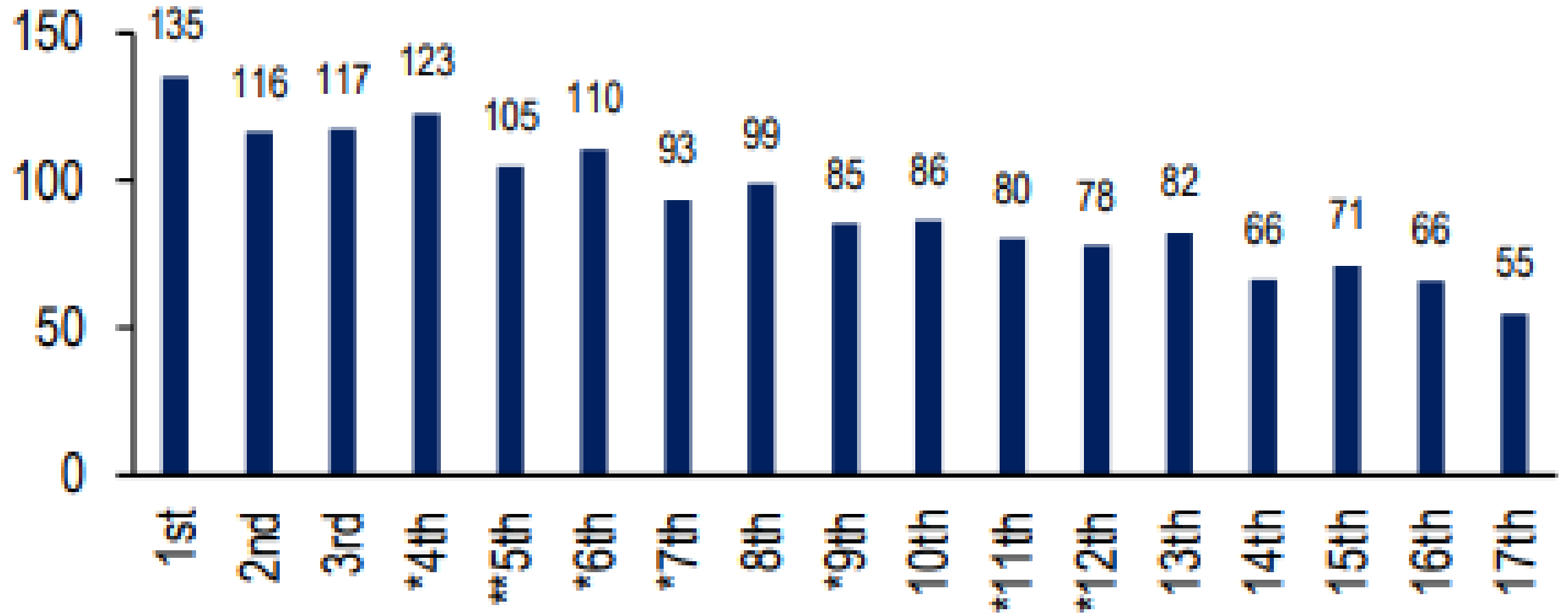
Of all the Lok Sabhas with completed terms, **the 17th Lok Sabha witnessed several regrettable firsts. It was the first to not appoint a Deputy Speaker, it recorded the lowest number of sittings, it passed significant legislation such as criminal reform Bills when more than 70% of the Opposition MPs were suspended, and the Prime Minister did not answer any questions orally and only one in writing.** **While these developments mark a new low in parliamentary functioning, this is not an anomaly; rather, it is a trend that has continued for more than 30 years.**



The annual average of Bills passed declined from 65 in the 1952-1990 period to 48 in 1991-2023. The number of Bills sent to committees for scrutiny also dwindled consistently, with the 17th Lok Sabha sending only 16% of Bills for scrutiny, the lowest in the past four Lok Sabhas .

The declining number of sitting days and hours in the Lok Sabha limits the scope for debates and diminishes MPs' participation. Prior to 1990, each Lok Sabha typically convened for over 550 days on average, spanning 3,500 hours. However, post-1990, an average Lok Sabha only meets for 345 days, spanning less than 1,800 hours. The 17th Lok Sabha had the least number of sittings (274)

Average annual sitting days



Note: * indicates a term less than five years; ** indicates a six year term.

Parliamentary tools allow MPs to ensure executive accountability and remediate potential issues for their constituents.

1. A half-hour discussion enables MPs to deliberate on responses to parliamentary questions. Before the 1990s, there were 88 such discussions per Lok Sabha. Post-1990, there were only 11 half-hour discussions per Lok Sabha.

The 17th Lok Sabha permitted only one such discussion, marking an all-time low.

2. Short-duration discussions, permitting members to initiate discussions on matters of public importance, were prevalent before 1990, averaging 46 per Lok Sabha. Post-1990, this number diminished to 39, with the **17th Lok Sabha engaging in only 13 such discussions.**

3. Calling attention, a vital tool allowing MPs to draw attention to issues and elicit responses from ministers was extensively used between 1957 and 1990, with an average of 300 notices allowed per Lok Sabha. **Post-1990, only 40 notices have been allowed per Lok Sabha.**

The 17th Lok Sabha allowed only one such discussion.

4. The adjournment motion, employed to address urgent issues with a subsequent vote, serves as an expression of disagreement with the government's policies. Pre-1990, the Lok Sabha permitted discussion and voting on four such motions on average. Post-1990, this number decreased to three. **The 16th and 17th Lok Sabha allowed no adjournment motions**

WHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF MOTIONS USED IN PARLIAMENT

- ADJOURNMENT MOTION
- SHORT DURATION DISCUSSION
- MOTION WITH A VOTE
- NO-CONFIDENCE MOTION
- CONFIDENCE MOTION
- PRIVILEGE MOTION
- MOTION OF THANKS
- CUT MOTION
- CLOSURE MOTION

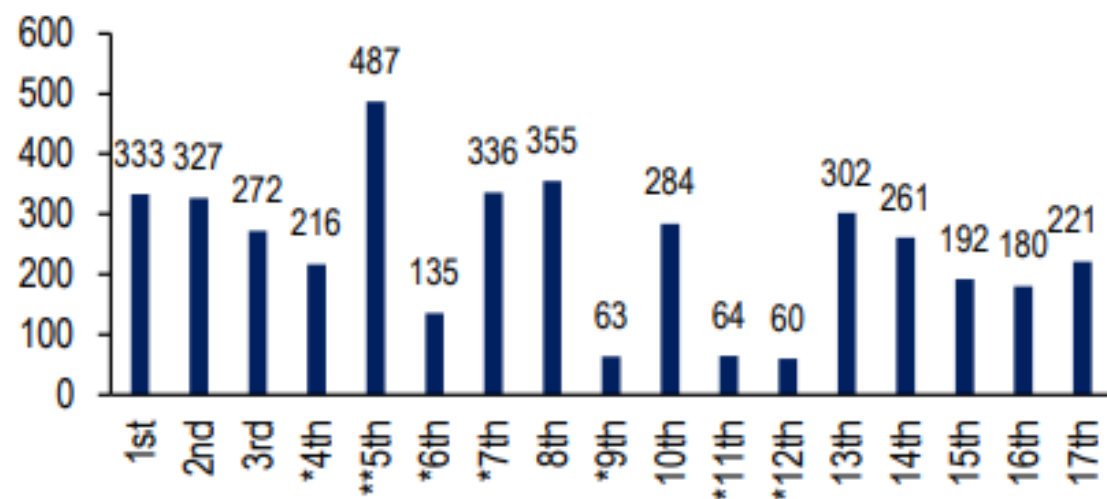


5. There has also been a substantial decline in the time spent on discussing the Union Budget, Ministry-wise demands, and the Finance Bill, from around 120 hours annually before 1990 to a mere 35 hours post-1990. Notably, ministry-wise demands have been passed without discussion only five times since 1952 — and all of them after 1999

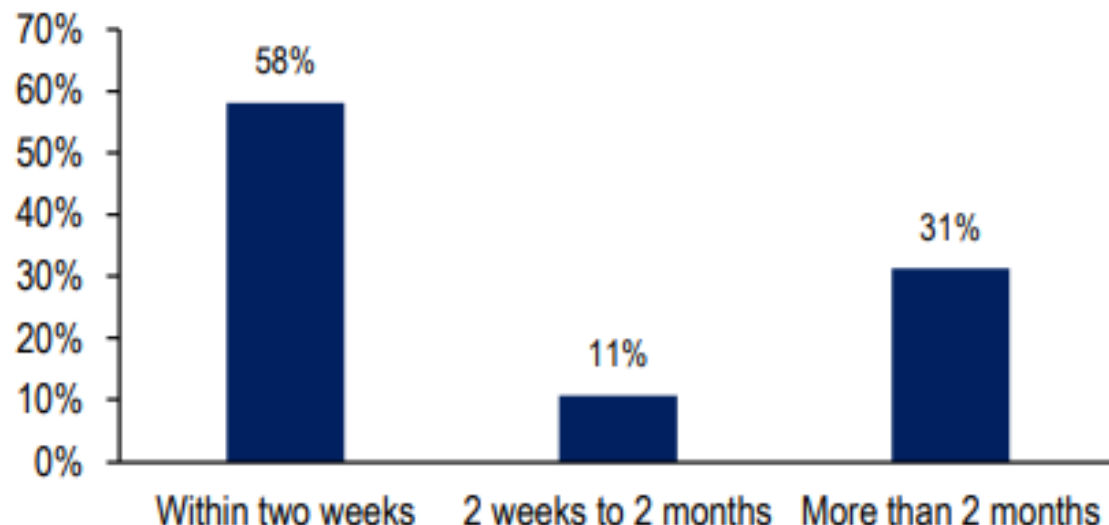
Scholars and experts identified this trend early on, with a notable instance being a 2000 paper authored by Dr. Subhash C Kashyap, the former Secretary-General of Lok Sabha. He proposed the establishment of a Parliamentary Reforms Commission or a 'Study of Parliament Group' outside parliamentary confines. Urgent and comprehensive parliamentary reforms are imperative to restore the efficacy of parliamentary procedures and practices.

179 Bills passed; 58% Bills passed within 2 weeks of introduction

Bills passed by Parliament



Days between introduction and passing of Bills in Parliament



Note: * indicates a term less than five years; ** indicates a six-year term.
This figure includes Finance and Appropriation Bills.

- 179 Bills (excluding Finance and Appropriation Bills) were passed. The Ministries of Finance and Home Affairs piloted the highest number of Bills (15% each), followed by Law and Justice (9%), and Health and Family Welfare (9%).
- Key Bills passed include, the Women's Reservation Bill, 2023, the J&K Reorganisation Bill, 2019, the Appointment of CEC Bill, 2023, three Labour Codes, the Digital Data Protection Bill, 2023, and three Farm laws (which were later repealed). Three Bills replacing the IPC, 1860, the CrPC, 1973, and the Indian Evidence Act, 1872 were also passed.





Narendra Modi, Prime Minister

पीठासीन : भर्तृहरि महताब, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष

News

tant Interpreters for Regional Languages on contractual basis in Lok Sab

11:07

INDIA गठबंधन जान की बाजी लगाकर संविधान की रक्षा करेगा.

[Translate post](#)



॥ ये देश संविधान से चलेगा ॥

0:04 / 0:08    

18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन 262 सांसदों ने शपथ ली है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और आखिरी में मध्य प्रदेश के ज्ञानेश्वर पाटिल ने शपथ ली। कल 270 सांसद शपथ लेंगे। लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट का नाम भी कल सामने आ सकता है।

लोकसभा सत्र का पहला दिन सोमवार को विपक्ष के नाम रहा। सत्र शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर हाथ में संविधान की कॉपी लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की।

यह प्रदर्शन संसद के अंदर भी देखने को मिला। जब सांसदों की शपथ शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्डियम पर आए। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने संविधान की कॉपी PM की तरफ दिखाई। प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद जब लौटे तो दोनों तरफ से हाथ जोड़कर अभिवादन हुआ।

प्रधानमंत्री के बाद प्रोटेम स्पीकर के पैनल में शामिल 5 वरिष्ठ सांसदों को शपथ लेना था। इनमें 3 विपक्षी सांसद- सुरेश कोडिकुन्निल (कांग्रेस), टीआर बालू (DMK), सुदीप बंदोपाध्याय (TMC) थे। प्रोटेम स्पीकर ने जब इनका नाम पुकारा तो कोई भी सांसद हॉल में उपस्थित नहीं था। ये बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।

विरोध यहीं खत्म नहीं हुआ। NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों के बीच जब शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शपथ लेने मंच की ओर बढ़े तो विपक्ष की ओर हूटिंग शुरू हो गई- **NEET-NEET, शेम-शेम**। हालांकि धर्मेन्द्र प्रधान का कोई रिएक्शन नहीं दिखा।



पीठासीन : भर्तृहरि महताब, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष





NEET PAPER LEAK

नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर CBI ने किया FIR दर्ज





Ankit Kumar Avasthi ✓

@kaankit



पिछले कुछ दिनों में-

NEET_PG स्थगित

NEET_UG पर सीबीआई जांच, मुकदमा, नए खुलासे

UGC_NET लीक और स्थगित

CSIR_NET स्थगित

बिहार TET स्थगित

इसके अलावे भी होंगे... आप लोग जोड़ लिजिए...

[Translate post](#)

10:15 AM · Jun 23, 2024 · **57.9K** Views

मोदी सरकार के पहले 15 दिन 📌

[Translate post](#)

मोदी सरकार के पहले 15 दिन





Rahul Gandhi ✓

@RahulGandhi



NDA के पहले 15 दिन!

1. भीषण ट्रेन दुर्घटना
2. कश्मीर में आतंकवादी हमले
3. ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा
4. NEET घोटाला
5. NEET PG निरस्त
6. UGC NET का पेपर लीक
7. दूध, दाल, गैस, टोल और महंगे
8. आग से धधकते जंगल
9. जल संकट
10. हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें

Psychologically backfoot पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं।

नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए acceptable नहीं है - और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे।

INDIA का मज़बूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बच कर निकलने नहीं देगा।

[Translate post](#)

1:24 PM · Jun 24, 2024 · 1.9M Views

फ्रंट लाइन में राहुल-अखिलेश के साथ अयोध्या के सांसद को जगह

विपक्ष के नेताओं के सिटिंग अरेंजमेंट की खूब चर्चा रही। विपक्ष के फ्रंट लाइन में सफेद टी-शर्ट पहने राहुल गांधी नजर आए तो लाल टोपी लगाए हुए अखिलेश यादव उनके बगल में बैठे थे। अखिलेश के ठीक बगल में फैजाबाद (अयोध्या) के सांसद अवधेश प्रसाद बैठे थे।

अखिलेश हर जगह उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे थे और कई मौकों पर तो खुद से आगे भी रख रहे थे। इसी लाइन में ममता बनर्जी के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को भी जगह दी गई। संकेत साफ था- विपक्ष इस बार मजबूती के साथ एकजुट है।





सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते

Constitution of India
भारत का संविधान

THE CONSTITUTION OF INDIA

भारत का संविधान

भारत का संविधान



23

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

LOK SABHA

SPEAKER



NCERT

FOUNDATION BATCH

EMI

OPTION AVAILABLE

OFFER PRICE
4999 Rs

Purchase Time to Pay
→ **2500 Rs**

Next Month to Pay
→ **2500 Rs**

EMI OFFER AVAILABLE FOR 24HR ONLY/-

- 1.SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
- 2.SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
- 4.SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
- 5.ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:



T&C APPLY



BY ANKIT AVASTHI SIR

LIMITED SEATS

और **EMI INFORMATION** के लिए

7878158882 अभी कॉल करें

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM









K.G.F

An aerial photograph of a large-scale open-pit gold mine. The mine is characterized by its terraced, stepped levels of yellowish-brown earth and rock. A winding road or path is visible on the left side, and a small structure is situated in the middle ground. The background shows a hazy landscape with distant hills under a clear sky.

K.G.F

Kolar Gold Fields

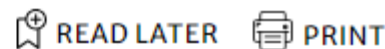


State clears Centre's proposal on reviving gold mining at KGF

The Centre submitted the proposal for reviving gold mining and auction of 13 tailing dumps spread over 1003.4 acres at KGF

Published - June 20, 2024 08:12 pm IST - BENGALURU

THE HINDU BUREAU



DECCAN HERALD

Karnataka okays Centre's proposal to revive gold mining at KGF

The Cabinet has given its approval for the central government's proposal to continue the mining activities in 13 tailing dumps of 1,003.4 acres at the defunct Bharat Gold Mines Limited's (BGML) mine at KGF in Kolar district



DHNS

Last Updated : 21 June 2024, 05:26 IST



Kolar district is a district in the state of Karnataka, India. Kolar is the district headquarters. Located in southern Karnataka, it is the state's easternmost district. [Wikipedia](#)

कोलार ज़िला भारत के कर्नाटक राज्य का एक ज़िला है। ज़िले का मुख्यालय कोलार है। अपने सोने की खानों के लिये प्रसिद्ध यह जिला बंगलोर के उत्तर-पूर्व में है। [विकिपीडिया](#)

हिन्दी में खोजें : [कोलार](#)

Area: 4,012 km²

Division: [Bengaluru](#)

Headquarters: [Kolar](#)

ISO 3166 code: IN-KA-KL

Literacy: 74.33%

Lok Sabha constituency: [Kolar Lok Sabha constituency](#)

Sex ratio: 976 ♀ / 1000♂

KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स

कर्नाटक के दक्षिण-पूर्व इलाके में कोलार जिला स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर रोबर्ट्सनपेट एक तहसील है। यहीं पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है, पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइंस है। जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।





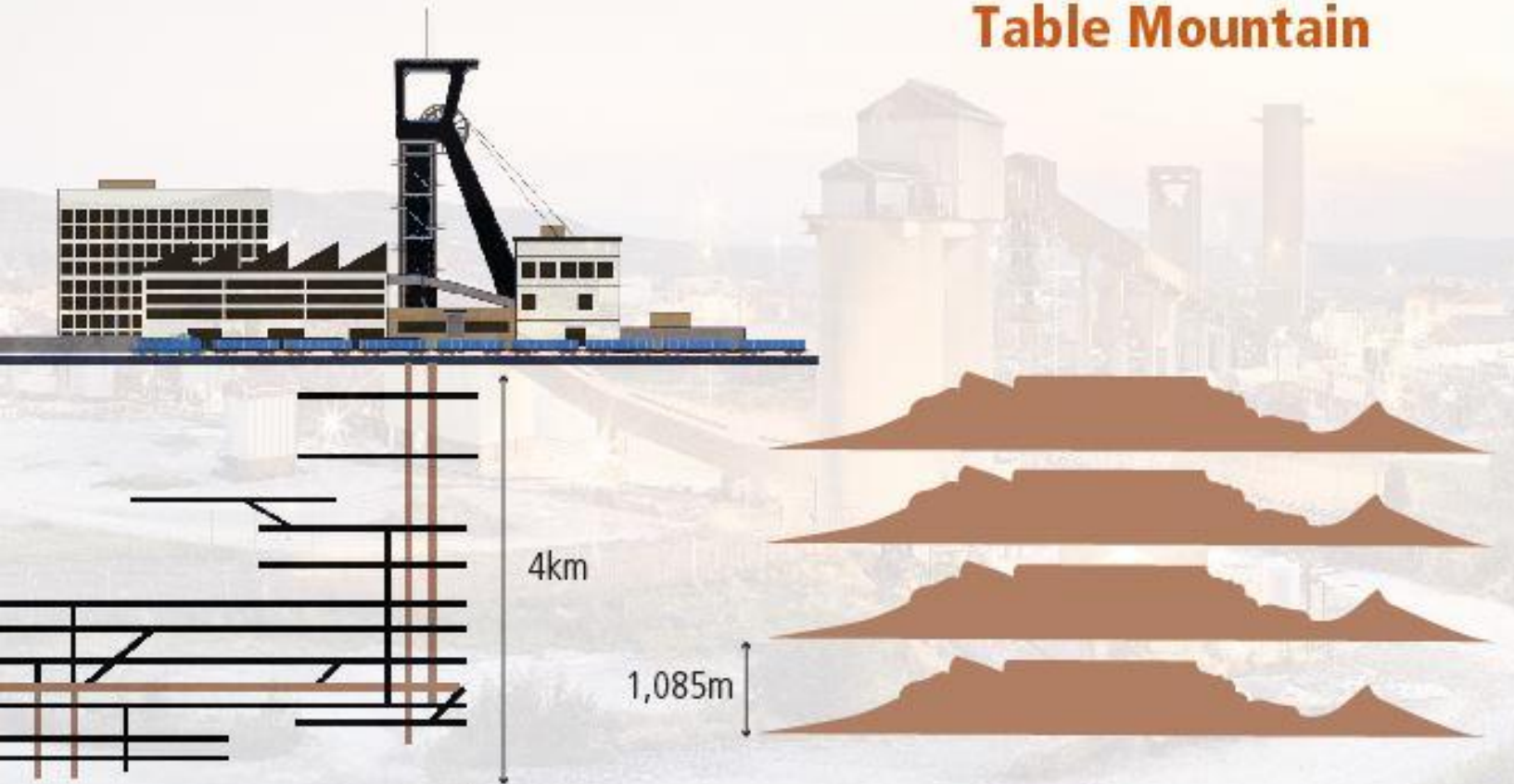
depth of 3,000 metres.



DID YOU KNOW?

The deepest mine in the world is AngloGold Ashanti's Mponeng Gold Mine near Carletonville, at 4km below surface, it is almost 4X the height of

Table Mountain



Mponeng is the deepest level shaft in the world, with a depth of 3 891 metres below datum and 2 062 metres below sea level.

The mine, which began producing in 1986, is near the town of Carletonville, some 90km south-west of Johannesburg.





हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे लोग

ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश की दंतकथाएं सुनी थीं कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। इसी बात से प्रभावित होकर वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकालकर दिखाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की लालच में ग्रामीण लेफ्टिनेंट वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए।

गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को पानी से धुला तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। उस समय वॉरेन ने करीब 56 किलो सोना निकलवाया। 1804 से 1860 तक काफी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस शोध के चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिसके कारण वहां खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया।



1871 में कोलार में फिर शुरू हुई रिसर्च

न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली 1804 में 'एशियाटिक जर्नल' में छपी एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर काफी उत्साहित हुए। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसको शुरू करूं? लेवेली ने बेंगलुरु में रहने का फैसला लिया। लेवेली ने 1871 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर तक का सफर किया। सफर के दौरान लेवेली ने खनन की जगहों की पहचान की और सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे।

लेवेली ने दो साल खोज को पूरा करने के बाद 1873 में मैसूर के महाराज की सरकार से कोलार में खनन करने का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1875 में लेवेली को खनन करने का लाइसेंस मिला, लेकिन माइकल लेवेली के पास उतना पैसा नहीं था तो उसने इंवेस्टर ढूंढे और खनन का काम जॉन टेलर और सन्स के हाथ में आ गया जो कि एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी। ज्यादा समय उसका पैसा जुटाने और लोगों के काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा। आखिरकार KGF से सोना निकालने का काम शुरू हो गया।

जॉन टेलर और सन्स ने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को टेकओवर कर लिया। 'स्टेट ऑफ द आर्ट' माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण लगाया। इनके द्वारा 1890 में लगाया गया उपकरण 1990 तक चला यानी 100 साल तक ऑपरेशनल था। 1902 में KGF भारत का 95 प्रतिशत सोना निकालता था, 1905 में गोल्ड प्रोड्यूस करने में दुनिया में भारत छठे स्थान पर था।





मजदूर गोल्ड माइनिंग के लिए बने हुए शार्प के बीच से जाया करते थे। इसके किनारे लकड़ी की बीम का सपोर्ट रहता था। लेकिन कई बार माइनिंग के दौरान मजदूरों की जान चली जाती थी।

1880 के दशक में माइनिंग ऑपरेशन बेहद कठिन था। पहले चुनिंदा जगहों पर ही लाइट हुआ करती थी, इसलिए कहीं लिफ्ट नहीं होती थी। माइंस में जाने के लिए शार्प हुआ करते थे, जिसमें लकड़ी की बीम से सपोर्ट किया जाता था। इसके बावजूद यहां पर कभी-कभी हादसा हो जाता है। **माना जाता है 120 साल के ऑपरेशन में 6000 लोगों की मौत हो गई।**

कोलार गोल्ड फील्ड्स में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कोलार से 130 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। ये पावर प्लांट एशिया का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था। बिजली मिलने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड का काम दोगुना हो गया। **इस केंद्र का निर्माण कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवनसमुद्र में किया गया। सोने की खदान के चलते बेंगलुरु और मैसूर की बजाय KGF को प्रथमिकता मिलने लगी।**

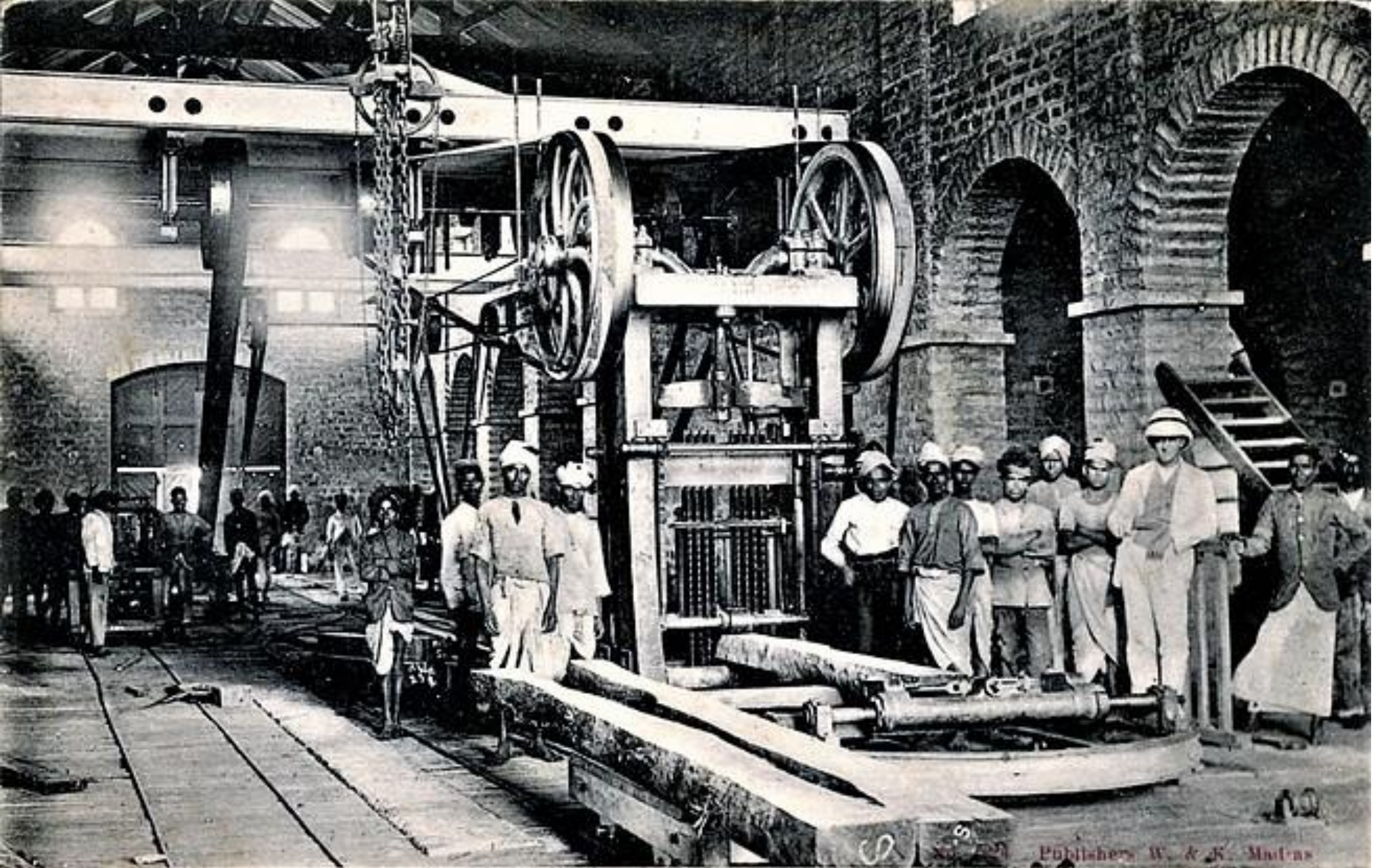


कोलार में सोने की खुदाई शुरू होने के बाद यहां की सूरत बदल गई। माइनिंग के साथ-साथ यहां डेवलपमेंट भी आया। यहां पर ब्रिटिश इंजीनियरों, अधिकारियों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए बंगले, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स और क्लब बनाए गए। जगह काफी ठंडी थी और वहां पर लोग ब्रिटिश अंदाज में घर बनाने लगे। इस निर्माण से **KGF मिनी इंग्लैंड** जैसा लगने लगा।

लेकिन जो लोग माइन में काम करते थे उनके लिए हालात इंग्लैंड जैसे नहीं थे। वो कुली लेन में रहते थे, जहां पर सुविधाएं कम थीं। एक ही शेड में कई परिवार रहते थे और उनका जीवन बेहद कठिन था। ये जगह चूहों के हमले के लिए प्रसिद्ध थी। बताया जाता है यहां रहने वाले श्रमिकों ने एक साल में करीब 50 हजार चूहे मार दिए थे।







Publishers W. & K. Mullins

Hajee Ismail Saits New Sawmill, Kolar Gold Fields

1956 में KGF पर सरकार का कंट्रोल

1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में करीब 30 हजार मजदूर काम करते थे। KGF में जब सोने के भंडार में कमी होने लगी, तब कामगार भी कोलार छोड़कर जाने लगे। हालांकि KGF पर आजादी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन आजादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वहीं ज्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया।

भारत के सोने का 95% उत्पादन करने वाली खदानों को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1979 तक काफी घाटा होने लगा और मजदूरों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स को बंद कर दिया गया।

KGF से कभी इतना सोना निकलता था कि हमारे देश को इंपोर्ट करने की जरूरत न के बराबर थी। **KGF** जब से बंद हुआ तब से भारत पर इंपोर्ट करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जो सुरंगें सोना निकालने के खोदी गई थीं, उनमें अब पानी भर चुका है। खदान एकदम खंडहर हो चुकी है। सरकारी और कोर्ट के आदेश के बावजूद **KGF** का किसी ने फिर से पुनरुत्थान नहीं किया। **माना जाता है कि KGF के पास अभी भी बहुत सोना है, लेकिन उसे निकालने के लिए जो लागत आएगी वो सोने से ज्यादा है।**



2001 में बंद होने के बाद 15 साल तक KGF ठप पड़ा रहा। साल 2016 में मोदी सरकार ने KGF में फिर से काम शुरू करने का संकेत दिया। साल 2016 में KGF के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए टेंडर निकालने के लिए कहा था। फिलहाल KGF को लेकर सारे संकेत ठंडे बस्ते में हैं।





News / LATEST / Policy / Govt to auction at least three gold mines this year

[Feedback](#)

Govt to auction at least three gold mines this year

The government now plans to auction at least three gold mines in 2016 with billions of dollars worth of estimated reserves, including Kolar in Karnataka that was shut 15 years ago on high costs, Mines Secretary Balvinder Kumar said.

ADVERTISEMENT

Make the switch to the future of business accounting. [Try for free](#)



Reuters

Updated Feb 17, 2016, 8:11 PM IST



The government is planning to auction at least three gold mines in 2016, an official said, opening up the sector to private firms for the first time ever in a bid to slash imports of the metal that cost the government \$36 billion last year.

Economically crippling shipments of up to 1,000 tonnes of gold, accounting for about a quarter of country's annual trade deficit, have already prompted the government to hike import duties and launch a scheme aimed at mobilising a pool of over 20,000 tonne of the metal lying idle in homes and temples.

But still the government has failed to curb imports by the world's second-biggest consumer, where gold is regarded as the highest form of gift for gods and humans alike. The absence of local production has scuppered efforts further.

THIS STORY IS FROM NOVEMBER 10, 2022

Karnataka seeks industrial land in Kolar Gold Fields, Centre says not now

Sandeep Moudgal / TNN / Nov 10, 2022, 23:18 IST

SHARE PRINT AA FOLLOW US

New For You



Another dirty NEET secret? Students' ranks jump on 2nd attempt from obscur...



Atishi hospitalised after health deteriorates due to hunger strike



Explained: Why the Hinduja, UK's richest family, is going to jail

The Karnataka government, which is seeking prime industrial land from the union government in Kolar Gold Fields (KGF) has been forced to "wait and watch" as the union mines ministry is yet to take a call on the possibility of alienating the centre's



BENGALURU: The Karnataka government, which is seeking prime industrial land from the union government in Kolar Gold Fields (KGF) has been forced to "wait and watch" as the union mines ministry is yet to take a call on the possibility of alienating the centre's prime land of 3,500 acres towards the state industries department.

Over the last two years, the [Karnataka](#) government has been trying to lobby for the 3,500 acres of land after conducting a survey of not having any precious metal available for alienating them towards industrial area development.

Karnataka okays Centre's proposal to revive gold mining at KGF

The Cabinet has given its approval for the central government's proposal to continue the mining activities in 13 tailing dumps of 1,003.4 acres at the defunct Bharat Gold Mines Limited's (BGML) mine at KGF in Kolar district



DHNS

Last Updated : 21 June 2024, 05:26 IST

Follow Us :



The Cabinet on Thursday allowed the Union government to take up mining activities on tailing dumps attached to Bharat Gold Mines Ltd. The state government has also sought transfer of 2,330 acres of the defunct company to set up an industrial park there in lieu of arrears of Rs 75.24 crore from the company.

The Cabinet has given its approval for the central government's proposal to continue the mining activities in 13 tailing dumps of 1,003.4 acres at the defunct Bharat Gold Mines Limited's (BGML) mine at KGF in Kolar district, under MMDR (Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment) Act's section 17, Law and Parliamentary Affairs Minister H K Patil told reporters.

“The mining of these dumps will provide employment opportunities to many in the region, therefore, we have agreed to allow mining in these dumps by the BGML,” he said.



कर्नाटक

○ कोलर गोल्ड फ़िल्ड्स



The mines, owned by **Bharat Gold Mines Ltd. (BGML)**, are set for revival under the **Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957**. **The move aims to generate employment and boost domestic gold production**. KGF is among the deepest in the world. **Mining at KGF began in 1880 by Jhon Taylor & Sons**. After 121 years of operation, the **mines closed on February 28, 2001**, due to high operational costs and low revenues.

Besides gold extraction, KGF has been utilized for **particle physics experiments**, leading to the discovery of **atmospheric neutrinos**.

Currently, India operates three gold mines: **Hutti and Uti in Karnataka, and Hirabuddini in Jharkhand**. **India produces approximately 1.6 tonnes of gold annually, far below its consumption of 774 tonnes per year**.

अगर कोलार खदान फिर से खुल जाएगी, तो क्या असर पड़ेगा...

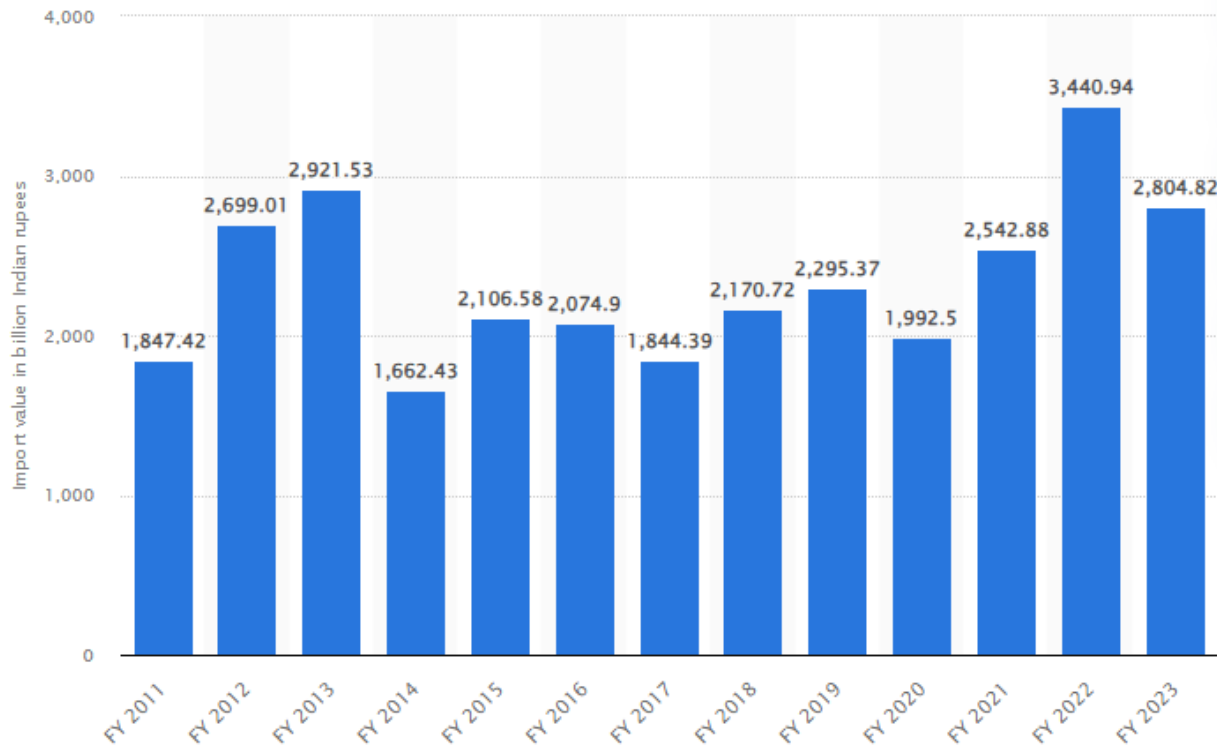
चीन के बाद सोने की खपत में भारत दूसरे नंबर पर है। कोलार में आज भी काफी सोना बचा हुआ है। **KGF का खुलना इसलिए भी अहम होगा कि जिस तरह सोने की मांग बढ़ रही है, उसे वहां से पूरा किया जा सकता है। इससे देश पर पड़ रहा बोझ भी थोड़ा कम होगा।**

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार भारत ने 2021 में 1067.72 टन सोना इंपोर्ट किया। सोने के इंपोर्ट की वजह से भारत की जेब पर बोझ पड़ता है। ऐसे में अगर कोलार खदान फिर से खुल जाए तो कुछ बोझ हल्का हो सकता है।

Chemicals & Resources > Mining, Metals & Minerals

Value of gold imported into India from financial year 2011 to 2023

(in billion Indian rupees)



- ★
- 🔔
- ⚙️
- 🔗
- “ ”
- 🖨️

DOWNL



Sources

- Show s
- Show p
- Use As

Release

Septembe

Region

India

Survey t

FY 2011 to

Supplem

* Provision

India's fin

March. Fo

and end...

Additional Information

© Statista 2024

Show source



NCERT

FOUNDATION BATCH

EMI

OPTION AVAILABLE

OFFER PRICE
4999 Rs

Purchase Time to Pay
→ **2500 Rs**

Next Month to Pay
→ **2500 Rs**

EMI OFFER AVAILABLE FOR 24HR ONLY/-

- 1.SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
- 2.SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
- 4.SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
- 5.ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:



T&C APPLY



BY ANKIT AVASTHI SIR

LIMITED SEATS

और **EMI INFORMATION** के लिए

7878158882 अभी कॉल करें

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM



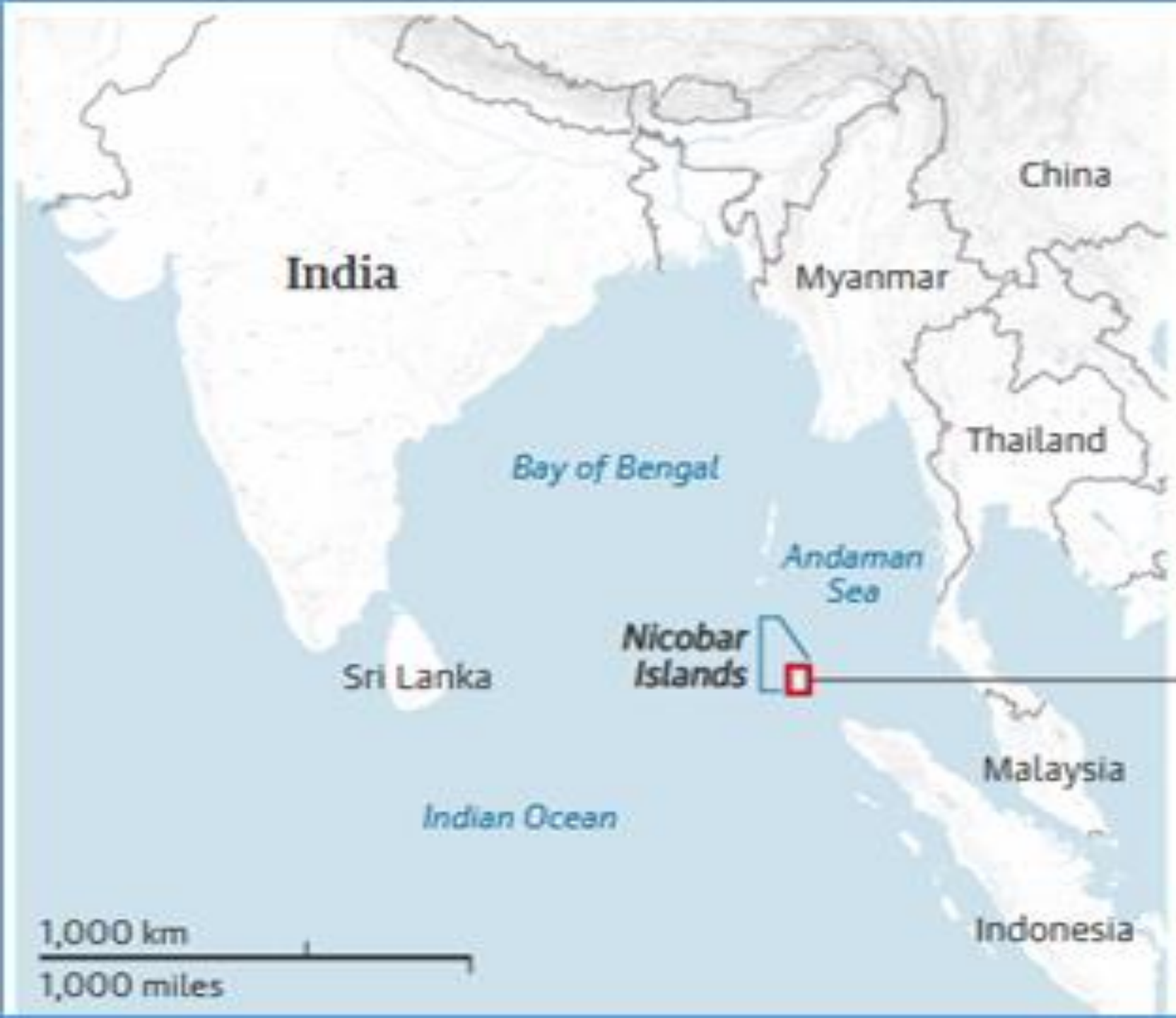








1000 0 (km) 2000



About



Area: 8,249 km²

Population: 4.34 lakhs (2019)

Capital and largest city: Port Blair

Demonym(s): Andamanese, Nicobarese

Districts: 3

Elevation: 568 m (1,864 ft)

Formation: 1 November 1956



Great Nicobar is the southernmost and largest of the Nicobar Islands of India, north of Sumatra. It is part of India, in the Nicobar district within the union territory of the Andaman and Nicobar Islands.

[Wikipedia](#)



बड़ा निकोबार, जिसे दक्षिण निकोबारी भाषा में टोकिओंग लोंग या केवल लोओंग कहा जाता है, भारत के निकोबार दमन द्वीपसमूह का एक द्वीप है। यह निकोबार द्वीपसमूह का दक्षिणतम द्वीप है और इसका सबसे दक्षिणी बिन्दु "इंदिरा प्वाइंट" कहलाता है और वह भारत का सबसे दक्षिणी बिन्दु भी है। [विकिपीडिया](#)

हिन्दी में खोजें : [ग्रेट निकोबार द्वीप](#)

Area: 921 km²

Island groups: [Andaman and Nicobar Islands](#), [Nicobar Islands](#)

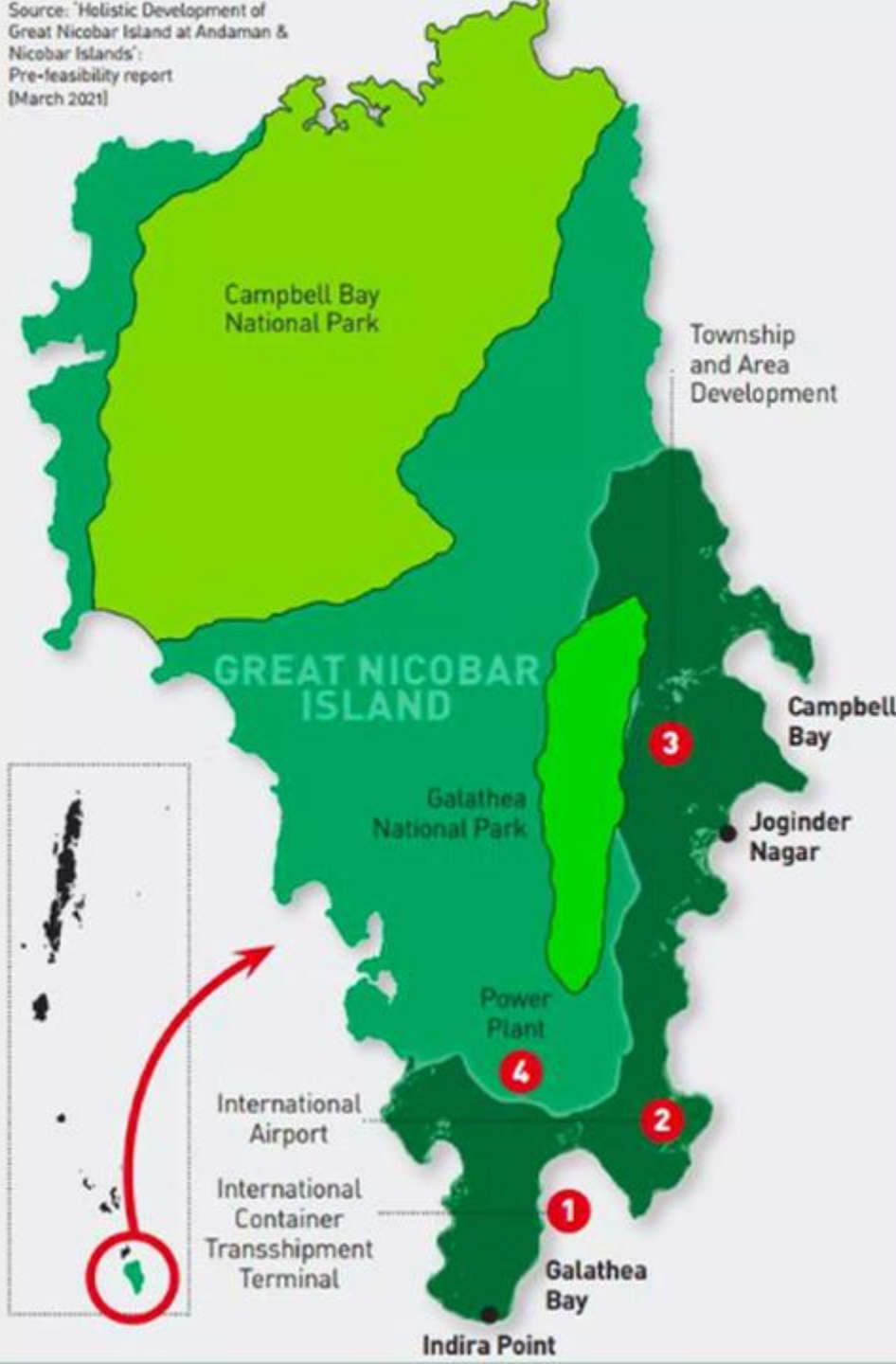
Population: 8,067 (2014)

Coordinates: 7°02'N 93°48'E / 7.03°N 93.8°E

Location: [Bay of Bengal](#)

Avg. summer temperature: 32.0 °C (89.6 °F)

Source: 'Holistic Development of Great Nicobar Island at Andaman & Nicobar Islands': Pre-feasibility report (March 2021)



- 149.60 sq km** Township
- 8.45 sq km** Airport
- 7.66 sq km** Container transshipment terminal
- 0.4 sq km** Power plant



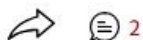
GREAT NICOBAR PROJECT

Congress demands withdrawal of clearances to Great Nicobar infrastructure project

Though details of a project being appraised for environmental clearance are usually made available on a public portal maintained by the Environment Ministry, details on the Great Nicobar Project have not been put up

Updated - June 17, 2024 09:57 pm IST Published - June 17, 2024 08:42 pm IST - NEW DELHI

THE HINDU BUREAU



2

READ LATER PRINT





Great Nicobar Island

- Great Nicobar is the **southernmost and largest of the Nicobar Islands**, a sparsely inhabited 910-sq-km patch of mainly tropical rainforest in southeastern Bay of Bengal.
 - **Indira Point** on the island, India's southernmost point, is located 90 nautical miles (<170 km) from Sabang at the northern tip of **Sumatra, the largest island of the Indonesian archipelago.**
- **The Andaman and Nicobar Islands consist of 836 islands**, divided into two groups known as the Andaman Islands located in the north and the Nicobar Islands situated in the south, separated by the 10° Channel which is 150 kilometres wide.
- Great Nicobar has two national parks, a biosphere reserve, **small populations of the Shompen, Onge, Andamanese and Nicobarese tribal peoples**, and a few thousand non-tribal settlers.



Andaman & Nicobar Islands

Malaysia

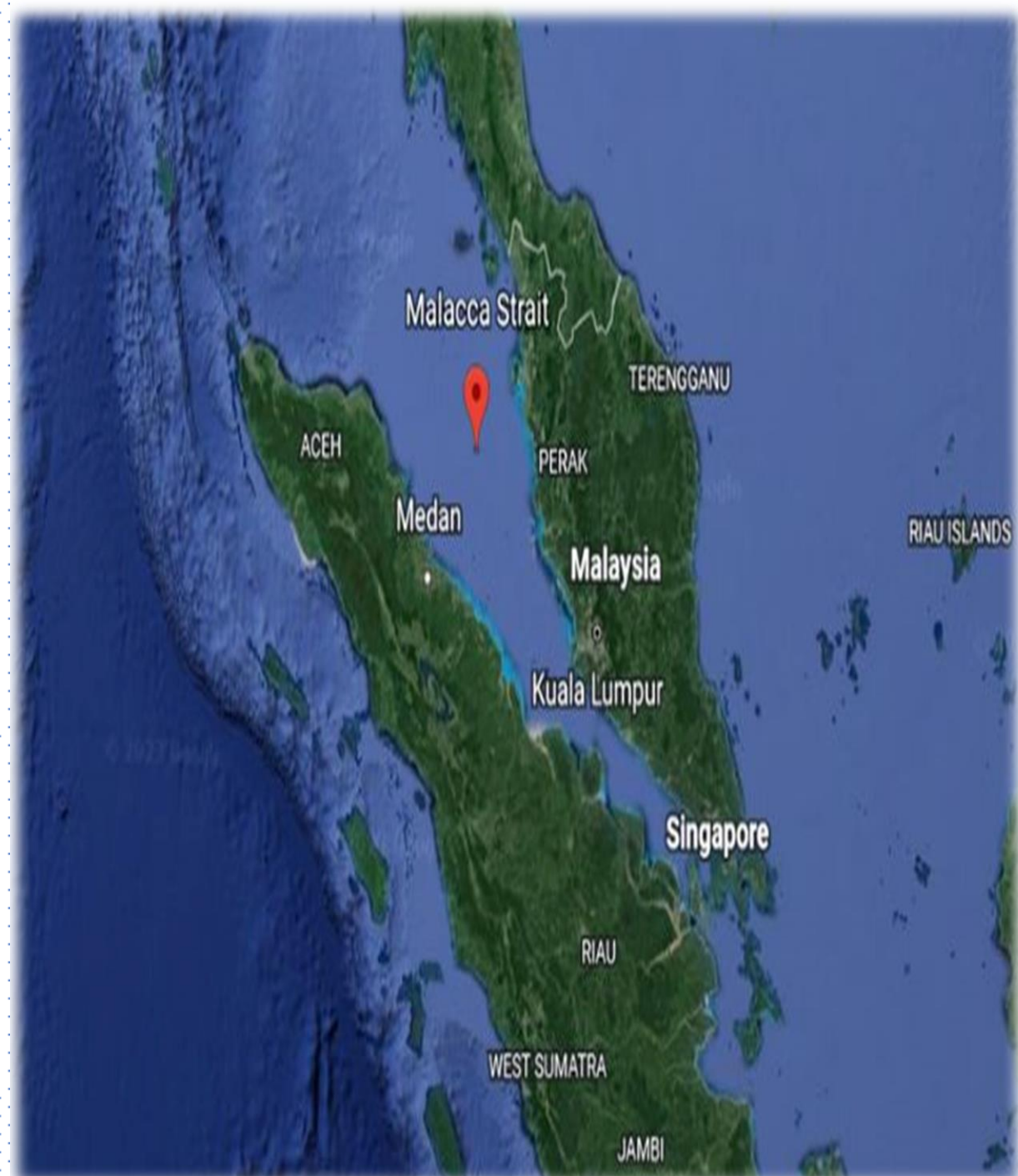
Singapore

मलक्का जलडमरूमध्य क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों

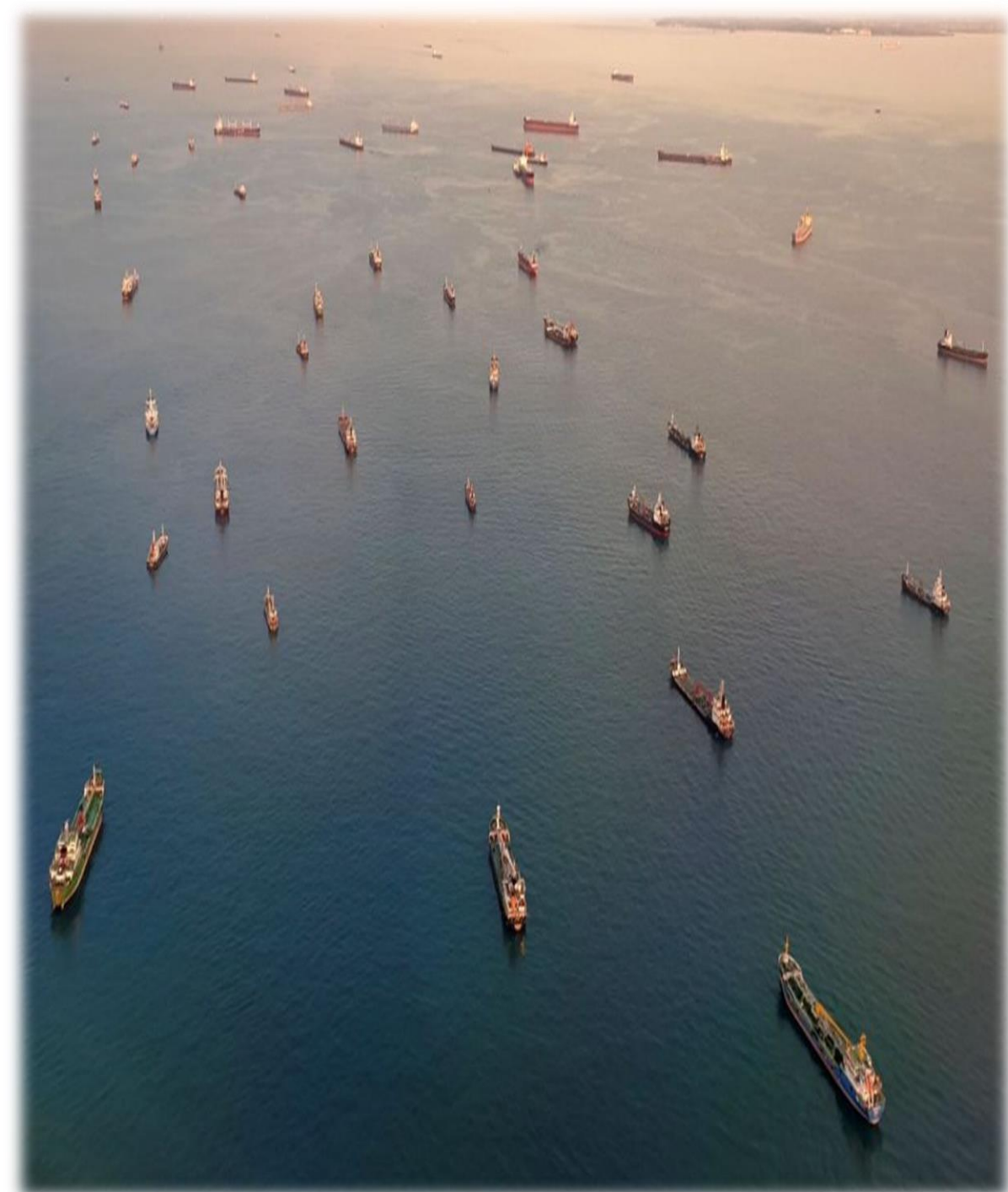
मलक्का जलडमरूमध्य - मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक पतला सा समुद्री मार्ग है। इसकी **लंबाई 805 किमी या 500 मील है जो इंडोनेशिया-मलेशिया मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है।** यह जलडमरूमध्य अधिक गहरा नहीं है। इसकी औसत **गहराई 25 मीटर** है। ऐसे में भारी भरकम समुद्री जहाजों को इस जलडमरूमध्य को पार करने के लिए और अधिक पतले कॉरिडोर से होकर गुजरने की जरूरत होती है।

यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र को भारत और मध्य पूर्व से जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। **दुनिया का लगभग एक चौथाई व्यापारिक माल मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इस जलडमरूमध्य पर कब्जे को लेकर शुरू से ही युद्ध होते रहे हैं। यहां से करीब 75-90 हजार जहाज हर साल गुजरते हैं। सोलहवीं सदी में पुर्तगालियों ने इस महत्वपूर्ण मार्ग पर कब्जा करने का अभियान चलाया था। सत्रहवीं सदी में डचों ने इसे पुर्तगालियों से छीन लिया और ८० सालों के बाद इसे ब्रिटिशों को एक संधि के तहत दे दिया।**

व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मार्ग
: यह एक उथला और संकरा समुद्री
मार्ग है, जो करीब 800 किमी लंबा है।
यह सिंगापुर, मलेशिया और
इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। साथ ही
यह दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले
व्यापारिक समुद्री मार्गों में से भी एक है
यह हिंद महासागर में स्थित अंडमान
सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता
है।



चीन के लिए महत्वपूर्ण : चीनी अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर रहता है। **करीब 80 फीसद तेल की आपूर्त इसी मलक्का जलसंधि मार्ग से होती है।** इस मार्ग पर भारत का नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो चीन के जहाजों को लंबा रास्ता चुनना होगा और इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संभालना इस वक्त उसके लिए संभव नहीं होगा। सामरिक विशेषज्ञों के मुताबिक, **अगर रास्ता बंद होता है तो यह चीन के बहुत बड़ा झटका होगा।**

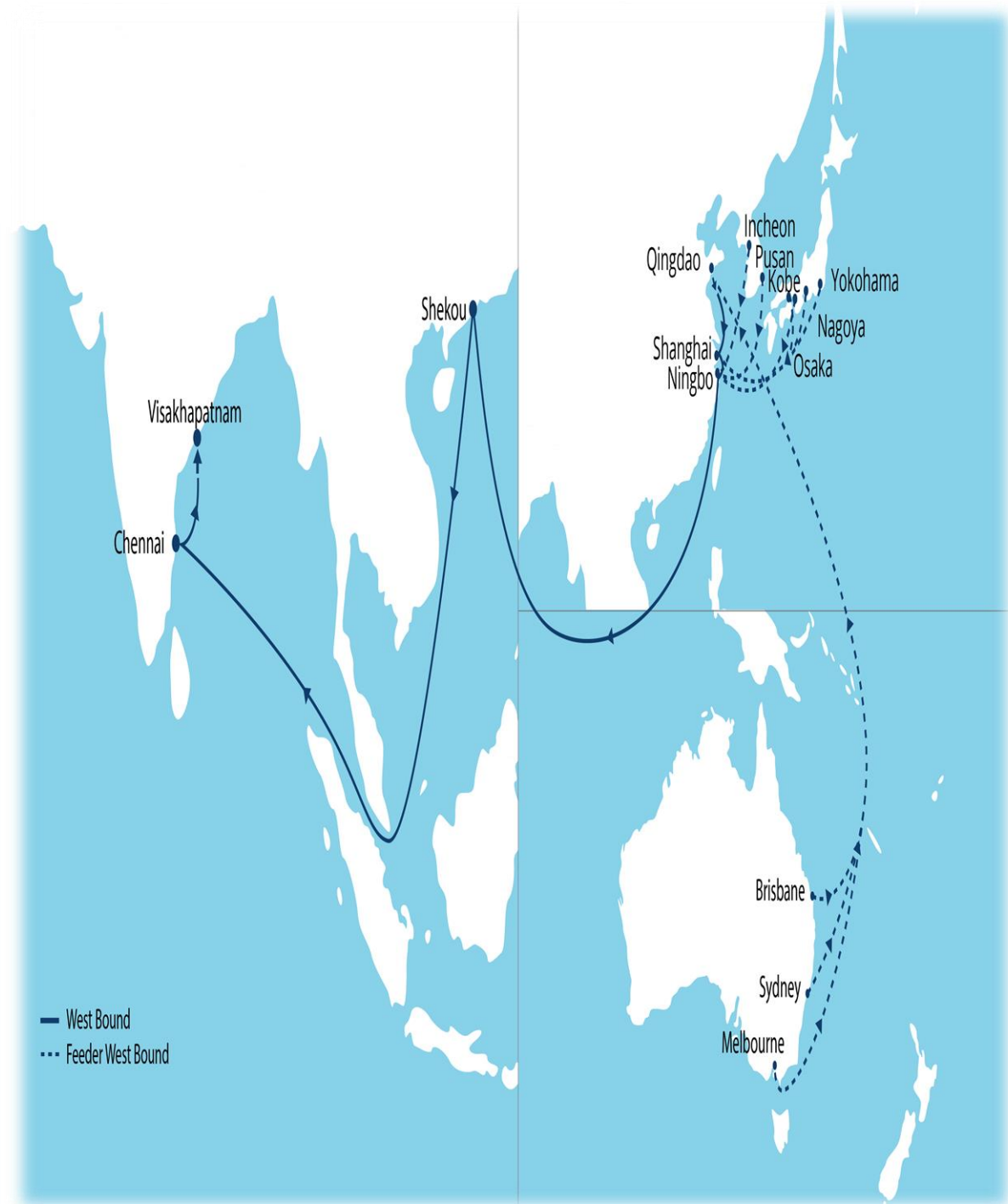


Major crude oil trade flows in the South China Sea (2016)

total 15.0 million barrels per day



चीन को बड़ी आर्थिक चपत : सप्ताह भर बंद रहने से ही चीन की समुद्री यातायात की लागत 6.40 करोड़ डॉलर तक बढ़ जाएगी। एक अन्य अनुमान के मुताबिक, यदि यह मार्ग बंद होता है तो चीन को अपेक्षाकृत लंबा समुद्री मार्ग चुनना होगा। इससे चीन को एक साल में 84 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त चपत लग सकती है।



सालों से नया रास्ता खोजने की कोशिश : चीन सालों से नया रास्ता तलाश रहा है, जिससे समुद्री यातायात में उसे सुविधा हो। कुछ समय पूर्व ही वह थाइलैंड से एक नया समुद्री व्यापारिक मार्ग बनाने की कोशिश में है। अपने महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ वह थाइलैंड को जोड़कर क्रा इस्थमस नहर बनाना चाहता है, जिसे थाई कैनाल के नाम से भी जाना जाता है।

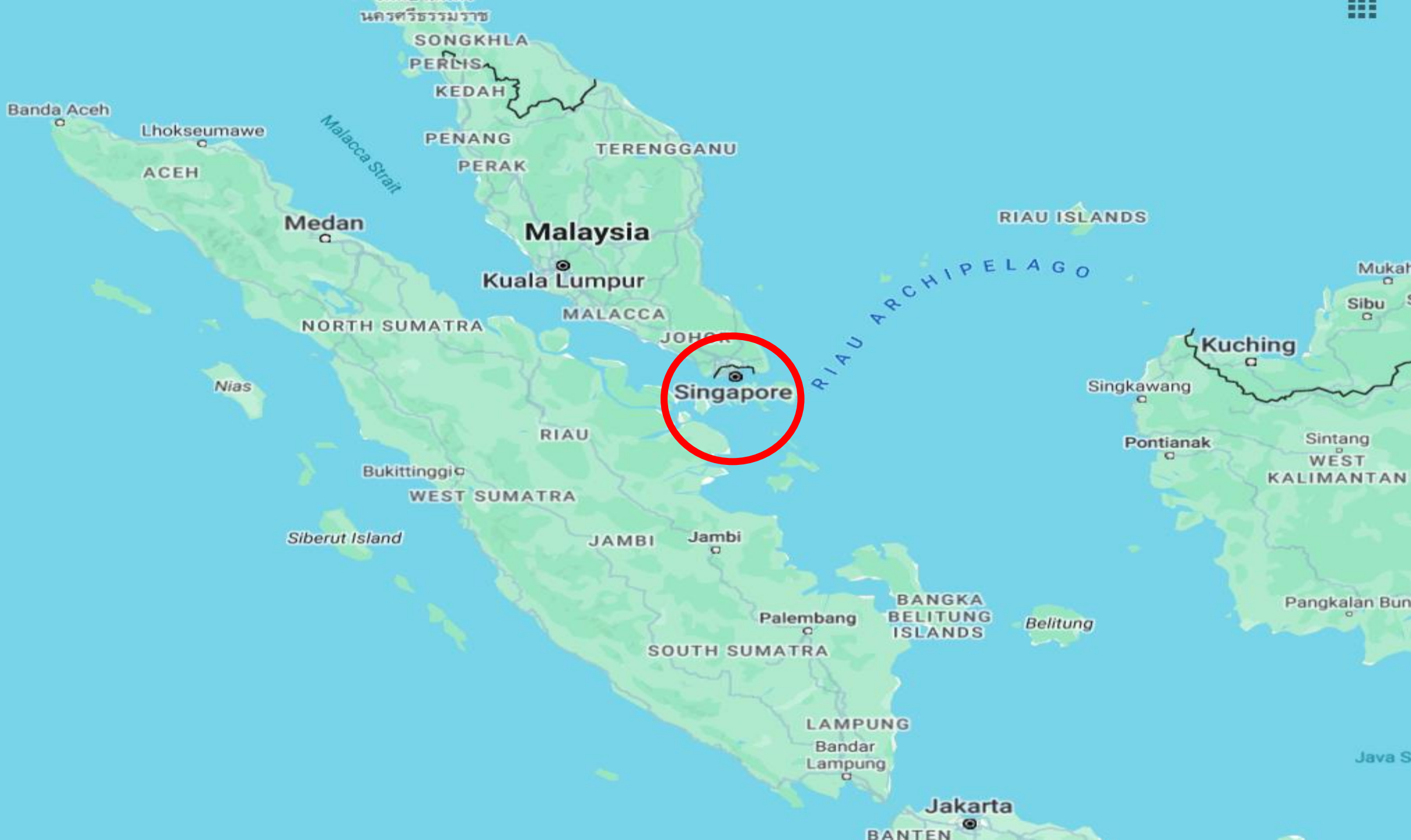
इस पर करीब 50 अरब डॉलर के खर्च आने की बात कही जा रही है। हालांकि कभी चीन के मित्र रहे थाईलैंड ने इस परियोजना को मना कर दिया है।

PROPOSED ROUTE FOR THAILAND CANAL



KRA CANAL

New canal route would shorten transit between the Indian and Pacific oceans by **1,200 kilometers.**



นครศรีธรรมราช

SONGKHLA

PERLIS

KEDAH

PENANG

TERENGGANU

PERAK

RIAU ISLANDS

Medan

Malaysia

Kuala Lumpur

MALACCA

NORTH SUMATRA

JOHOR

Singapore

RIAU ARCHIPELAGO

Kuching

Singawang

Pontianak

Sintang

WEST KALIMANTAN

Nias

Bukittinggi

WEST SUMATRA

RIAU

JAMBI

Jambi

Siberut Island

Palembang

BANGKA BELITUNG ISLANDS

Belitung

SOUTH SUMATRA

Pangkalan Bun

LAMPUNG

Bandar Lampung

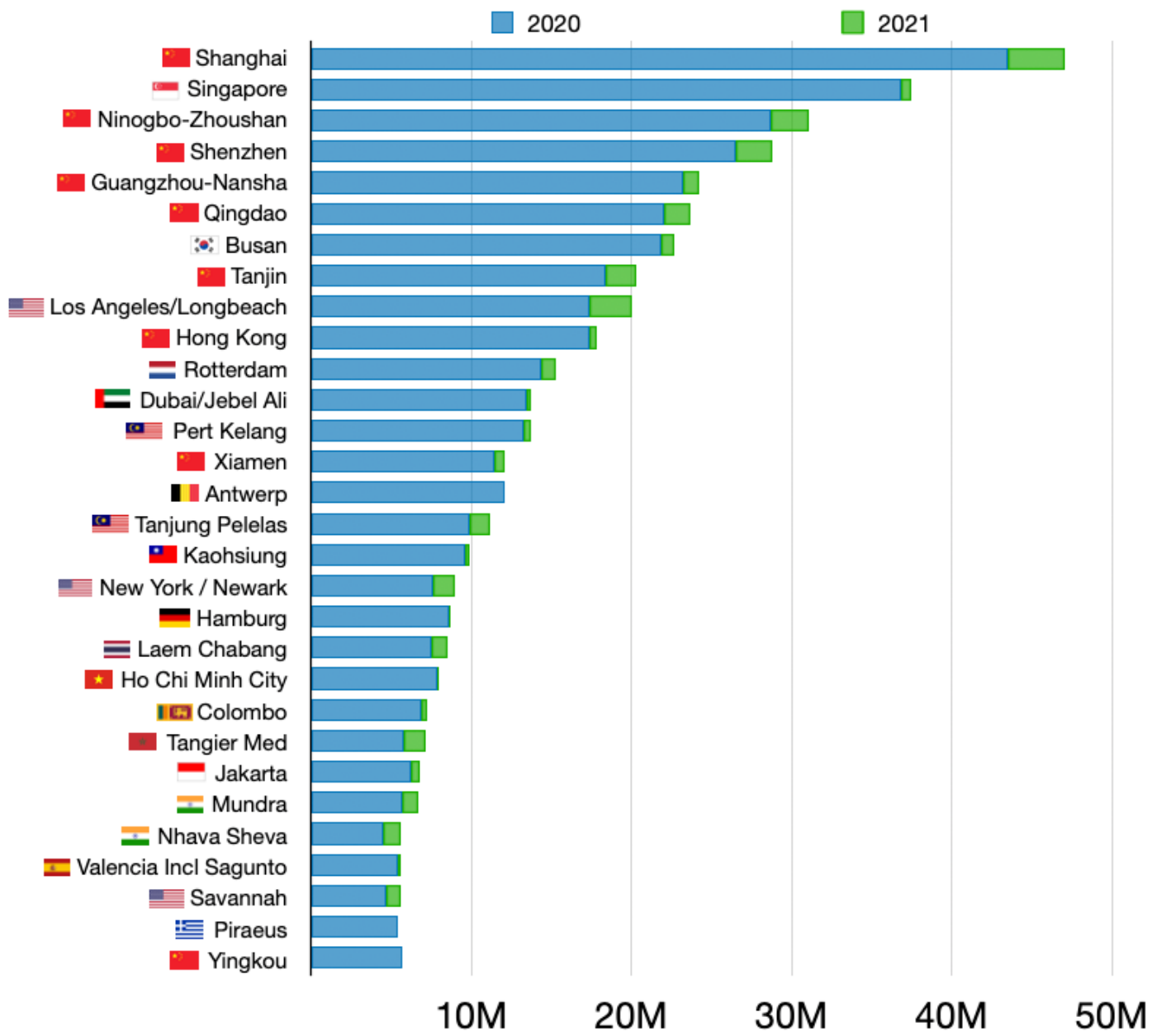
Jakarta

BANTEN

Java S

#	Port	Country / Territory	Region	Location	2023 ^[3]	2022 ^[4]	2021 ^[5]	2020 ^{[5][6]}	2019 ^[7]	2018 ^{[7][8][9]}	2017 ^[10]	2016 ^[11]	2015 ^[12]	2014 ^[12]	2013 ^[13]
1	Shanghai	 China	East Asia	Yangtze Delta	49,000	47,303	47,030	43,500	43,303	42,010	40,233	37,133	36,537 ^[23]	35,268	33,617
2	Singapore	 Singapore	Southeast Asia	Singapore Strait	39,010	37,289	37,470	36,600	37,195	36,599	33,666	30,904 ^[24]	30,922 ^[24]	33,869	32,240
3	Ningbo-Zhoushan	 China	East Asia	Yangtze Delta	35,300	33,351	31,070	28,720	27,530	26,351	24,607	21,560 ^[25]	20,620 ^[25]	19,450	17,351
4	Shenzhen	 China	East Asia	Pearl River Delta	26,890	30,036	28,768	26,550	25,770	25,740	25,208	23,979 ^[26]	24,204 ^[26]	23,798	23,280
5	Qingdao	 China	East Asia	Yellow Sea	26,390	25,670	23,710	22,000	21,010	19,315	18,262	18,010 ^[27]	17,510	16,624	15,520
6	Busan	 South Korea	East Asia	Korean Strait	22,750	22,078	22,706	21,590	21,992	21,662	20,493	19,850 ^[28]	19,469 ^[28]	18,423	17,690
7	Tianjin	 China	East Asia	Yellow Sea	21,800	21,021	20,269	18,350	17,264	15,972	15,040	14,490 ^[29]	14,090	14,050	13,010
8	Guangzhou	 China	East Asia	Pearl River Delta	20,800	24,857	24,180	23,190	23,236	21,992	20,370	18,858 ^[30]	17,625	16,160	15,309
9	Los Angeles / Long Beach	 United States	North America	West Coast	16,618 ^{[31][32]}	19,044	20,061	17,327	16,969	17,549	17,013	15,632 ^{[33][34]}	15,352	15,161	14,600
10	Hong Kong	 Hong Kong	East Asia	Pearl River Delta	14,300	16,685	17,798	20,070	18,361	19,596	20,770	19,813 ^[35]	20,073 ^[35]	22,374	22,352
11	Rotterdam	 Netherlands	Europe	Rhine delta	13,400	14,455	15,300	14,350	14,810	14,512	13,734	12,385 ^[36]	12,235	12,453	11,621
12	Jebel Ali	 United Arab Emirates	West Asia	Persian Gulf		13,970	13,742	13,488	14,111	14,954	15,368	14,772 ^[37]	15,592	14,750	13,641
13	Antwerp	 Belgium	Europe	Scheldt delta		13,500	12,020	12,031	11,860	11,100	10,451	10,037 ^[38]	9,654	9,136	8,578
14	Port Klang	 Malaysia	Southeast Asia	Malacca Strait		13,220	13,724	13,240	13,580	12,316	11,978	13,170 ^[39]	11,887	10,736	10,350
15	Xiamen	 China	East Asia	Taiwan Strait		12,434	12,045	11,410	11,122	10,702	10,380	9,614 ^[40]	9,183	8,572	8,010
16	Tanjung Pelepas	 Malaysia	Southeast Asia	Malacca Strait		10,512	11,200	9,850	9,100	8,960	8,261	8,281 ^[41]		9,120	8,500 ^[12]
17	New York / New Jersey	 United States	North America	East Coast		9,493	8,985	7,586	7,471	7,179	6,711	6,252 ^[42]	6,372	5,772	5,467
18	Kaohsiung	 Taiwan	East Asia	Taiwan Strait		9,491	9,864	9,622	10,428	10,445	10,271	10,465 ^[43]	10,264	10,593	9,938
19	Laem Chabang	 Thailand	Southeast Asia	Gulf of Thailand		8,741	8,335	7,547	8,106	8,070	7,670	7,227 ^[44]	6,780	6,518	6,032
20	Hamburg	 Germany	Europe	Elbe River		8,261	8,715	8,540	9,274	8,730	8,860	8,910 ^[45]	8,821	9,729	9,302
21	Taicang / Suzhou	 China	East Asia	Yangtze Delta		8,025	7,038	5,212	5,152	5,071	4,514	4,081	3,760		

Container Port Traffic



Twenty Foot Equivalent Units

DUBAI + SINGAPORE



Modi government's Rs 10,000 crore plan to transform Andaman and Nicobar islands

By Rajat Arora, ET Bureau - Last Updated: Sep 26, 2015, 12:31:00 PM IST

FOLLOW US
 SHARE
 FONT SIZE
 SAVE
 PRINT
 COMMENT ⁷³

Synopsis
 Modi govt has readied a blueprint of the plan that also entails protection of the original Jarawa inhabitants while boosting the tourism potential.



India has drawn up an ambitious, Rs 10,000 crore plan to transform the Andaman and Nicobar Islands into the country's first maritime hub, taking advantage of its strategic location and making it the base for infrastructure that will include an expanded dry dock and ship repair industry in the capital Port Blair.

The Narendra Modi government has readied a blueprint of the plan that also entails protection of the original Jarawa inhabitants while boosting the tourism potential of locations such as limestone caves and mud volcanoes.

"Plans for the projects that are to be undertaken over the next two years have already been formulated," shipping Minister Nitin Gadkari told ET. "Action is being initiated."

Speaker

Tejasvi Suresh Bala
 CEO, Swirl Lifestyle

Videos

Projects that entail an investment of Rs 2,000 crore have been sanctioned and work on the rest of the programme will start soon.

The shipping ministry has prepared a 15-year perspective plan for the development of shipping and port infrastructure on the islands, which are home to India's eastern and southern tips, putting them within close distance of an international shipping route.

Apart from ship repairs, the plan includes the development of port infrastructure, the acquisition of vessels to run mainland-island services, the purchase of tugs for safe berthing and sprucing up docking capacity.

"Andaman is a very sensitive zone. So, all these projects will have to be undertaken after assessing the impact on environment," said a senior government official. "Tribal areas and tourist areas would be bifurcated. We are creating sea routes so that these areas are not disturbed."

Andaman and Nicobar will play important role in govt's self-reliant India programme: PM Modi

PTI / Updated: Aug 9, 2020, 18:56 IST

SHARE PRINT AA FOLLOW US

New For You



750 of 1,563 students skipped NEET-UG retest: NTA



'As I faced abuse each day ...': Rahul Gandhi's note for Wayanad



Right Melodi: Italian PM married strategy and selfie diplomacy

A day before inaugurating a submarine optical fibre cable facility for Andaman & Nicobar Islands, PM Modi said that it will ensure that the region faced no problem in getting virtually connected to the outside world as he highlighted various ...[Read More](#)



NEW DELHI: A day before inaugurating a submarine optical fibre cable facility for [Andaman and Nicobar Islands](#), Prime Minister [Narendra Modi](#) asserted on Sunday that it will ensure that the region faced no problem in getting virtually connected to the outside world as he highlighted his government's various development initiatives for the union territory.

Speaking at an interaction with [BJP](#) workers from the distant region, he noted that the islands are "strategically" located and can become a key centre for global sea trade, stressing that the central government is working to make it a blue economy hub and also an important place for maritime startups.

THE ICONIC ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS TO BECOME DIGITALLY INDEPENDENT ON 10TH AUGUST 2020



PM Shri Narendra Modi will dedicate to the nation his dream project '**The Submarine Optical Fibre Cable**', connecting Chennai and Port Blair.

The 2,300 km undersea high-speed broadband cables will

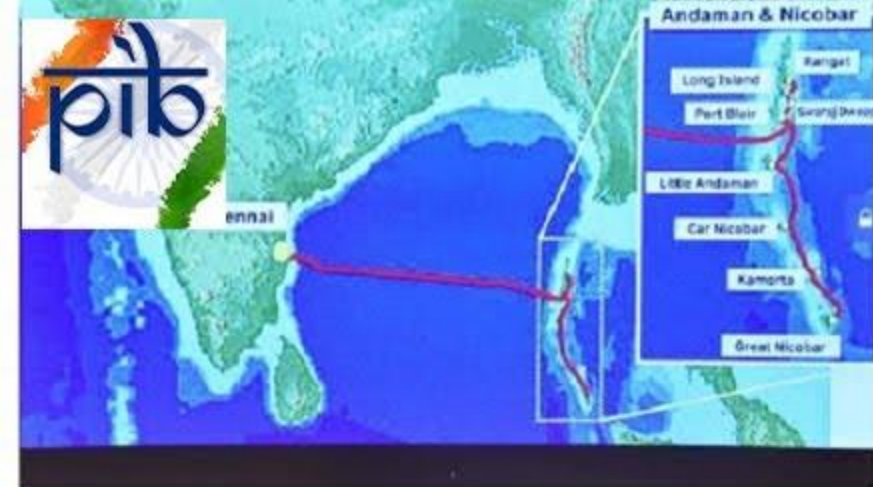
- Enable faster telecom and broadband services
- Boost e-governance, tourism and employment generation
- Strengthen India's strategic maritime security



History Nugget

Netaji Subhash Chandra Bose had 'freed' Andaman & Nicobar Islands and hoisted Tricolour at Port Blair in December 1943.





PM Narendra Modi launches submarine cable connectivity between

Chennai and Andaman & Nicobar Islands



Chennai

Andaman & Nicobar

Rangat

Long Island

Port Blair

Havelock

Little Andaman

Car Nicobar

Kamorta

Great Nicobar

After 'Digital Andaman', PM plans to make it hub of 'blue economy'

Prime Minister Narendra Modi spoke to the Andamanese people via the digital mode amid the Covid-19 pandemic on Sunday.

Reported by: IANS

New Delhi

Published on: August 09, 2020 20:33 IST



Follow us on [Google News](#)



Prime Minister of India

Image Source : ANI

After 'Digital Andaman', PM plans to make it hub of 'blue economy'

Prime Minister Narendra Modi spoke to the Andamanese people via the digital mode amid the Covid-19 pandemic on Sunday. The Prime Minister interacted with the BJP workers of Andaman and Nicobar Islands through a video conference on Sunday, a day before dedicating the Submarine optical fiber cable project, connecting Chennai and Port Blair.

Advertisement

Indiatvnews



Read More

Delhi gets respite with rainfall after weeks of...

TOP NEWS



NEET-UG paper leak case: 750 out of 1,563 candidates awarded grace marks skip re-exam, 813 appear



Sonakshi Sinha, Zaheer Iqbal's wedding pictures are out, couple registers their marriage



Smriti Mandhana and Deepti Sharma lead India women to clean sweep South Africa in ODI series

Advertisement



THE BLUE ECONOMY.



is inclusive and improves the lives of all



harnesses renewable energy



uses smart shipping to lessen the impacts on the environment



is based on sustainable fisheries



takes action against illegal fishing



creates jobs, reduces poverty and ends hunger

conserves marine life and oceans



protects coastal communities from the impacts of climate change



tackles marine litter and oceans pollution

NITI AAYOG

SELECTION

OF

TECHNICAL CONSULTANT

REQUEST FOR PROPOSALS

FOR

PREPARATION OF MASTER PLAN FOR HOLISTIC
DEVELOPMENT OF GREAT NICOBAR ISLAND IN
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS


201 pages

F.No.M-13040/32(2)/2020-IDA
Government of India
NITI Aayog
Natural Resources & Environment Vertical
Sansad Marg, New Delhi -110001

Request for Proposal (RfP)

7th September, 2020

Notice Inviting Request for Proposal (RfP) for "Preparation of Master Plan for Holistic Development of Great Nicobar Island in Andaman & Nicobar Islands".

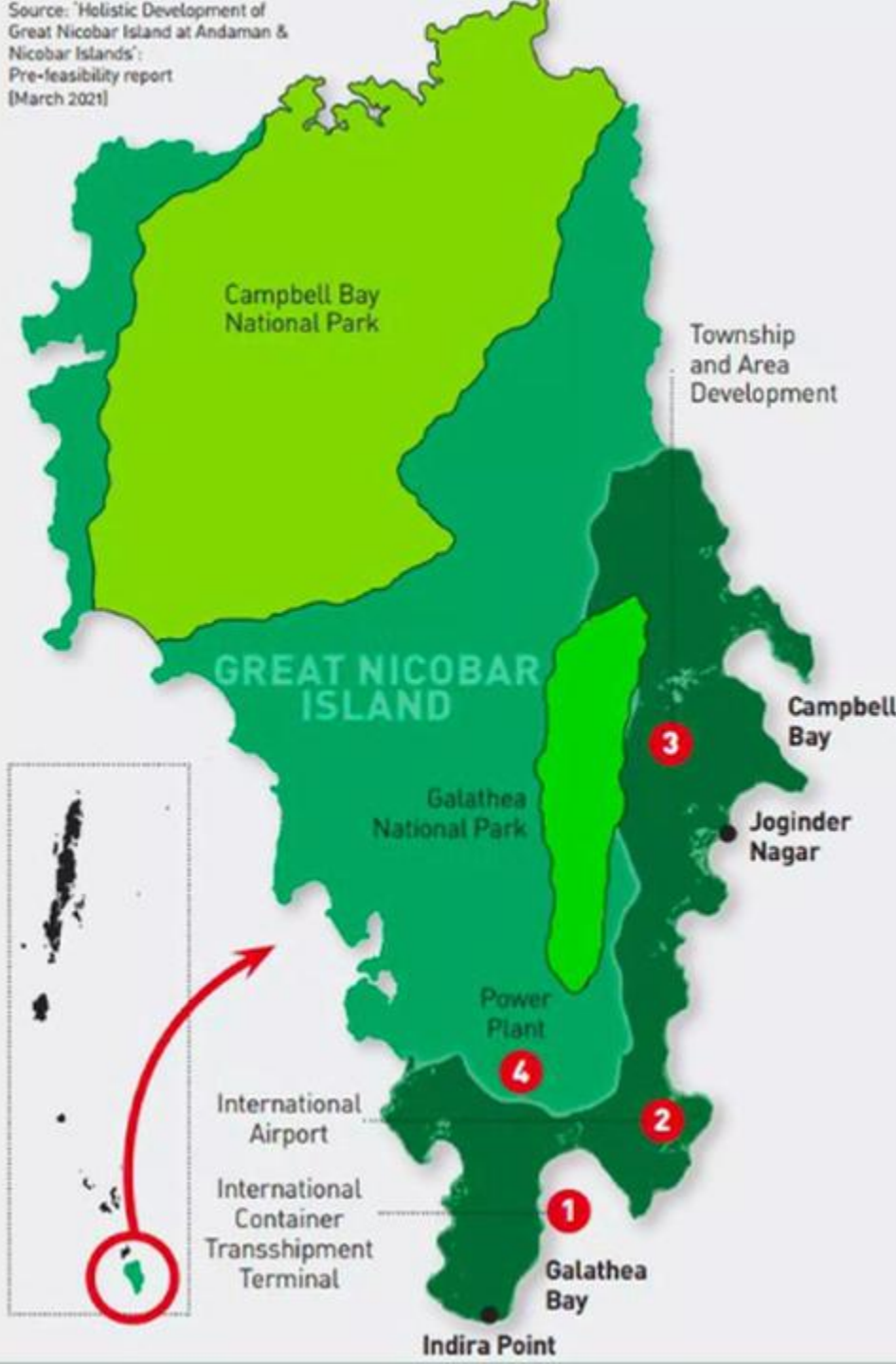
The National Institution for Transforming India (NITI) Aayog, Government of India, intends to engage Technical Consultant to facilitate holistic development of Great Nicobar Island in Andaman & Nicobar Islands details of which have been provided in the RfP document.

NITI Aayog invites on-line RfP for National Competitive Bidding (NCB) for Great Nicobar Island from national firms/ organisations/ institutions, which have requisite experience in this field as detailed in the RfP. The detail tender notice and RfP can be downloaded from Central Public Procurement Portal at <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> and from the website of NITI Aayog at <https://niti.gov.in/tenders>. The salient features of the study, eligibility criteria and instructions on how to bid and other details are available in the RfP document uploaded on the websites <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> and <http://NITI.gov.in>. No manual bids will be accepted under any circumstances.

Interested applicants are requested to submit their response to the 'RfP' on Central Public Procurement Portal as prescribed and titled as **RfP for Preparation of Master Plan for Holistic Development of Great Nicobar Island in Andaman & Nicobar Islands** on or before, 6th October, 2020 1500 hrs.

The submission must be addressed to:
Specialist,
NRE Vertical - Island Development
(Saloni Goel)
Room No: 280,
NITI Aayog, Sansad Marg
New Delhi, 110001
Tel: +9111-23096 635
Email: saloni.goel@gov.in

Source: 'Holistic Development of Great Nicobar Island at Andaman & Nicobar Islands': Pre-feasibility report (March 2021)



- 149.60 sq km** Township
- 8.45 sq km** Airport
- 7.66 sq km** Container transshipment terminal
- 0.4 sq km** Power plant



GREAT NICOBAR PROJECT

Great Nicobar - The Jewel of Andaman and Nicobar Islands!



**INR 72,000 Crore
Developmental Project Planned**

**First Phase to Cost Around INR
19,000 Crores and is envisioned
to be completed by 2028**

**Tender for the Construction of
First Phase Likely to be Called in
Early 2024, Post Cabinet Nod**

Great Nicobar Development plan

- **Firstly**, The overall Great Nicobar Development plan envisages the use of about 244 sq. km. region for development purposes.
- **Secondly**, Phase 1 of the plan will cover:
 - **22 sq. km. airport complex,**
 - **Transshipment port (TSP) at South Bay**
 - **Parallel-to-the-coast mass rapid transport system and**
 - **Free trade zone and warehousing complex on the southwestern coast.**
- **Thirdly**, Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO) will be the nodal agency for the implementation of the Great Nicobar Development plan.

A Boon or A Bane?

The Great Nicobar Island is the southernmost and the largest of Nicobar Island archipelago in Bay of Bengal

Area
921
sq. Kms.

Coastline
202 Km



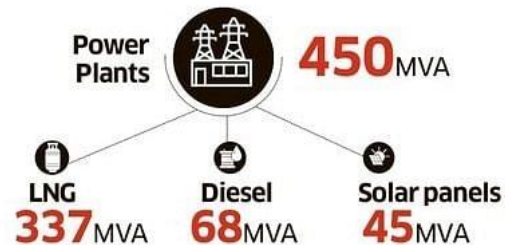
Project site

Home to hunter-gatherer **Shompen Tribe**

Great Nicobar Biosphere Reserve comprises **85%** of the areas of the island

THE PLAN

- An **Int'l Container Transshipment Port** with cargo handling capacity of 14.2 million TEUs, A Free Trade Warehousing Zone
- A parallel-to-the-coast **Mass Rapid Transit System**
- A **Greenfield Int'l Airport** with peak hour capacity for 4000 passengers
- A **Township** to accommodate **6.5 lakh** people by 2050 over an area of **166 sq km**



Estimated Cost **₹ 75,000 cr** | Jobs to be generated **128,000+**

AND THE PERILS

- **Over 8.5 lakh trees** to be felled over an area of **130 sq kms**
- Destruction of tropical rainforests in Galathea National Park, home to **648 species of flora** and **330 species of fauna**, including Nicobar's **wild pig**, **tree shrew**, the Great Nicobar crested serpent eagle, Nicobar paradise flycatcher and the **Nicobar megapode**.
- **Threat to the Shompen tribe:** Proposed project areas have been important foraging grounds for the hunter-gatherer nomadic community.

- Threat to nesting sites of iconic species like **Giant leatherback turtle** and the **Nicobar megapode**.
- **Threat to coral and marine ecosystem:** ZSI reported presence of 117 species of scleractinian corals in Galathea. But the Environment Impact Assessment of the project states that there is no coral located in the Galathea Bay region.
- Threat to **Dugongs** due to loss of seagrass meadows, rising anthropogenic activities.



- **Threat to biodiversity:**
 - Construction in the region threaten the biodiversity of the region
 - The beaches at the mouth of the river Galathea in South Bay are among the most prominent nesting sites of Giant leatherback turtles.
 - Similarly, 90% of the Nicobar megapode's nesting sites are within a distance of 30 m from the shore.
- **Against the spirit of environmental legislations:**
 - Standing Committee of the **National Board for Wildlife (NBWL) denotified the entire Galathea Bay Wildlife Sanctuary** for building port and other related infrastructure.
 - Wildlife Protection Act 1972 – the parent legislation from which NBWL draws its powers – **doesn't permit the diversion of protected areas**, like national parks and sanctuaries, **unless the diversion will benefit the area's wildlife.**
 - Hence the plan violates the purpose of such legislations
- **Not considering the water resource availability**
 - The project is also **unrealistic given the islands' prevailing water scarcity.**
 - The islands depend on rain for their freshwater needs. The longest river flowing through Great Nicobar, Galathea, isn't voluminous enough.
 - **There may not be enough freshwater to sustain a large-scale developmental project** over the long run
- **Affects tribal rights:**
 - The island has two indigenous groups – the Nicobarese and the Shompen, a forest-dwelling community.
 - The proposed project areas are important grounds for Shompen.
 - Initiation of work would **make large forest areas inaccessible and useless for the Shompen.**

GIANT LEATHERBACK TURTLE





Leatherback turtles are named for their shell, which is leather-like rather than hard, like other turtles.

They are the largest sea turtle species and also one of the most migratory, crossing both the Atlantic and Pacific Oceans. Pacific leatherbacks migrate from nesting beaches in the Coral Triangle all the way to the California coast to feed on the abundant jellyfish every summer and fall.

Although their distribution is wide, numbers of leatherback turtles have seriously declined during the last century as a result of intense egg collection and fisheries bycatch. Globally, leatherback status according to IUCN is listed as Vulnerable, but many subpopulations (such as in the Pacific and Southwest Atlantic) are Critically Endangered.

PLACES

Mesoamerican Reef, Coastal East Africa, The Galápagos, Coral Triangle



STATUS

Vulnerable



SCIENTIFIC NAME

Dermochelys coriacea



WEIGHT

600-1500 pounds



LENGTH

55-63 inches



HABITATS

Oceans

THE SUNITA NARAIN SHOW



WILDLIFE & BIODIVERSITY

India's turtle researchers oppose development plans for Little Andaman, Great Nicobar islands

The islands have global significance for global Leatherback turtle conservation and are also home to indigenous peoples like the Onge and the Shompen



NEXT NEWS >

By Ashis Senapati

Published: Thursday 10 June 2021



Projects worth Rs 75,000 crore on Great Nicobar island shown green flag

The projects will need the felling of over 800,000 trees and the loss of 12-20 hectares of mangrove forests, leading to a considerable loss to corals and claiming over 298 hectares of the sea bed



Representative Image

BS Web Team | New Delhi

2 min read Last Updated : Sep 15 2022 | 10:59 AM IST



Connect with us 



ETPrime

Airport, container depot, township in 16,610 hectares of pristine Nicobar cleared

By Anubhuti Vishnoi, ET Bureau • Last Updated: Sep 15, 2022, 12:17:00 AM IST

FOLLOW US SHARE FONT SIZE SAVE

Synopsis

The Great Nicobar Island was declared as a biosphere reserve in January 1989 by the Centre and included in the Unesco man and biosphere programme in May 2013. It is considered a global biodiversity hotspot, which explains the strong opposition to the project from several quarters.



Great Nicobar Island is considered perfect as a site as it is equidistant from Colombo, Port Klang and Singapore and is also very close to the East-West international shipping corridor.

The Centre has cleared the decks for the controversial Rs 75,000 crore project to construct a greenfield international port, an international container transshipment terminal, a township and power plants across 16,610 hectares of pristine forests in a Great [Nicobar island](#).

The environment ministry's Expert Appraisal Committee on Infrastructure

projects approved the project on the island that is home to the indigenous

Great Nicobar Island

Geographical location

- Great Nicobar, the southernmost of the Andaman and Nicobar Islands.
- The Andaman and Nicobar Islands are a cluster of about 836 islands inside the eastern Bay of Bengal.
- The two groups of which might be separated by the 150-km extensive Ten Degree Channel.
- The Andaman Islands lie to the north of the channel, and the Nicobar Islands to the south.
- Indira Point on the southern tip of Great Nicobar Island is India's southernmost factor, less than one hundred fifty km from the northernmost island of the Indonesian archipelago.

Ecosystem

- The Great Nicobar Island has tropical wet evergreen forests, mountain levels attaining nearly 650 m above sea level, and coastal plains.
- The Island has two national parks and a biosphere reserve.
- Many endangered species are determined on the Island. The leatherback sea turtle is the island's flagship species.

Tribes

- Great Nicobar is home to the Shompen and Nicobarese tribal peoples.
- The Shompen are hunter-gatherers who depend on forest and marine resources for sustenance.
- The Nicobarese, who lived along the west coast of the island were mostly relocated after the 2004 tsunami.
- An estimated 237 Shompen and 1,094 Nicobarese individuals now live in a 751 sq km tribal reserve, some 84 sq km of which is proposed to be denotified.

Great Nicobar Island project

- In November 2022, the Environment ministry has given environmental clearance for the Centre's bold Rs seventy two,000 crore multi-improvement initiatives in Greater Nicobar Island.
- The task for the holistic development of Great Nicobar Island turned into implemented after a file by means of NITI Aayog.
- A pre-feasibility report flagged the opportunity to leverage the strategic region of the island.
- The Great Nicobar Island (GNI) is a mega undertaking to be carried out at the southern stop of the Andaman and Nicobar islands.
- The mission includes an worldwide container trans-shipment terminal, a greenfield global airport, township development, and a 450 MVA gas and solar based totally power plant over an volume of 16,610 hectares inside the island.
- The port can be controlled by means of the Indian Navy, while the airport may have twin navy-civilian capabilities and will cater to tourism as well.

Concerns

Threat to Island Ecology

- The proposed massive infrastructure development in an ecologically important and fragile region has alarmed many environmentalists.

Impact on Indigenous People

- Critics point out that there will be devastating impact on the Shompen, a particularly vulnerable tribal group (PVTG) of hunter-gatherers with an estimated population of a few hundred individuals living in a tribal reserve on the island.

Seismic Concerns

- Many experts have highlighted that the proposed port is in a seismically volatile zone, which experienced a permanent subsidence of about 15 ft during the 2004 tsunami.

National Green Tribunal's intervention

- In April 2023, the Kolkata Bench of the National Green Tribunal (NGT) declined to interfere with the environmental and forest clearances granted to the project.



Lt Gen Satish Dua

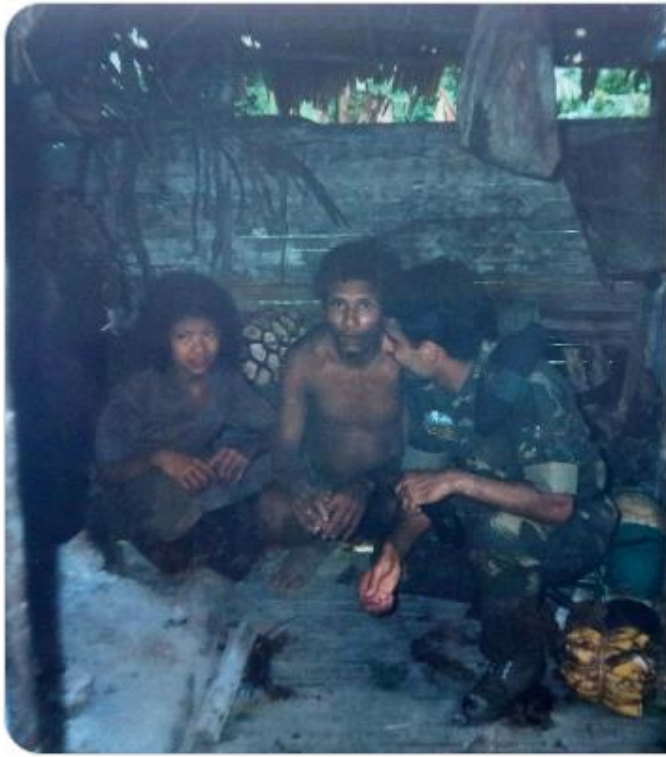
@TheSatishDua



Very heartening to see the voting by the Shompen tribals in the remote Great Nicobar Island in [#LokSabha](#) polls

Recall the days when I was posted in Port Blair in mid nineties when it took me several days to reach there.

This is one of the success stories of these elections



Lt Gen Satish Dua

@TheSatishDua

Retd Army General • Former GOC 15 Corps, Kashmir • Retired as Chief of Integrated Defence Staff • Counter Terrorism expert • Author • Motivational/TEDx Speaker

New Delhi, India Joined February 2016

152 Following 150.9K Followers



Great Nicobar Island





Jairam Ramesh

@Jairam_Ramesh

First thing I read on 63rd day of #BharatJodoYatra is the depressing news that 15% of rich forest area of Great Nicobar island will be destroyed in the name of so-called 'development'. This is another aspect of Bharat Todo that the yatra is challenging.

प्रकृति रक्षति रक्षितः ॥



Facing the axe: More than eight lakh trees will have to be cut for the project, as per a government estimate. SPECIAL ARRANGEMENT

Pankaj Sekhsaria
MUMBAI

The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has granted an in-principle (Stage 1) clearance for the diversion of 130.75 sq. km of forest

project implementation agency is the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO).

The area is nearly 15% of the thickly forested Great Nicobar Island that is spread over 900 sq. km

final environment impact assessment (EIA) report of the project that was prepared in March 2022 and accepted by the Ministry's Expert Appraisal Committee (EAC) had calculated the cost of this compensatory afforestation to be ₹970 crores.

Interestingly, the final EIA report mentioned that the compensatory afforestation over 260 sq km (twice the diversion area) will be carried out in Madhya Pradesh and even carries a letter of the Andaman and Nicobar Forest Department certifying that the Government of Madhya Pradesh has submitted the details for the same. There is no clarity on how the switch was made to Haryana and what process, if any, was followed for the same.

Though the permission letter mentions the "recommendations of the FAC", no details or minutes are available on the Ministry's website of the FAC meetings where these decisions were taken.

Communications (and reminders) seeking details sent to the official email addresses of all the members of the FAC that granted the forest clearance also did not evoke any response. A Right to Information (RTI) application filed in October

Nicobar project gets assent for diversion of 130 sq. km of forest



Facing the axe: More than eight lakh trees will have to be cut for the project, as per a government estimate. SPECIAL ARRANGEMENT

Pankaj Sekhsaria
MUMBAI

The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has granted an in-principle (Stage 1) clearance for the diversion of 130.75 sq. km of forest on Great Nicobar Island for the mega ₹72,000-crore project that includes a transshipment port, an airport, a power plant and a greenfield township. The

project implementation agency is the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDCO).

The area is nearly 15% of the thickly forested Great Nicobar Island that is spread over 900 sq. km. This will be one of the largest single such forest diversions in recent times.

CONTINUED ON
» PAGE 10



A port, airport, and power plant are being planned on over 130 sq. km of pristine forest as part of the project. GETTY IMAGES

Over nine lakh trees likely to be axed for Great Nicobar Project

Jacob Koshy
NEW DELHI

er, this was challenged in the National Green Tribunal (NGT) following which

Over nine lakh trees likely to be axed for Great Nicobar Project

Jacob Koshy
NEW DELHI

The Centre's ambitious ₹72,000-crore Great Nicobar Project may see 9.64 lakh, and not 8.5 lakh, trees felled to enable the construction of a transshipment port, an international airport, a township, and a 450- MVA gas- and solar-based power plant on the Great Nicobar island, according to a response by Minister of State (Environment) Ashwini Kumar Choubey in the Rajya Sabha on Thursday.

Green Tribunal (NGT), following which it set up an expert committee in April to investigate aspects of the clearance.

'Strategic importance'
Though details of a project being appraised for environmental clearance are usually made available on a public portal maintained by the Environment Ministry, details on the Great Nicobar Project have not been put up, it is learnt, following instructions from the Union Home Ministry that has classified



Praveen Chakravarty

@pravchak

Modi govt is moving very fast to clear a ₹70,000 cr trans-shipment port in the 'Great Nicobar Island' in Andaman & Nicobar.

Why?

Adani Ports is one of the bidders for that project.

In an unprecedented haste, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has cleared the dossier for a mega project at the cost of about ₹70,000 crore at the southern tip of the Andaman and Nicobar Islands. NITI Aayog is leading the project and the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation is the project proponent. The 'Holistic Development of Great Nicobar Island' project aims to develop an international transshipment port of 84.2 MTEU cargo capacity at Galathea Bay along the island's south-eastern coast, an international airport to support 4,000 passengers during peak hours, a 450 MVA gas and solar-based power plant, and an ecotourism and residential township of about 100 sq km. The government hopes to establish the offices of multinational corporations by clearing about a million trees in the tropical rain forests and destroying large parts of coral reefs.



G.P. Rajendran is an adjunct professor at National Institute of Advanced Studies, Bangalore, and a director of the Centre for Sustainable Development, Chennai, India.

shows that the Union government is keen to implement this project. The Great Nicobar Island has a population of about 5,000. Once completed, the project is expected to attract more than 2 lakh people, which is equal to the current population of the entire Lakshadweep island chain. The ecological and environmental cost of this urbanisation project in an area known for its marine and terrestrial biodiversity appears to have been set aside without any serious consideration. Thus, it would be a travesty to call this project as 'holistic' if the authorities forgotten that a financially successful transshipment hub can be sustained only with viable hinterland economic activities? Expecting that in a place like Great Nicobar is wishful thinking.

The island, which is spread over 900 sq km, was declared a Biosphere reserve in 1989 and included in the UNESCO's Man and Biosphere Programme in 2013. More than three-fourth of it is designated as a tribal reserve under the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Amendment legislation. The agenda to convert this pristine island into a commercial hub to compete with the international port in Singapore is nothing but 'suicide'. This project will also run counter to the rights of vulnerable tribal communities, such as the Nicobarese and Shompen, who have been living in these areas for thousands of years and who depend on the forests for survival.

To recreational afforestation as a compensation for the loss of forest in the Great Nicobar Island is farcical. The EIA report says compensatory afforestation will be carried out in Haryana and Madhya Pradesh. For field afforestation, that too in areas that have no ecological comparison, makes no sense. The project will end up destroying vast stretches of coral reefs. The report recommends 'trimmication' of

change-induced ocean warming. Transplanted corals do not have a high survival rate and are susceptible to bleaching, according to various studies.

Tectonic instability Further, the Great Nicobar Island is located close to the sub-trend of the 2004 Indian Ocean earthquake which displaced the sea floor by 10-20m vertically as well as release of tonnes of undersea rock. The EIA report itself admits that "Great Nicobar lies in close proximity to the Ring of Fire and the tsunami of 26 December 2004 is a clear demonstration of how prone it is to severe natural disasters."

The report, however, fails to mention scientific studies during and prior to the 2004 earthquake. The coastline of the Great Nicobar Island, which was raised earlier, sank several meters during the earthquake. Post earthquake satellite measurements show that the island topography is slowly regaining its original height relative to the sea level. Massive earthquakes like this are inevitable in this region. The repeated up and down movement of land in response to such earthquakes makes the Great Nicobar Island unsuitable to be developed as an urban port city, but the EIA report hardly considers the tectonic instability around Great Nicobar.

On international fora, India's leaders and representatives always highlight the country's role in championing conservation, sustainability, and green development models. But our opinion is clouded by unsustainable developmental projects such as the one being formulated for Great Nicobar - projects which dilute environmental laws to ease execution. Growth in terms of GDP makes no sense if it ends up in the inevitable loss of natural capital. It is high time that the Prime Minister's expressed vision of 'green developmental model'

Adani Ports, Concor, JSW Infra among ten entities to file EoI for container transshipment hub in Great Nicobar Island

Dutch dredging contractor Royal Boskalis Westminster N.V., Rail Vikas Nigam, Essar Ports, Megha Engineering & Infrastructures, Navayuga Engineering, Vishwa Samudra Holdings and PDP International.

ETInfra • March 08, 2023, 12:27 IST

Adani Ports, Concor, JSW Infra among ten entities file EoI for container transshipment hub in Great Nicobar Island

Dutch dredging contractor Royal Boskalis Westminster N.V., Rail Vikas Nigam, Essar Ports, Megha Engineering & Infrastructures, Navayuga Engineering, Vishwa Samudra Holdings and PDP International.

P Manoj • ETInfra • March 08, 2023, 12:27 IST

CONCERNS ASSOCIATED WITH THE NICOBAR PROJECT

8.5 lakh trees will have to be cut, loss of 12 to 20 hectares of mangrove cover.



Indigenous Shompen and Nicobarese tribes will be affected.



Around 10 hectares of coral cover will have to be translocated.



The leatherback sea turtles, Nicobar megapode, Nicobar Macaque, and saltwater crocodiles are the rare fauna that will be affected.





Great Nicobar Project may see 9.64 lakh trees axed, says Minister

The Hindu had reported in November 2022, based on documents then available, that the Environment Ministry had estimated that close to 8.5 lakh trees were expected to be cut for the project

August 03, 2023 08:53 pm | Updated August 04, 2023 12:02 pm IST - NEW DELHI



JACOB KOSHY



READ LATER



PRINT



Great Nicobar Biosphere Reserve

3 languages ▼

Article Talk

Read Edit View history Tools ▼

From Wikipedia, the free encyclopedia

Coordinates: 7.0500°N 93.7750°E﻿ / ﻿

The **Great Nicobar Biosphere Reserve** encompasses a large part (some 85%) of the island of [Great Nicobar](#), the largest of the [Nicobar Islands](#) in the [Indian Union Territory](#) of [Andaman and Nicobar Islands](#). The Nicobars lie in the [Bay of Bengal](#), eastern [Indian Ocean](#), 190 km (120 mi) to the north of the [Indonesian](#) island of [Sumatra](#). The reserve has a total core area of approximately 885 km², surrounded by a 12 km-wide "forest buffer zone".^[1] In year 2013 it was included in the list of Man and Biosphere program of [UNESCO](#) to promote sustainable development based on local community effort and sound science.^[2]

Geography [edit]

The reserve was formality created in January 2013. It incorporates two [National parks of India](#), which were gazetted in 1992: the larger [Campbell Bay National Park](#) on the northern part of the island, and [Galathea National Park](#) in the southern interior. The non-[Biosphere](#) portions of the island (set aside for agriculture, forestry and settlements) are confined to the southwestern and southeastern coastal reaches.

The reserve has a total area of 103,870 ha. The core area of 53,623 ha comprises Cambell Bay and Galathea national parks. A buffer area of 34,877 ha includes forested lands adjacent to and between the two parks. There is also a transitional area of 10,070 ha, including 5,300 marine hectares.^{[3][4]}

Flora and fauna [edit]

The environment is classified by the [World Wide Fund for Nature](#) as [tropical and subtropical moist broadleaf forests biome](#), and located in the [Indomalayan realm](#).^[4]

The reserve is home to many [species](#) of plants and animals, often [endemic](#) to the Andaman and Nicobars [biogeographic](#) region. Species of [fauna](#) in the reserve include: [Nicobar scrubfowl](#) (*Megapodius nicobariensis*, a [megapode](#) bird), the [edible-nest swiftlet](#) (*Aerodramus fuciphagus*), the [Nicobar long-tailed macaque](#) (*Macaca fascicularis umbrosa*), [saltwater crocodile](#) (*Crocodylus porosus*), [Andaman water monitor](#) (*Varanus salvator andamanensis*),^[5] [giant leatherback sea turtle](#) (*Dermochelys coriacea*), [Malayan box turtle](#) (*Cuora amboinensis*), [Nicobar tree shrew](#) (*Tupaia nicobarica*), [reticulated python](#) (*Python reticulatus*) and the [giant robber crab](#) (or coconut crab, *Birgus latro*).^{[3][4]}



Appearance hide

Text

- Small
- Standard
- Large

Width

- Standard
- Wide

Great Nicobar

General information

Great Nicobar is the southernmost island of the Nicobar Islands Archipelago. It covers 103 870 hectares of unique and threatened tropical evergreen forest ecosystems. It is home to a very rich ecosystems, including 650 species of angiosperms, ferns, gymnosperms, bryophytes, among others. In terms of fauna, there are over 1800 species, some of which are endemic to this area.

Detailed information

Key data

Year of nomination

2013

Country

India

Total population

353

Area

Surface

1,038.70 ha

Total terrestrial area

985.70 ha

Total Marine area

53.00 ha

Location

Latitude: 7.03 - Longitude: 93.8026

Contact

Ecosystem-based network

SACAM

Ecological Characteristics



The Great Nicobar Biosphere Reserve harbours a wide spectrum of ecosystems comprising tropical wet evergreen forests, mountain ranges reaching a height of 642 m (Mt. Thullier) above sea level, and coastal plains. The region is noted for its rich biodiversity. It houses 650 species of angiosperms, ferns, gymnosperms, bryophytes and lichens among others. The tract is rich in plant diversity and fosters a number of rare and endemic species, including *Cyathea albosetacea* (tree fern) and *Phalaenopsis speciosa* (orchid). A total of 14 species of mammals, 71 species of birds, 26 species of reptiles, 10 species of amphibians and 113 species of fish have been reported. The region also harbours a large number of endemic and endangered species of fauna. To date, 11 species of mammals, 32 species of birds, 7 species of reptiles and 4 species of amphibians have been found to be endemic. Of these, the well-known Crab-eating Macaque, Nicobar Tree Shrew, Dugong, Nicobar Megapode, Serpent Eagle, salt water crocodile, marine turtles and Reticulated Python are endemic and/or endangered.

Socio-Economics Characteristics

The Mongoloid Shompen Tribe, about 200 in number, live in the forests of the biosphere reserve particularly along the rivers and streams. They are hunters and food gatherers, dependent on forest and marine resources for sustenance. Another Mongoloid Tribe, Nicobarese, about 300 in number, used to live in settlements along the west coast. After the tsunami in 2004, which devastated their settlement on the western coast, they were relocated to Afra Bay in the North Coast and Campbell Bay. They survive on fish caught from the sea. The settlers and mainlanders, which number over 8 000, live along the southeast coast of the island, practising agriculture, horticulture and fishing. The Shompens move between the Core and Buffer Zones, while the settlers and Nicobarese live in settlements spread along the coast in the Transition zone.





NGT constitutes high-powered committee to revisit environmental nod granted to Great Nicobar Island project

The Great Nicobar Island (GNI) is a mega project to be implemented at the southern end of the Andaman and Nicobar islands. The project includes an international container transshipment terminal, an international airport, township development, and a 450 MVA gas and solar based power plant over an extent of 16,610 hectares in the island.

Updated - April 07, 2023 05:14 pm IST Published - April 07, 2023 03:19 pm IST - Chennai


THE HINDU BUREAU




 READ LATER  PRINT



 greentribunal.gov.in 

 The National Green Tribunal is a statutory body in India that deals with expeditious disposal of cases related to environmental protection and other natural resources. It was set up under the National Green Tribunal Act in 2010. [Wikipedia](#)

 Translated by Google

 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान से संबंधित है। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। [विकिपीडिया](#)

हिन्दी में खोजें : [राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण](#)

Founded: 18 October 2010

Headquarters: [India](#)

Agency executive: [Prakash Shrivastava](#), Chairperson
[Afroz Ahmad](#), Member

Formed: 2010



Environment

Cut trees for projects in Nicobar, plant some in MP? Why Modi govt plan hasn't assuaged concerns

Great Nicobar Island to get transshipment port, airport, township. MP, Haryana earmarked for compensatory afforestation but experts say that can't make up for lost virgin rainforests.

SIMRIN SIRUR 01 December, 2022 02:09 pm IST



Representational image | Credit: Commons



Most Popular

Haryana results can be a template for Rahul Gandhi to build New Congress
D.K. Singh - 17 June, 2024

Suspected of 'committing murder for hire' — Czech extradites 'Pannun assassination plot' accused to US
Ananya Bhardwaj - 17 June, 2024

Why Nayab Singh Saini govt is confident of sailing through Oppn's floor test demand

Follow Us:

Text Size:

Review committee set to clear Rs 41,000 crore Nicobar Port project

On April 3, the Kolkata Bench of the National Green Tribunal (NGT) put a two-month stay on any further work in the EC granted to the project

Advertisement



Dhruvaksh Saha | Shreya Jai | New Delhi

4 min read Last Updated : Jun 18 2023 | 11:07 PM IST



Connect with us



A high-powered committee (HPC) formed to scrutinise the environmental clearance (EC) given to the Centre's ambitious Great Nicobar transshipment port project is likely to give its all-clear to the proposed project, which has been halted since April, multiple senior officials told *Business Standard*.

On April 3, the Kolkata Bench of the National Green Tribunal (NGT) put a two-month stay on any further work in the EC granted to the project. The Rs 41,000 crore project would be on hold until the NGT-appointed committee scrutinises the green approval granted by the Centre, read the order.

The committee was given two months



Ministry of Ports, Shipping and Waterways

@shipmin_india



Today, Shri @sarbanandsonwal , Union Minister, MoPSW visited the site of International Container Transshipment Port, at Galathea Bay, Great Nicobar Island and reviewed the project progress. The strategic location of Galathea Bay is a huge advantage to EXIM trade.

@mygovindia

Project Site Review

International Container Transshipment Port

23rd November, 2023



Galathea Bay,
Great Nicobar Island



Randhir Jaiswal and 9 others

2:54 PM · Nov 23, 2023 · 3,930 Views

Union Minister [@sarbanandsonwal](#) visits Galathea Bay in Great Nicobar Island and reviews the progress of the proposed International Container Transhipment Port (ICTP)

ICTP will be a shining example of a new India as envisaged by Prime Minister [@narendramodi](#) in Maritime Amritkal Vision 2047

Read more: pib.gov.in/PressReleasePa...



Shri Sarbananda Sonowal visits Galathea Bay in Great Nicobar Island and reviews progress of proposed International Container Transshipment Port (ICTP)

ICTP will be a shining example of new India as envisaged by Prime Minister Shri Narendra Modi in Maritime Amritkal Vision 2047

DPR of the project is under finalization and the tenders for construction of the project will be invited at the beginning of the next year.

With an estimated cost of about ₹44,000 Crores ICTP will play a crucial for the economic and infrastructural development of the Region

Posted On: 23 NOV 2023 5:49PM by PIB Delhi

Union Minister for Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) and Ayush, Shri Sarbananda Sonowal visited the site of the proposed International Container Transshipment Port (ICTP), at Galathea Bay, Great Nicobar Island today and reviewed its progress with the senior officials. As envisaged in the Maritime India vision 2030 as well as one of the key projects in the Amrit kaal Vision 2047, the proposed International Container Transshipment Port (ICTP) project has reached significant milestones, solidifying its position as a transformative initiative with a total estimated cost of about ₹44,000 Crores. The project is strategically important for the country and crucial for the economic and infrastructural development of the entire region, has garnered key approvals and support from government bodies.



Transshipment port: Govt says 11 players have expressed interest in the project in Great Nicobar Island

PTI - Last Updated: Jan 03, 2024, 04:50:00 PM IST

FOLLOW US SHARE FONT SIZE SAVE PRINT COMMENT

Synopsis
The government has received expressions of interest from 11 entities for the Rs 41,000-crore international transshipment port project at Great Nicobar Island. Union Minister Sarbananda Sonowal announced the submissions for the Bay of Bengal project, expected to handle 16 million containers annually. Planned in four phases, the first phase aims to commission by 2028, costing Rs 18,000 crore.



Sarbananda Sonowal

NEW DELHI: The government has received expressions of interest (EOIs) from 11 players for the Rs 41,000-crore international transshipment port project at Great Nicobar Island in the Bay of Bengal, Union minister Sarbananda Sonowal said on Wednesday. Last year, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in a

statement said the project is expected to be completed with an investment of Rs 41,000 crore (USD 5 billion), including investment from both government and public-private partnership (PPP) concessionaires.

"11 players have submitted expressions of interest for the international transshipment port project at Great Nicobar Island," the ports, shipping and waterways minister said.

Speaker

Tejasvi Suresh Bala
CEO, Swirl Lifestyle

Videos



Public-Private Partnership

['pə-blik 'prī-vət 'pärt-nər-,ship]

A collaboration between a government and private enterprise, often on large infrastructure projects that the private partner may finance, plan, or execute.



Ministry of Ports, Shipping and Waterways

@shipmin_india



MoPSW is developing Greenfield International Container Transshipment Port in Galathea Bay at Great Nicobar island. ICTP will allow Great Nicobar to participate in the regional & global maritime economy as a major player in cargo transshipment

[@narendramodi](#)

[@NITIAayog](#)

[@DPIITGoI](#)



10:31 AM · Feb 12, 2024 · 8,073 Views



Bengaluru
ಬೆಂಗಳೂರು

Bay of Bengal

Bangkok
กรุงเทพมหานคร

Andaman Sea


Sri Lanka

Laccadive Sea

Thai

Gu
The

Ma
Kuala

 India is determined to build its own "Hong Kong" on the pristine Great Nicobar island. Activists warn the impact could go beyond wrecking the environment — it could spell extinction for the indigenous people.

Read here: p.dw.com/p/4cc94



NATURE AND ENVIRONMENT | INDIA

Will India's megaproject sink Great Nicobar island?

Murali Krishnan in New Delhi
02/20/2024

India is determined to build its own "Hong Kong" on the pristine Great Nicobar island. Activists warn the impact could go beyond wrecking the environment — it could spell extinction for indigenous islanders.



A wooden boat

Suspend all clearances, conduct review of 'mega infra project' in Great Nicobar Islands: Congress to govt

Ambika Pandit / TNN / Jun 17, 2024, 22:31 IST

SHARE



AA

FOLLOW US



New For You



'Didn't expect tip-off to ...
'; Mystery call on 'safe
house' put cops on NEET...



PM Modi meets Bangladesh
PM Sheikh Hasina at
Rashtrapati Bhavan



Congress demands suspension of Rs 72,000 crore infra project in Great Nicobar Islands, posing threat to tribal communities and natural ecosystem.



The Congress party on June 17 demanded the withdrawal of clearances and a ground-up review of the ₹72,000 crore infrastructure project, being championed by the National Democratic Alliance (NDA) government, at the Great Nicobar Island.

The Great Nicobar Project, as it is called, involves developing a trans-shipment port, an international airport, township development, and a 450 MVA gas and solar-based power plant on the island. The project area is expected to be spread over 130 sq. km. of pristine forest, and has been accorded environmental clearance — one of the mandatory pre-requisites — by an expert committee. Several concerns have been raised on the project on environmental grounds, as well as the alleged violation of the rights of tribals resident in the region.



Jairam Ramesh ✓

@Jairam_Ramesh



This is a mega ecological disaster that **MUST** be averted



The Hindu ✓ @the_hindu · Jun 17

The Congress party on June 17 demanded the withdrawal of clearances and a ground-up review of the ₹72,000 crore infrastructure project, being championed by the National Democratic Alliance (NDA) government, at the Great Nicobar Island.

trib.al/ib3MqKI

10:53 AM · Jun 18, 2024 · **27.8K** Views



**STATEMENT ISSUED BY SHRI JAIRAM RAMESH, MP, GENERAL
SECRETARY (COMMUNICATIONS), AICC**

17th June 2024

The Union Government's proposed Rs. 72,000 crore "Mega Infra Project" in Great Nicobar Island is a grave threat to Great Nicobar Island's tribal communities and natural ecosystem. The project, initiated in March 2021 at the instance of the NITI Aayog, shows numerous red flags:

- The Ministry of Environment, Forests and Climate Change has given 'in principle' clearance for diverting 13,075 hectares of forest land. This area is about 15% of the island's land mass and constitutes one of the country's largest forest diversions in a nationally and globally unique rainforest ecosystem
- Compensatory afforestation for the loss of this unique rainforest ecosystem has been planned in the state of Haryana, thousands of kilometres away and in a vastly different ecological zone
- The coastline where the port and the project is proposed to come up is an earthquake prone zone, and saw a permanent subsidence of about 15 feet during the tsunami of December 2004. Locating such a massive project here puts investment, infrastructure, people, and the ecology in harm's way
- The project poses a direct threat to the wellbeing and survival of the Shompen, an indigenous community classified as a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG). 39 experts from across the world have warned the Administration that the project poses the threat of genocide to the Shompen
- The Administration has compromised on due process in its rush to get approval –
 - The Administration did not adequately consult the Tribal Council of the Islands, as is legally required. The Tribal Council of Great Nicobar Island has in fact expressed objections to the Project, claiming that the authorities had earlier "rushed them" into signing a "No Objection" letter based on misleading information – and that the No Objection letter has since been revoked
 - The Administration ignored the Island's Shompen Policy, notified by the Union Ministry of Tribal Affairs, which requires authorities to prioritise the tribe's welfare when considering "large scale development proposals"
 - The Administration appears to have skipped the legally mandated consultation with the Scheduled Tribes Commission, required by Article 338(9) of the Indian Constitution
 - The "Social Impact Assessment" conducted as part of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR) ignored the existence of the Shompen and the Nicobarese
 - Parts of the project site come under CRZ 1A (areas with turtle nesting sites, mangroves, coral reefs), which has been noted in an NGT order in response to petitions challenging the clearances. Allowing port construction here is clearly violative of the said provisions.
 - The Project violates the letter and spirit of the Forest Rights Act (2006), which holds the Shompen as the sole legally empowered authority to protect, preserve, regulate and manage the tribal reserve

In view of these numerous violations of due process, legal and Constitutional provisions protecting Tribal communities, and the project's disproportionate ecological and human cost, the Indian National Congress demands an immediate suspension of all clearances and conduct of a thorough impartial review of the proposed project, including by the Parliamentary committees concerned.



Jairam Ramesh ✓

@Jairam_Ramesh

Our statement on the Mega Infra Project on Great Nicobar Island. @INCIndia demands an immediate suspension of all clearances and conduct of a thorough impartial review of the proposed project, including by the Parliamentary committees concerned.

1:42 PM · Jun 17, 2024 · 28.1K Views



Q. Which of the following have coral reefs?

1. Andaman and Nicobar Islands
2. Gulf of Kachchh
3. Gulf of Mannar
4. Sunderbans

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1, 2 and 3 only
- (b) 2 and 4 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

Ans: (a)



NCERT

FOUNDATION BATCH

EMI

OPTION AVAILABLE

OFFER PRICE
4999 Rs

Purchase Time to Pay
→ **2500 Rs**

Next Month to Pay
→ **2500 Rs**

EMI OFFER AVAILABLE FOR 24HR ONLY/-

- 1.SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
- 2.SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
- 4.SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
- 5.ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:



T&C APPLY



BY ANKIT AVASTHI SIR

LIMITED SEATS

और **EMI INFORMATION** के लिए

7878158882 अभी कॉल करें

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM



KASHMIR THE HEAVEN ON EARTH









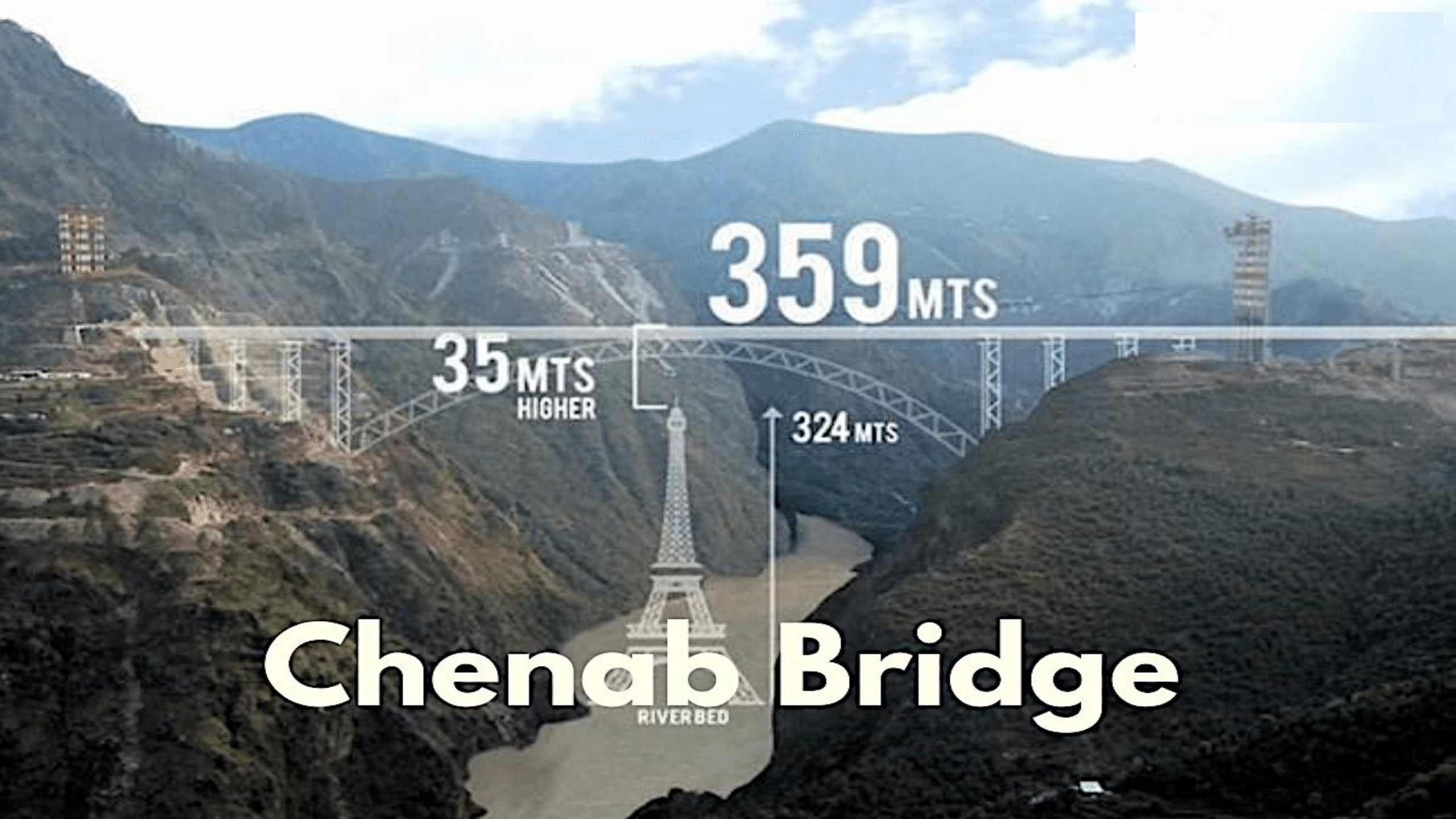
359 MTS

35 MTS
HIGHER

324 MTS

Chenab Bridge

RIVER BED







Railways conducts trial run on world's highest arch rail bridge in J&K

According to the Ministry, it was the first ever full train that crossed over the iconic bridge between Dugga and Bakkal stations across the Chenab river, which is the world's highest arch railway bridge

Published - June 21, 2024 04:14 am IST - New Delhi/Jammu



Chenab Rail Bridge Achieves Big Milestone! Indian Railways Conducts Train Trials On World's Highest Railway Bridge - Check Top Facts

TOI Business Desk / TIMESOFINDIA.COM / Updated: 20 Jun 2024, 11:36:04 PM

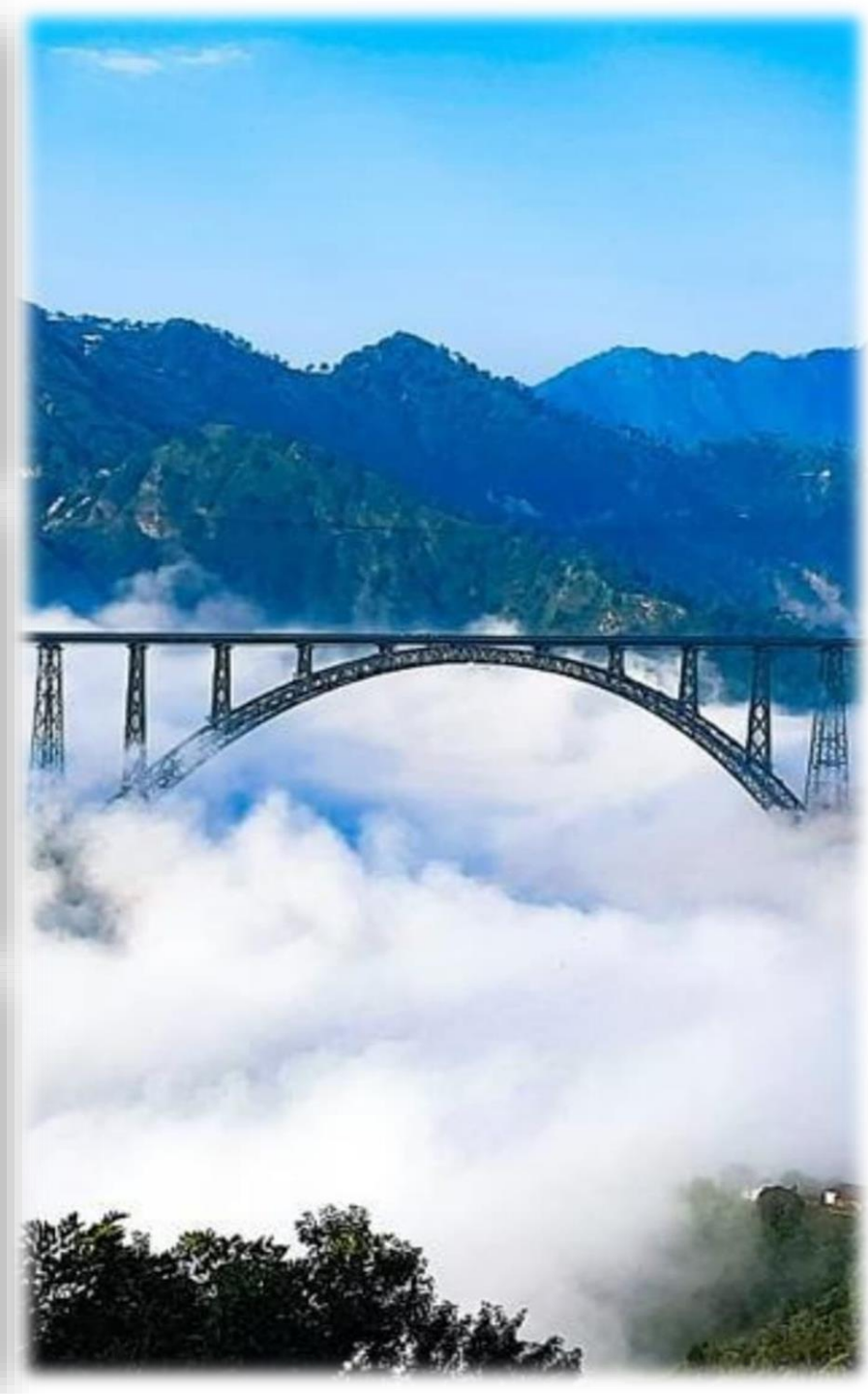
SHARE AA FOL

Home / India News / WATCH: Railways' successful trial run on world's highest Chenab rail bridge

WATCH: Railways' successful trial run on world's highest Chenab rail bridge

3 min read Last Updated : Jun 21 2024 | 10:52 AM IST

Indian Railways conducted the first trial run on the Chenab Rail Bridge, the world's highest railway bridge, connecting Sangaldan in Ramban district to Reasi



भारतीय रेलवे ने 20 जून, 2024 को रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच नवनिर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल-चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रायल रन किया। लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी।

भारतीय रेलवे ने 20 जून को जम्मू-कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल - चिनाब ब्रिज - पर आठ कोच वाली मेमू ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे कश्मीर में रियासी से बारामूला तक मार्ग पर रेल सेवा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

"रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे और कोंकण रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नवनिर्मित चिनाब ब्रिज के व्यापक निरीक्षण के बाद, रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच 46 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत लाइन खंड पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक परीक्षण चलाया गया," रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा।



Ashwini Vaishnaw 

@AshwiniVaishnaw



1st trial train between Sangaldan to Reasi.



Last edited 7:50 PM · Jun 16, 2024 · **606.6K** Views



anand mahindra   @anandmahindra · Jun 21



The first train to cross the world's highest railway bridge—the **Chenab Bridge** in India.

Since it's Yoga Day, it's the perfect image to signify that our infrastructure is stretching itself as far towards the skies as possible.... 😊



From **Indian Tech & Infra** 

“इसे सफलतापूर्वक दोपहर 12:35 बजे संगलदान से शुरू किया गया और दोपहर 2:05 बजे (20 June) रियासी तक पहुंचाया गया। रास्ते में यह 40.787 किमी की कुल लंबाई और 11.13 किमी की सबसे लंबी सुरंग टी-44 के साथ नौ सुरंगों से होकर गुजरती है।” उन्होंने कहा।

मंत्रालय के अनुसार, यह पहली पूर्ण ट्रेन थी जो चिनाब नदी पर दुग्गा और बक्कल स्टेशनों के बीच प्रतिष्ठित पुल को पार कर गई, जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है।

स्टेशन - रियासी, बक्कल, दुग्गा और सावलकोटे - जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित हैं। मंत्रालय ने कहा, "इस खंड पर विद्युतीकरण कार्य रेलवे पर पहली बार 25 केवी पर अत्याधुनिक तकनीक, ROCS (रिगिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम) के साथ निष्पादित किया गया है।"



Ankit Kumar Avasthi ✓

@kaankit



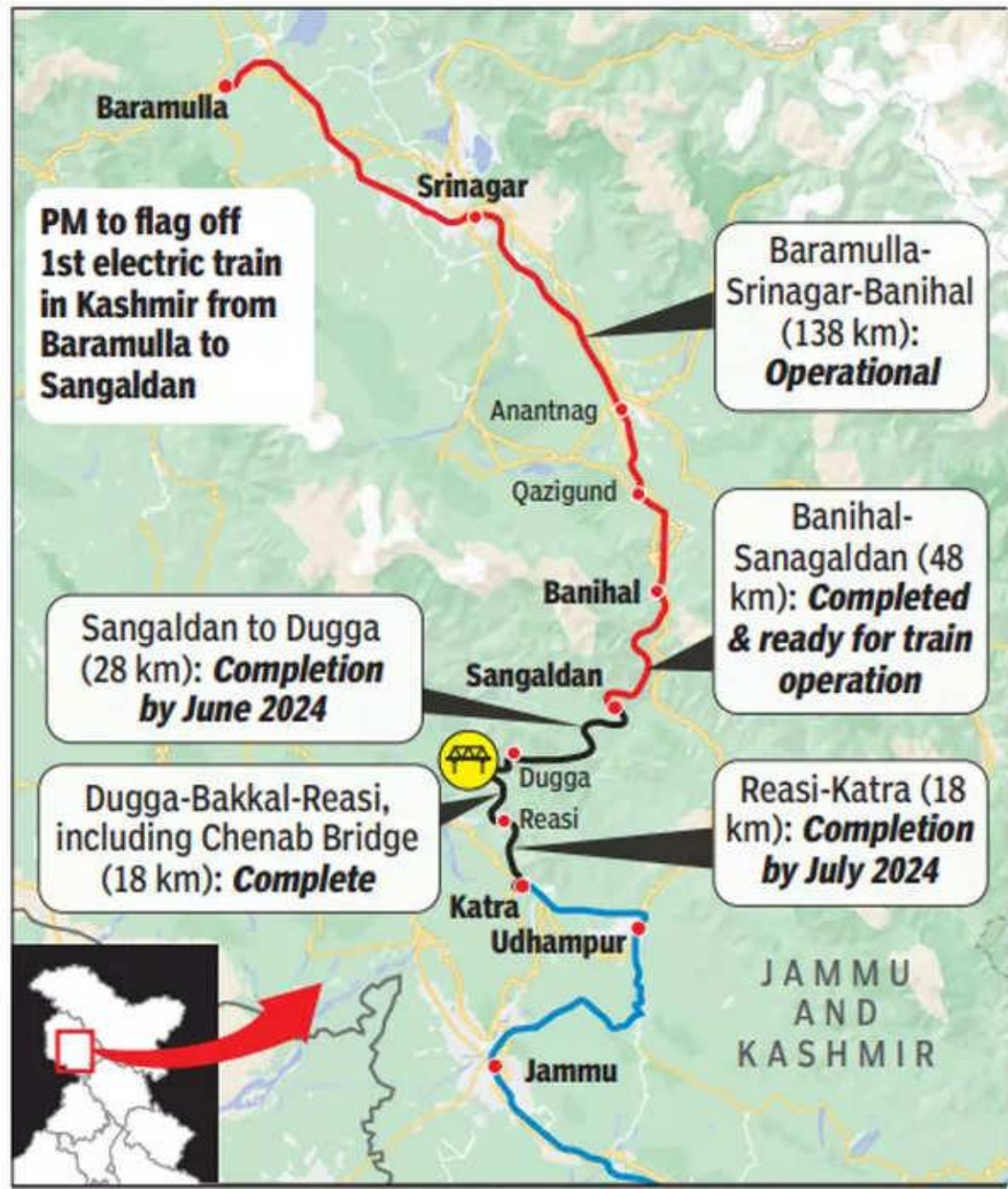
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर भारतीय रेल !

📍 चिनाब नदी का आर्च ब्रिज, जम्मू-कश्मीर



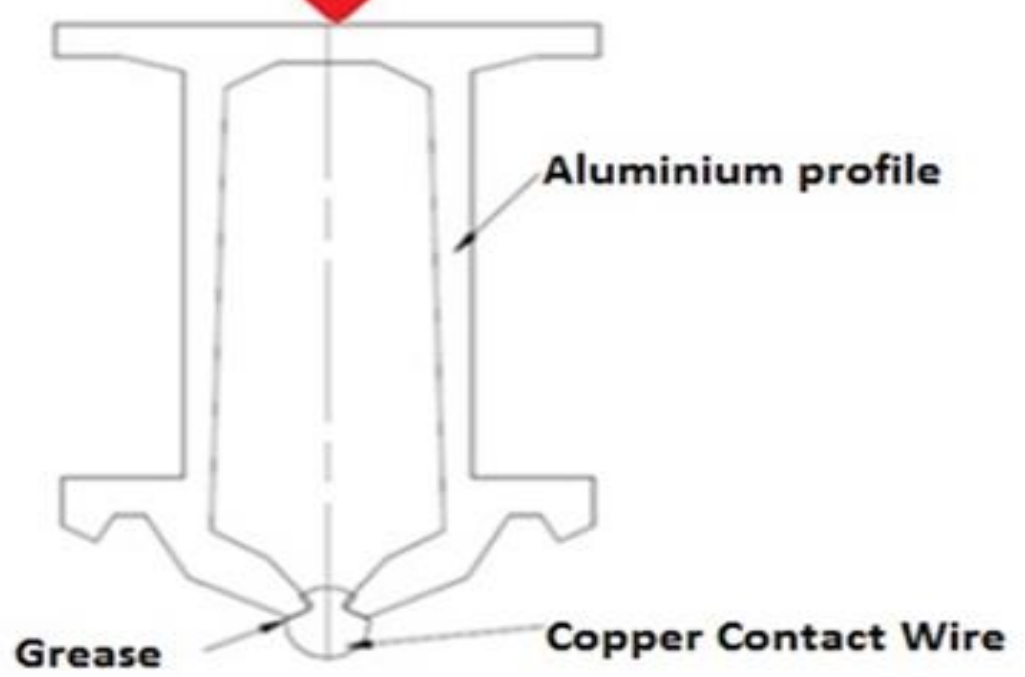
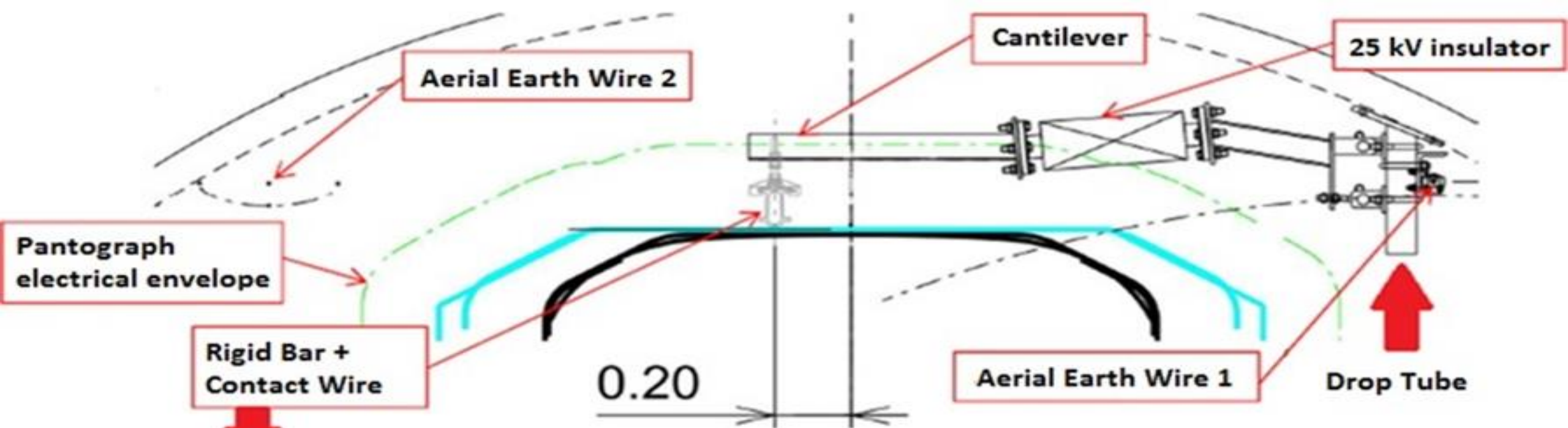
4:30 PM · Jun 21, 2024 · 152.7K Views

STATUS OF KATRA-BARAMULLA SECTION



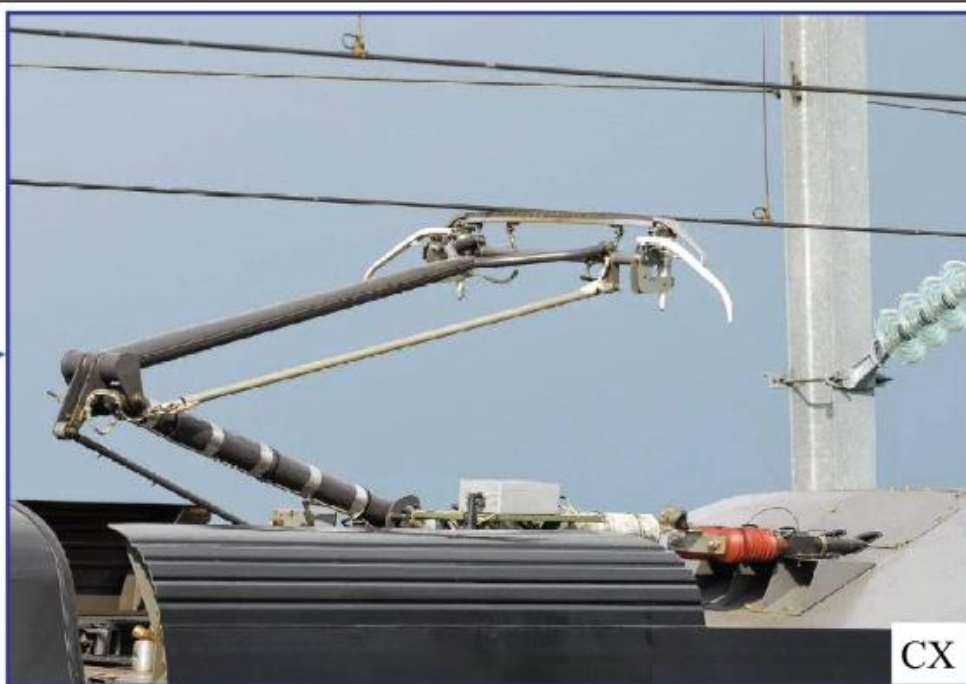
Rigid Overhead Conductor System (ROCS) uses a rigid conductor instead of a flexible wire for electric power collection. ROCS has a rigid conductor rail installed overhead. A copper contact wire is inserted in the conductor rail and the Pantograph on the rolling stock collects power from this rigid conductor. 6 Apr 2021



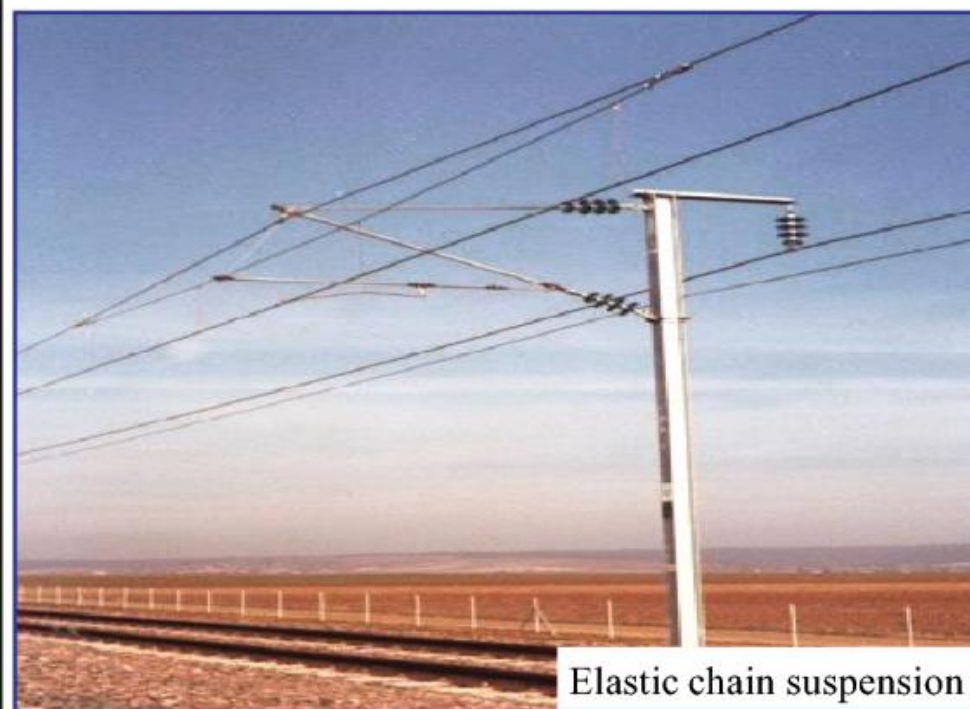




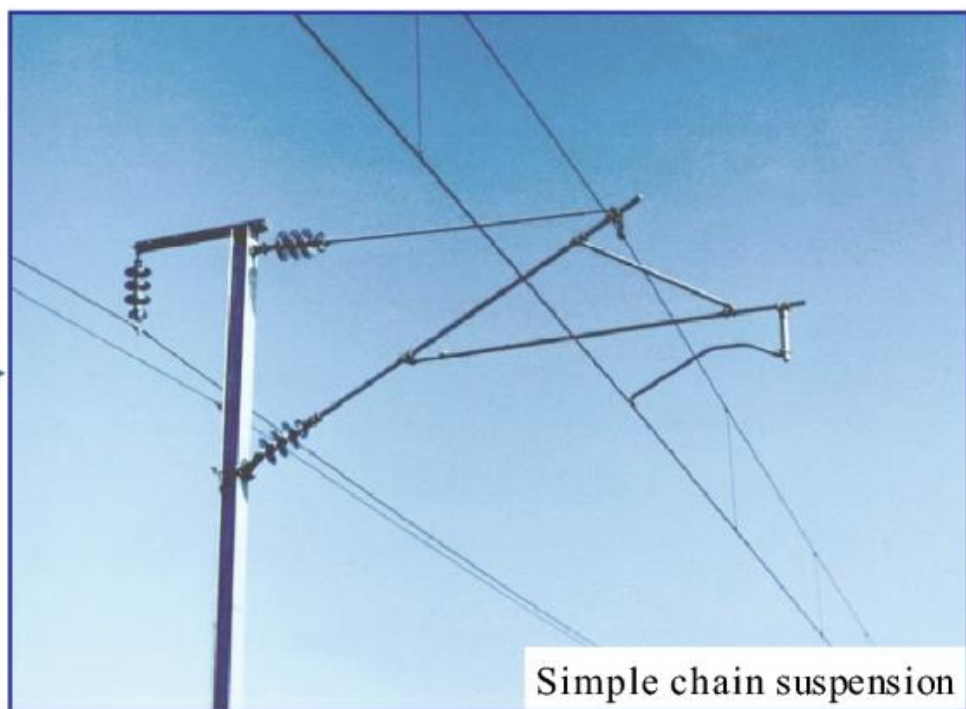
ADME



CX

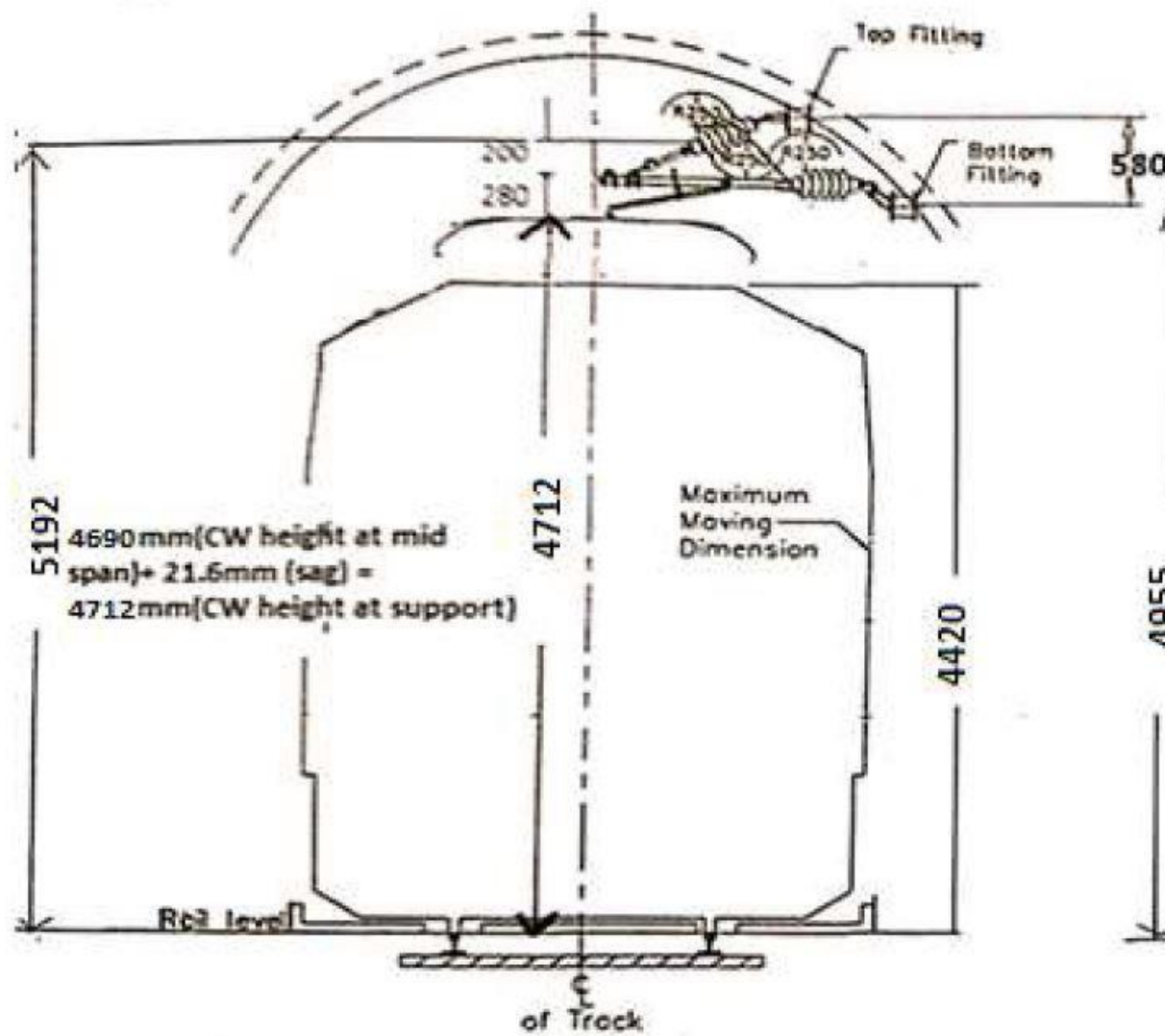


Elastic chain suspension

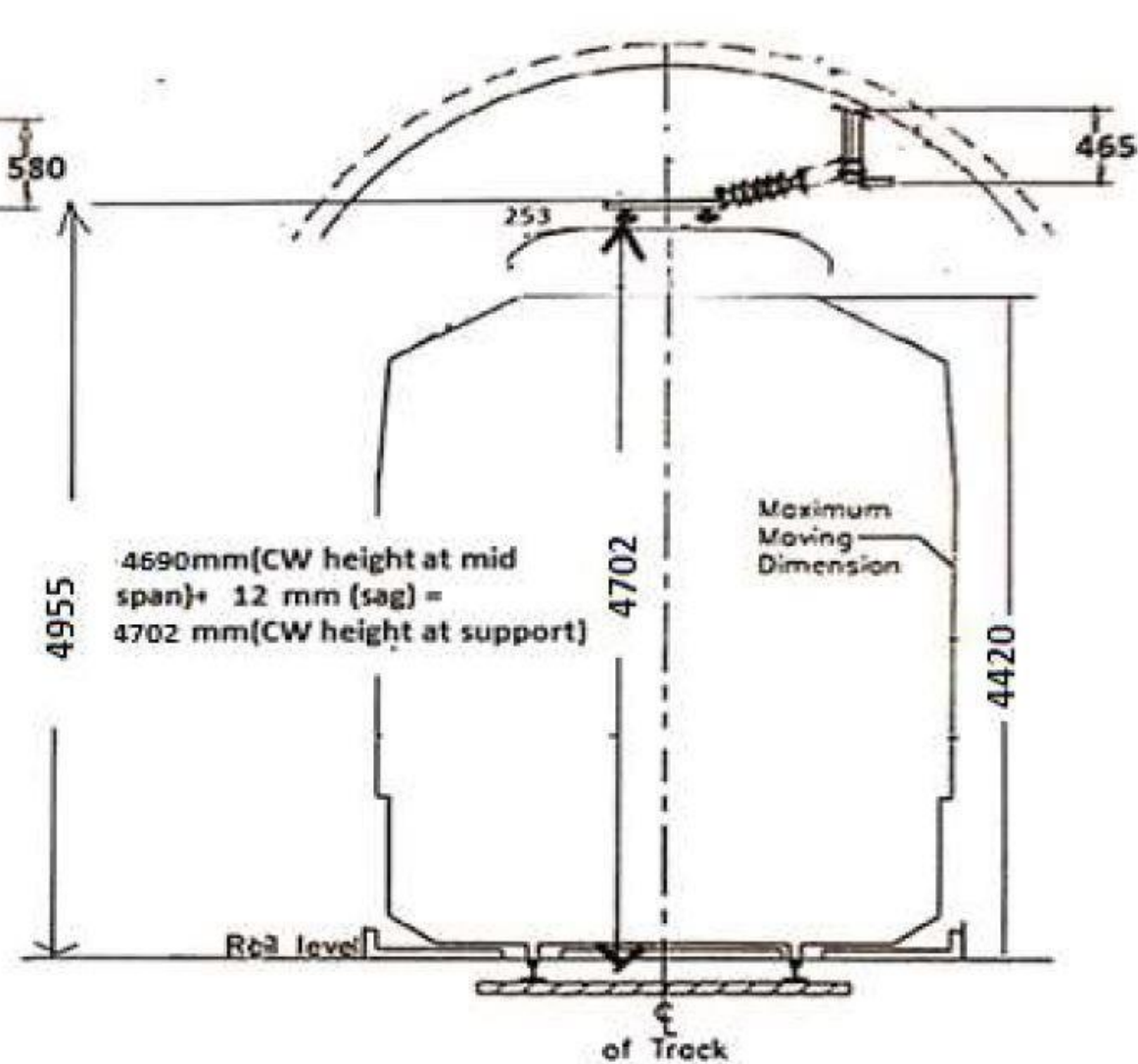


Simple chain suspension

CONVENTIONAL OHE



ROCS SYSTEM



जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज संगलदान और रियासी के बीच रेलवे लाइन का हिस्सा है। इस रूट पर 30 जून से ट्रेन ऑपरेट करेगी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जून को बताया था कि जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ है। यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस सफल परीक्षण की जानकारी दी।

चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टॉवर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किमी लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है।



Ashwini Vaishnaw 

@AshwiniVaishnaw



1st trial train between Sangaldan to Reasi.



Last edited 7:50 PM · Jun 16, 2024 · **606.6K** Views

359 MTS

35 MTS
HIGHER

324 MTS

Chenab Bridge

RIVER BED



चिनाब पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज

• ब्रिज की लंबाई
1,315 मीटर

• नदी तल से
ब्रिज की ऊंचाई
359 मीटर

• एफिल टावर
330 मीटर

चिनाब नदी





CHENAB BRIDGE

**World's highest railway bridge,
359m** above the river bed level.

Part of the **Udhampur-Srinagar-Baramulla**
rail link project.

The Bridge is **1315 meters** long and is
35 meters higher than the iconic
Eiffel Tower in Paris (France).

Length of Arch span is **467 meters**,
longest in India

Bridge designed to withstand high
wind speed up to **266 km/hr.**

ARCHITECTURAL MARVEL



1.3 km
Total length
of the bridge

17
Total number
of spans

133.7 m
Maximum
height of
steel pier

485 m
Main arch
span

359 m
Height of the
bridge from
the riverbed

- 326 km**
Total stretch
between Bara-
mulla & Jammu
- 25,000**
Metric ton is total
steel fabrication
- 220 kmph**
Wind velocity
at the deck
- 100 kmph**
Maximum speed
permissible
- ₹512 cr**
Cost of the
bridge
- ₹20,000 cr**
Total cost of
the project

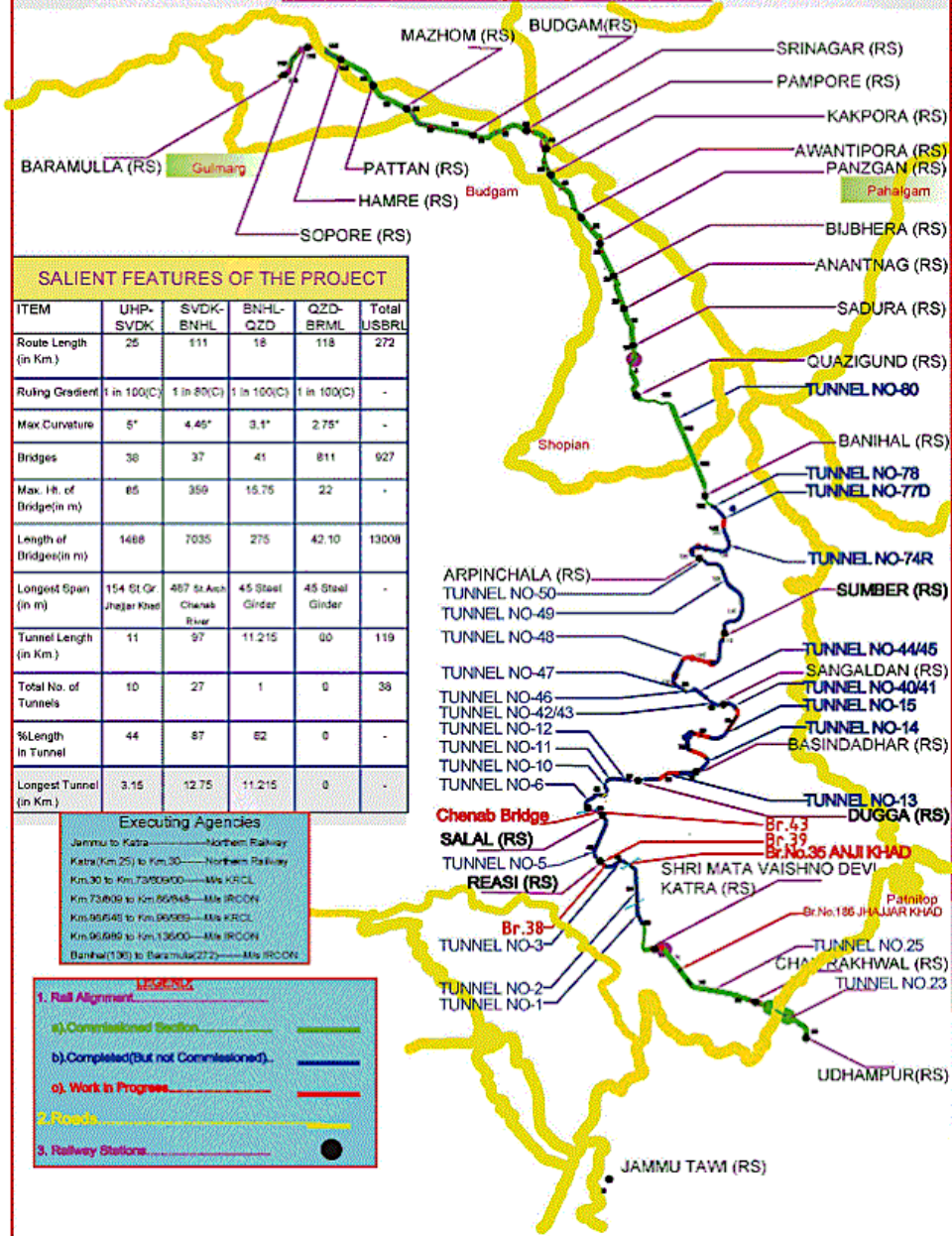
**CHENAB
RIVER**

रेल मंत्री बोले- प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक (USBRL) प्रोजेक्ट के तहत सभी निर्माण कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। टनल नंबर 1 का निर्माण थोड़ा बाकी है। USBRL प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारतीय रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक और कदम पूरा होगा।

केंद्रीय मंत्री और ऊधमपुर से भाजपा सांसद जितेंद्र सिंह ने भी 15 जून को X पर लिखा कि रामबन के संगलदान से रियासी के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा।

**UDHAMPUR SRINAGAR BARAMULLA
NEW RAIL LINK (B.G.) PROJECT.**



The plan

The Udhampur to Baramulla rail link is 272 km long.



Source: Northern Railway Construction Organization (USBRL Project)

THE TRAIN TO KASHMIR

KATRA-QAZIGUND SECTION

ESTIMATED COST
₹21,653 cr



BARAMULLA

QAZIGUND-BARAMULLA (119 km)
COMMISSIONED in Oct 2009;
Cost ₹ 3,493 cr

Srinagar

BANIHAL-QAZIGUND (18 km)
COMMISSIONED in July 2014;
Cost ₹ 1,692 cr

Qazigund

Banihal

Work In Progress

COMPLETED (129 km)
(But not commissioned)

CHENAB BRIDGE

Shri Mata Vaishno Devi Katra

ANJI KHAD BRIDGE

UDHAMPUR-KATRA (25 km)
COMMISSIONED in July 2014;
Cost ₹ 1,111 cr

Udhampur

Graphic: IE Design

**HIGHEST RAILWAY
BRIDGE IN WORLD**

359 m above Chenab
bed, 35 m higher than
Eiffel Tower

**FIRST CABLE-
STAYED BRIDGE**

of the Indian Railways
on the Anji Khad, in
Reasi district

**LONGEST
TRANSPORT TUNNEL**

in India; 12.75 km
long, in Ramban
district

38 TUNNELS with combined
length 119 km

927 BRIDGES with combined
length 13 km

27-28 जून को रेलवे सेफ्टी कमिश्नर रूट का दौरा करेंगे

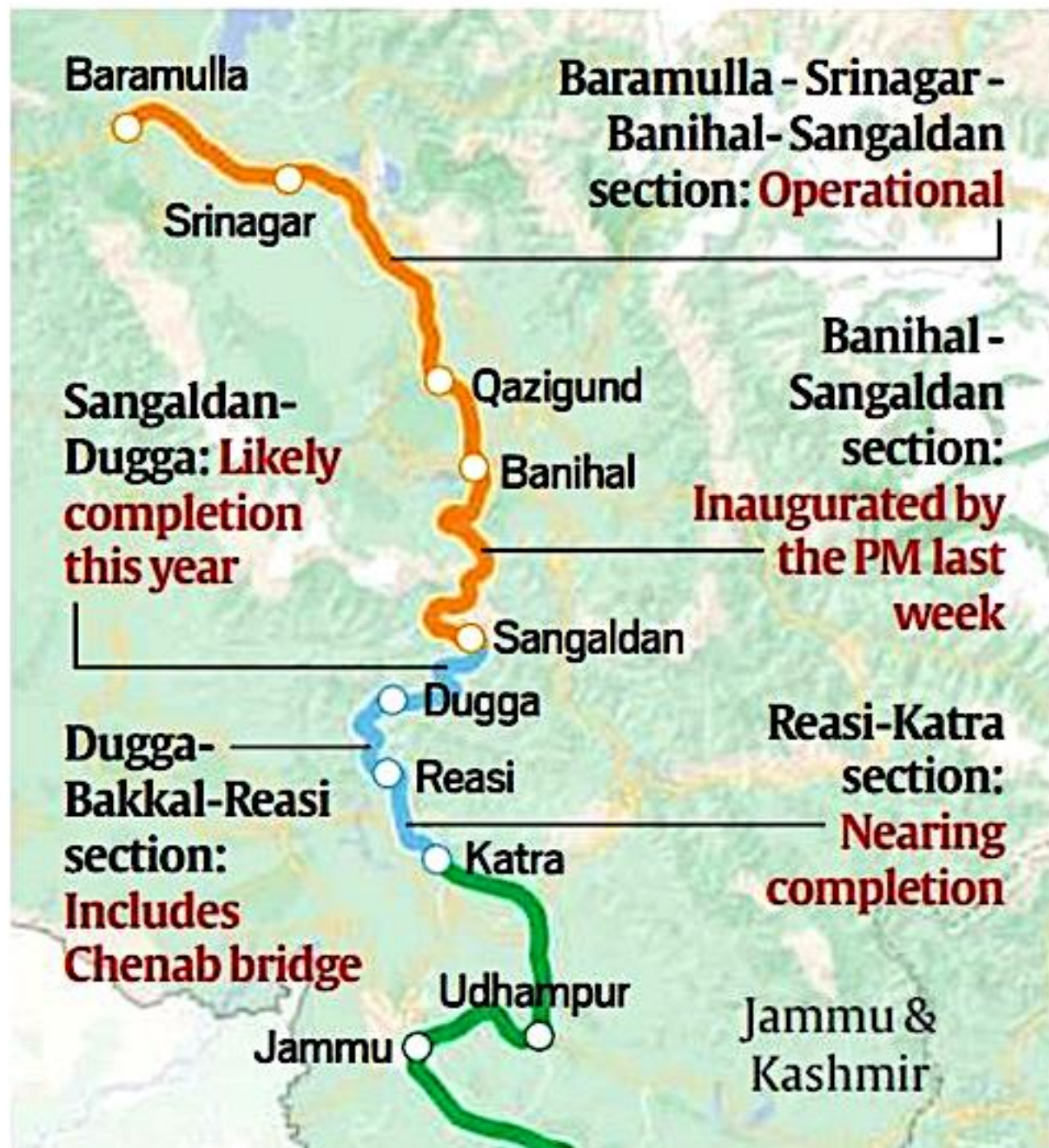
46 किमी लंबे संगलदान-रियासी रूट का 27 और 28 जून को रेलवे सेफ्टी कमिश्नर डीसी देशवाल इंस्पेक्शन करेंगे। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ PRO दीपक कुमार ने बताया कि इंस्पेक्शन तक बाकी काम पूरा हो जाएगा।



USBRL प्रोजेक्ट 1997 से शुरू हुआ था और इसके तहत 272 किमी की रेल लाइन बिछाई जानी थी। अब तक अलग-अलग फेज में 209 किमी लाइन बिछाई जा चुकी है। इस साल के अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी 17 किमी लाइन बिछाई जाएगी, जिससे एक ट्रेन कश्मीर को बाकी देश से जोड़ेगी।

48 km Sangaldan-Banihal stretch goes from 1,232 m to 1,705 m above sea level.

30 curves over 23.72 km have ensured a 0.5-1% track gradient between the two stations.

272 km Udhampur-Srinagar-Baramulla line; almost 209 km has been commissioned. 95% work complete on remaining 63 km stretch between Sangaldan and Katra. Valley likely to be linked with the Indian Railways network this summer.



 Railway Line
 Under construction



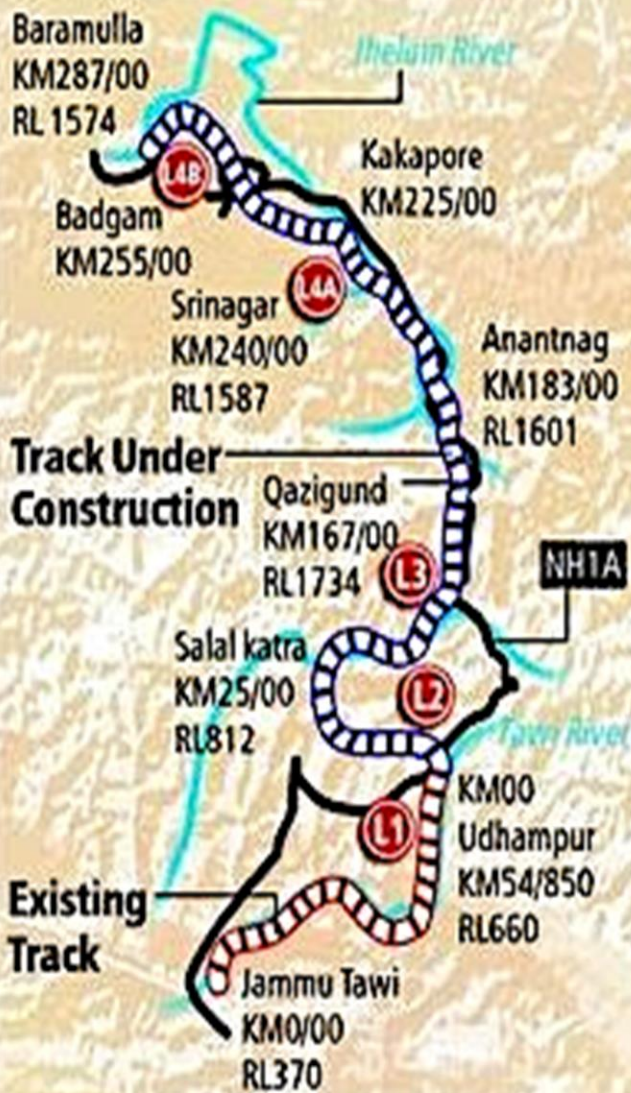
Map not to Scale

20 साल में बनकर तैयार हुआ यह ब्रिज

आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी। 22 फरवरी 2024 तक कश्मीर घाटी तक सिर्फ नेशनल हाईवे- 44 के जरिए जाया जा सकता था। बर्फबारी होने पर कश्मीर घाटी जाने वाला ये रास्ता भी बंद हो जाता था।

इसके अलावा कश्मीर जाने के लिए जम्मू-तवी तक ही ट्रेन जाती थी, जहां से करीब 350 किलोमीटर लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ता था। जवाहर टनल होते हुए गुजरने वाले इस रास्ते से लोगों को जम्मू-तवी से घाटी जाने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था।

Tracking the train



JAMMU-UDHAMPUR, 54 KM:

Line already operational

UDHAMPUR-KATRA, 25 KM:

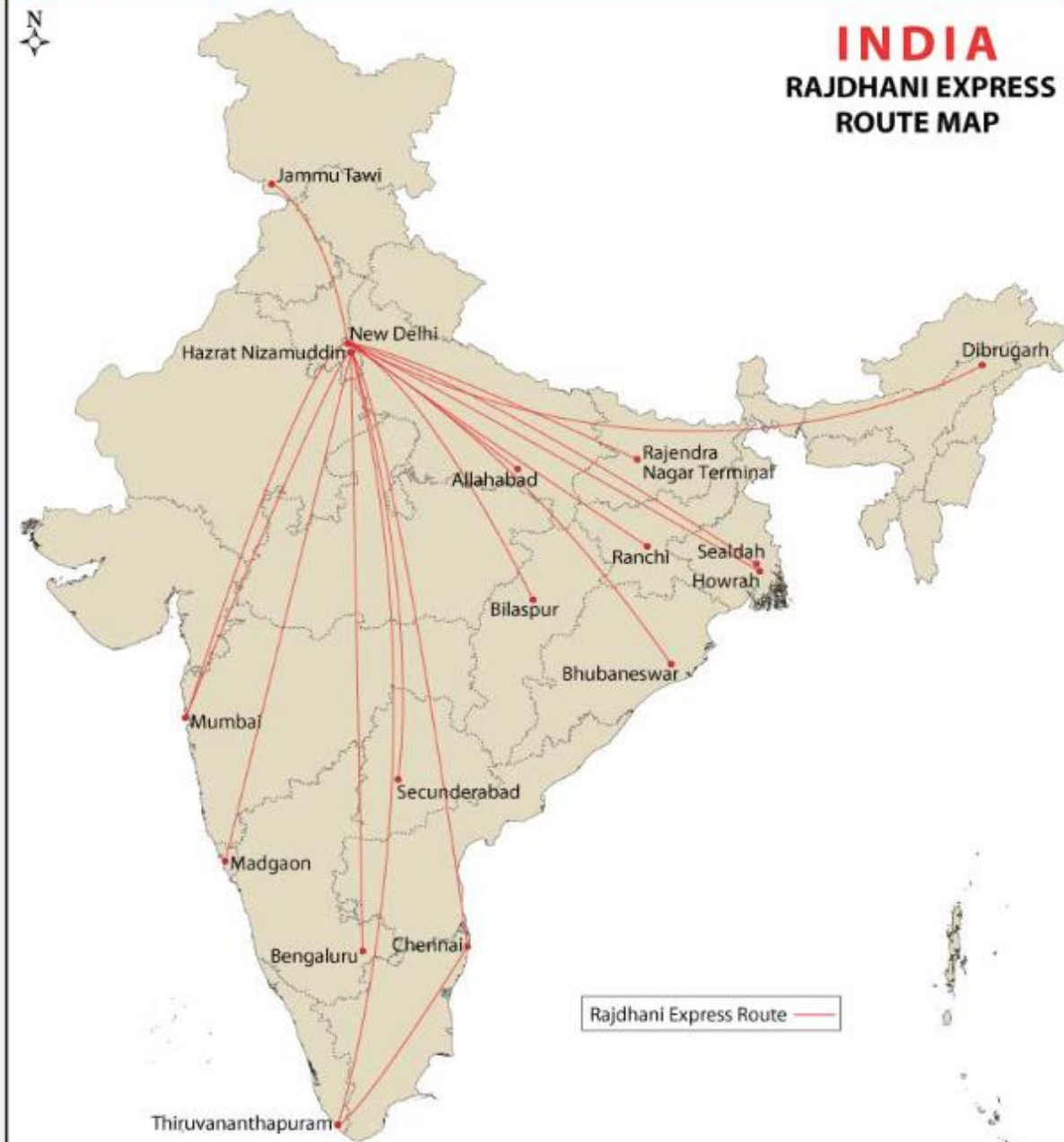
Most of the work completed but inauguration delayed because of partial collapse of an important tunnel. Was originally slated for inauguration on August 15, 2007

KATRA-QAZIGUND, 148 KM:

Work on 70-km stretch being constructed by Konkan Railways put on hold. The remaining work being done by IRCON is still on.

QAZIGUND-BARAMULLA, 119 KM:

Construction on, with work complete on more than 100 km. Inauguration of this section will see the first train coming to the Valley. Inauguration likely in a couple of months.



Rajdhani Express Route

0:30
Afghanistan

Karakoram Range

Area ceded to China
from Pakistan in 1963

China

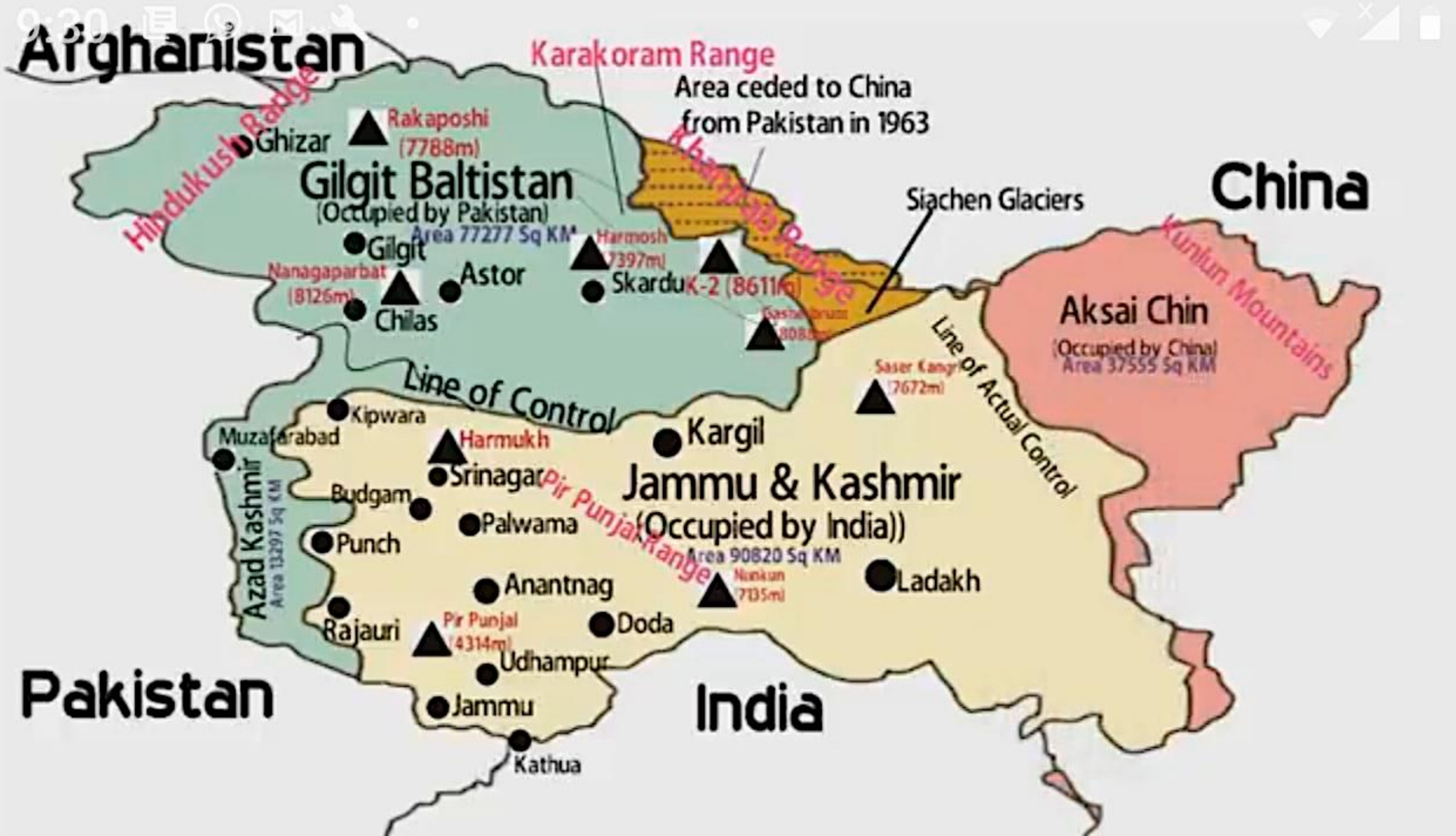
Gilgit Baltistan
(Occupied by Pakistan)
Area 77277 Sq KM

Siachen Glaciers

Aksai Chin
(Occupied by China)
Area 37555 Sq KM

Pakistan

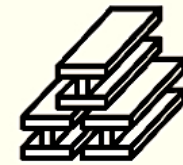
India



2003 में भारत सरकार ने सभी मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया। इसी साल सरकार ने चिनाब ब्रिज परियोजना पर मुहर भी लगा दी। 2009 तक इस ब्रिज को बनकर तैयार होना था। हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया।

अब करीब 2 दशक के बाद चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप भी झेल सकता है। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है।

17 पिलर्स पर खड़ा है चिनाब ब्रिज



25,000

मीट्रिक टन
कुल स्टील
इस्तेमाल हुआ



40

किलोग्राम तक
विस्फोटक
झेलने की क्षमता



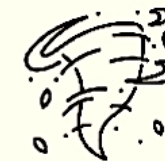
485

मीटर ब्रिज का
मेन आर्क स्पैन



133

मीटर स्टील पिलर की
अधिकतम ऊंचाई है



220

किलोमीटर/घंटा के रफ्तार वाली
हवा या आंधी को झेलने की क्षमता

Chenab Bridge

- Once completed, it will surpass the record of the *Beipan river Shuibai railway bridge (275 m)* in China.

The bridge will rise **359m** above the river bed

- Designed to withstand wind speeds of upto 260 km per hour, the 1.315 km long "*engineering marvel*" will connect Bakkal (Katra) and Kauri (Srinagar).

- The bridge forms a crucial link in the 111-km stretch between *Katra and Banihal*, which is part of the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link project.

- Slated to be completed by 2019*, it is expected to become a tourist attraction in the region.

The massive arch-shaped structure is being constructed at a cost of around

Rs 11bn

- 24,000** tonnes of steel will be used

Eifel Tower
324m

River bed

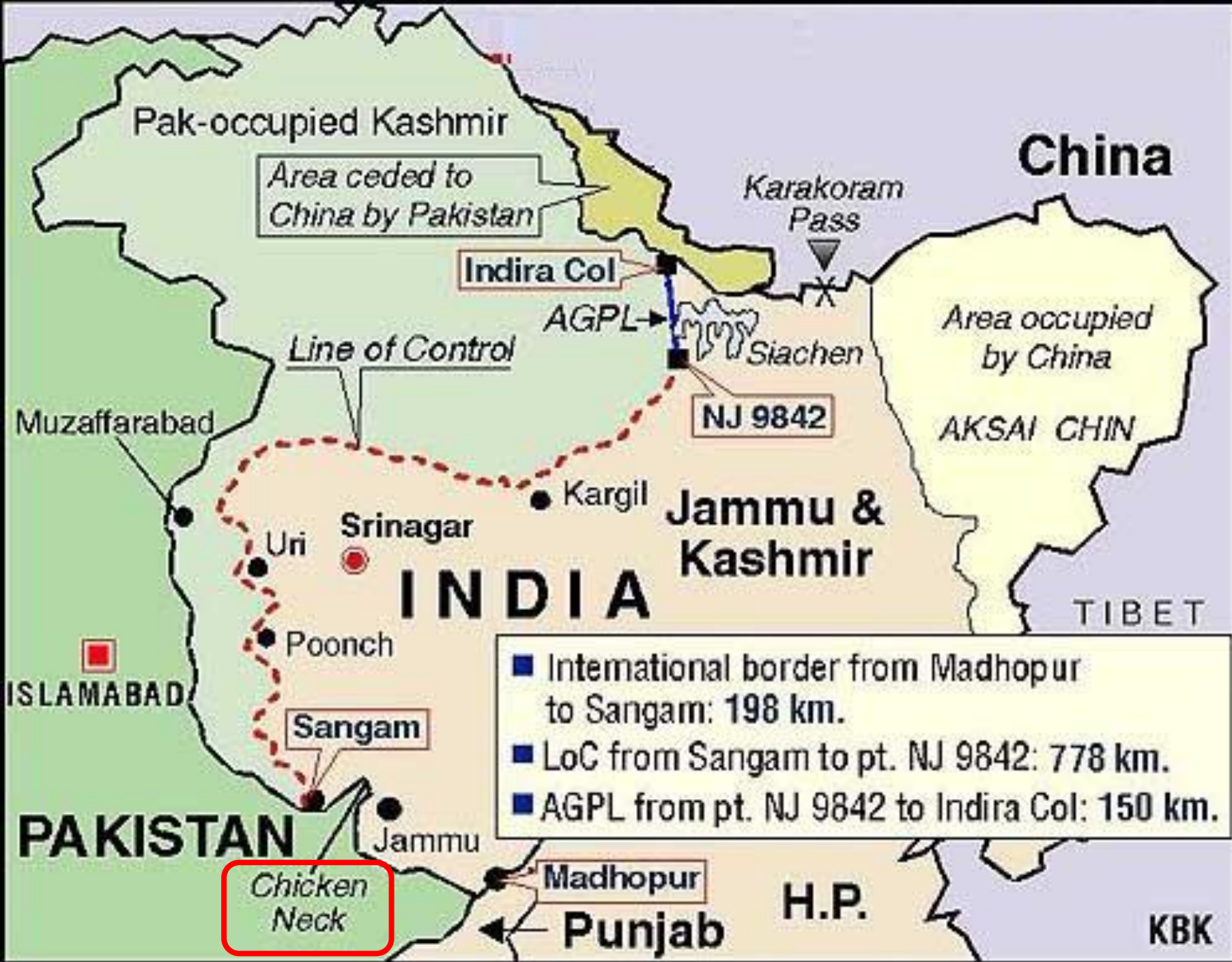


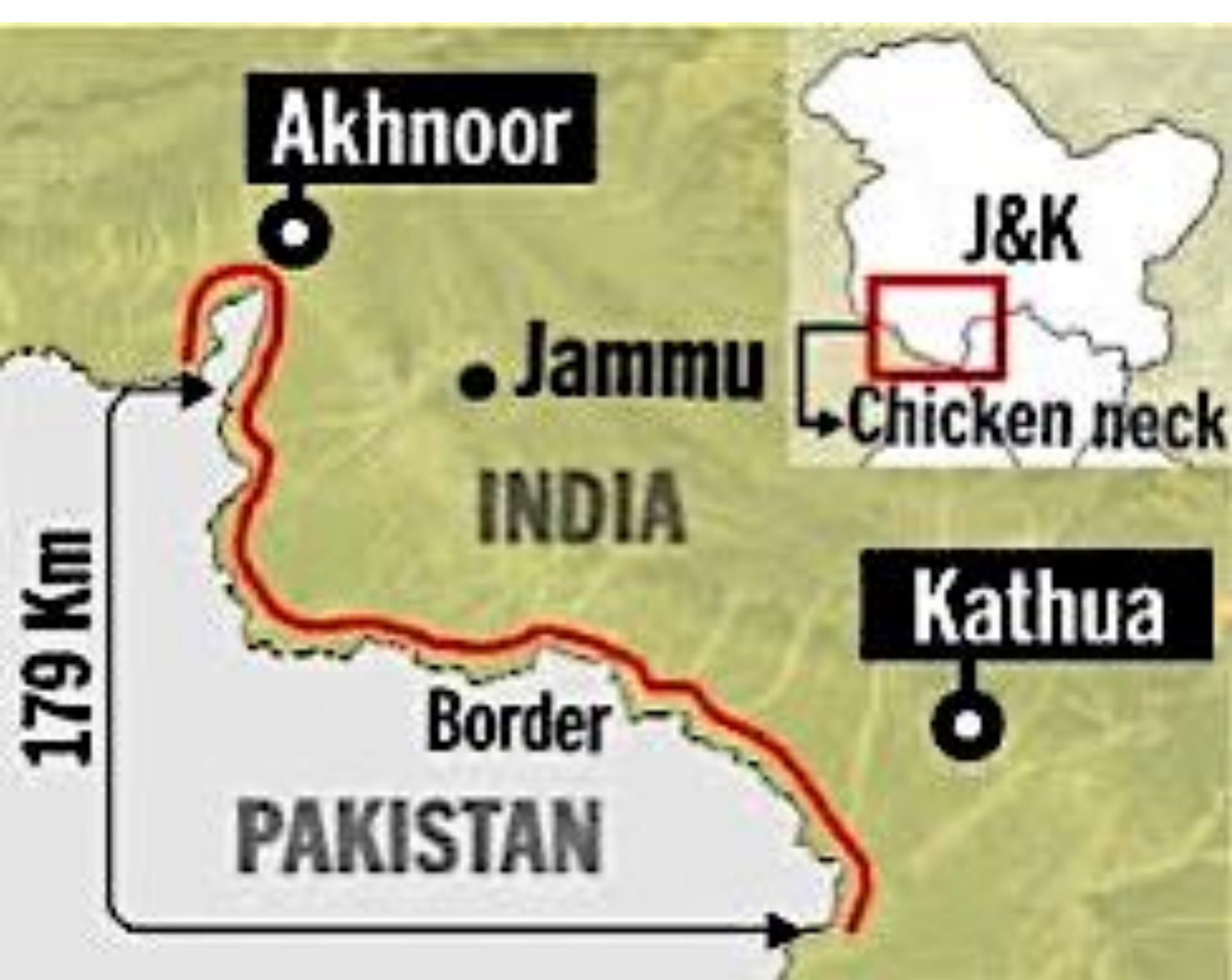
चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान और चीन की चिंता क्यों बढ़ी है?

डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी के मुताबिक चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके में बना है।

जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जहां अगर चीन का कब्जा हो जाए तो देश दो हिस्सों में टूट सकता है।

इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है। इसीलिए इस इलाके में चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर बेहद खास है। अब हर मौसम में सेना और आम लोग इस हिस्से में ट्रेन या दूसरे वाहनों से जा सकेंगे।

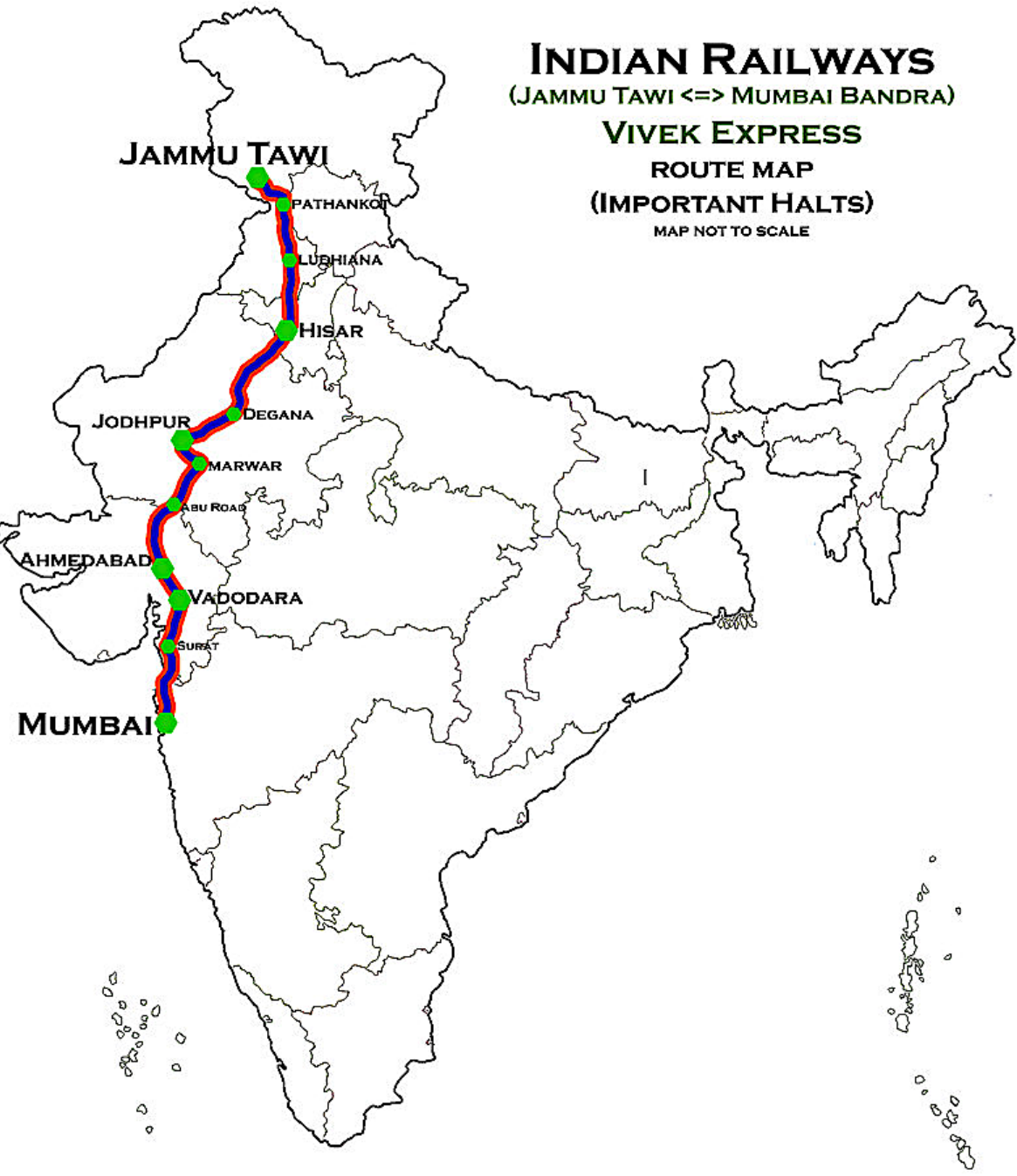




INDIAN RAILWAYS

(JAMMU TAWI <=> MUMBAI BANDRA)

VIVEK EXPRESS ROUTE MAP (IMPORTANT HALTS) MAP NOT TO SCALE





Chicken's neck or
Siliguri corridor



India and ASEAN





NCERT

FOUNDATION BATCH

EMI

OPTION AVAILABLE

OFFER PRICE
4999 Rs

Purchase Time to Pay
→ **2500 Rs**

Next Month to Pay
→ **2500 Rs**

EMI OFFER AVAILABLE FOR 24HR ONLY/-

- 1.SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
- 2.SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
- 4.SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
- 5.ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:



T&C APPLY



BY ANKIT AVASTHI SIR

LIMITED SEATS

और **EMI INFORMATION** के लिए

7878158882 अभी कॉल करें

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM





ONION



ONION



NUTRITION FACTS



Calories 40



Water 89%



Protein 1.1 gm



Carbs
9.3 gm



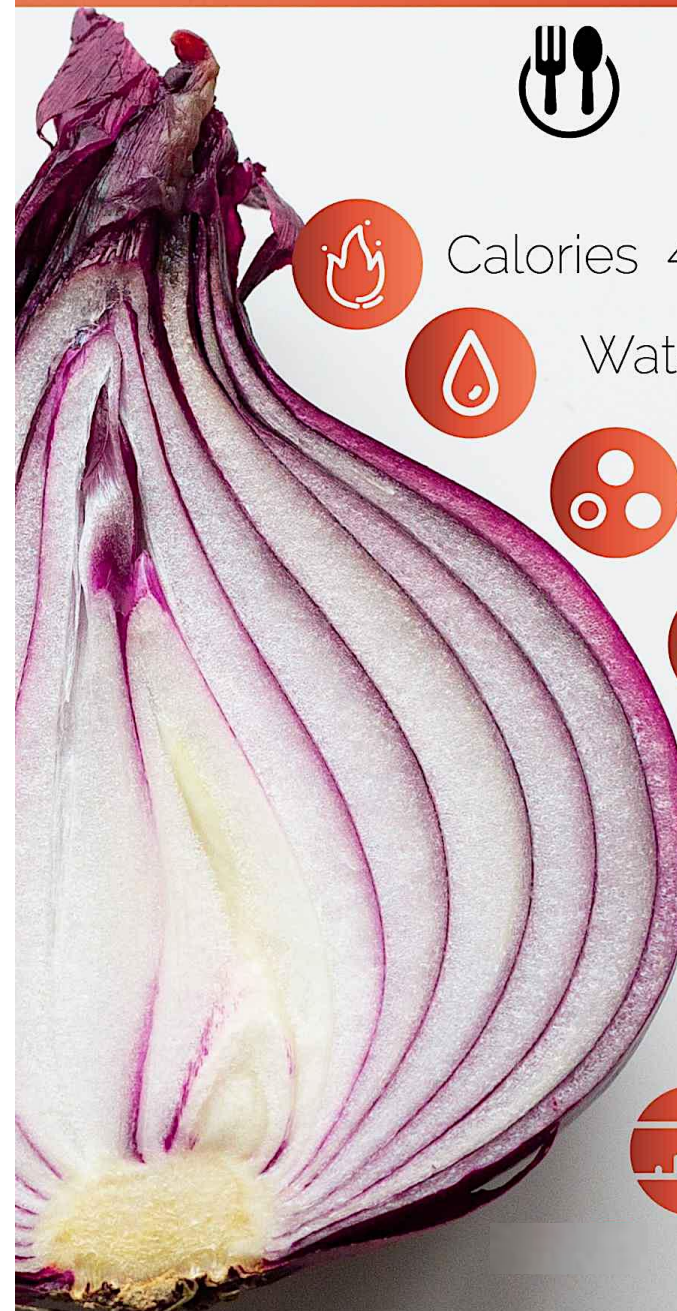
Sugar
4.2 gm



Fiber
1.7 gm



Fat
0.1 gm



Govt buys 71,000 tons of onion for buffer stock; expects retail prices to ease with normal monsoon

New Delhi | June 22, 2024 17:44 IST

The government will exercise the option of holding or releasing onions from the buffer in order to maintain stability in prices of onion

The Indian EXPRESS

er Leak Row >>> NTA Director General Subodh Kumar Singh removed; Pradeep Singh Kharola appointed new

Govt buys 71,000 tonnes of onion for buffer stock; expects retail prices to ease with normal monsoon

Updated: Jun 22, 2024, 04:02:00 PM IST

THE ECONOMIC TIMES

NDTV

LIVE TV

LATEST

INDIA

VIDEO

ELECTIONS

OPINION

CITIES

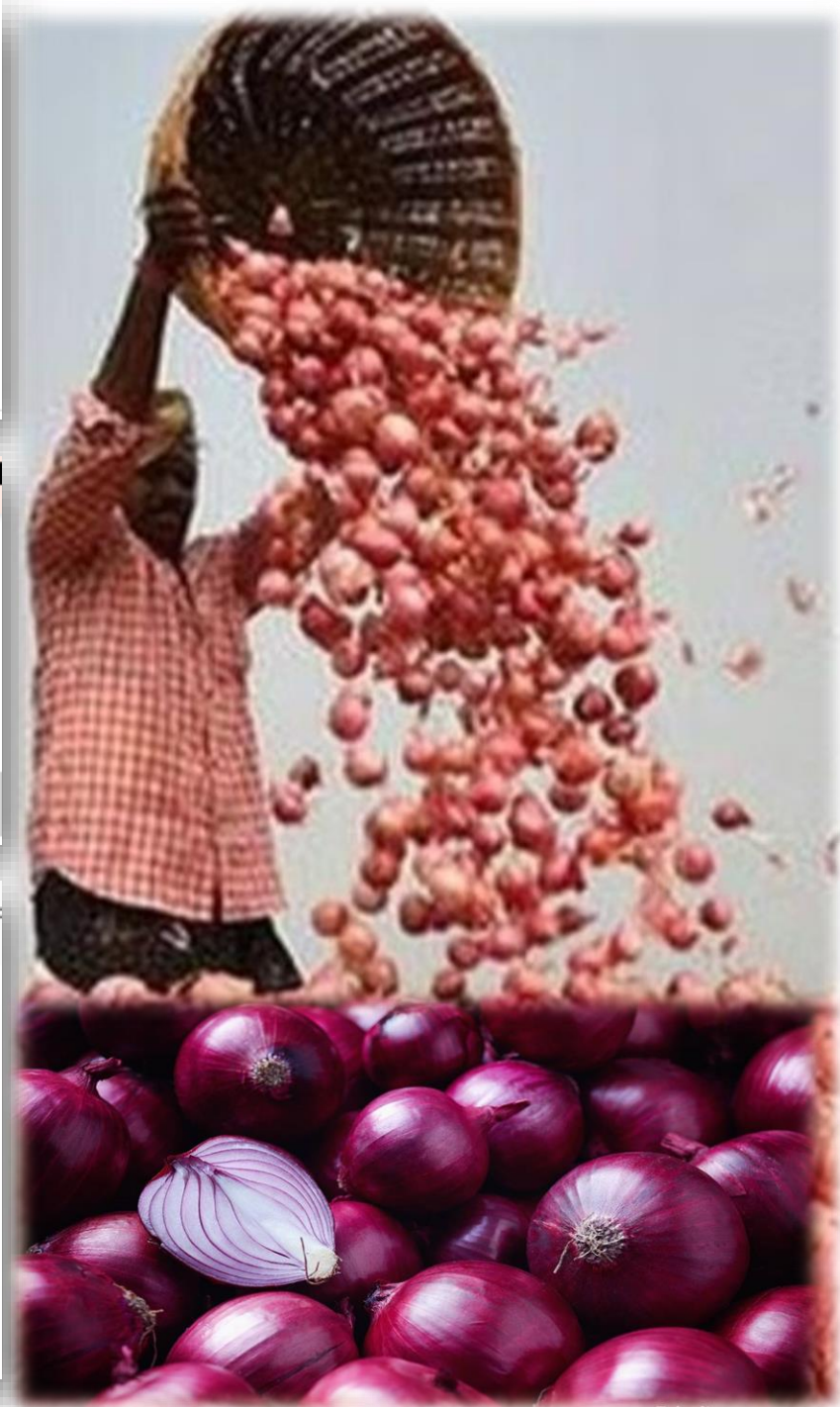
WEB STORIES

OFFBEAT

Centre Buys 71,000 Tonnes Of Onion For Buffer Stock, Expects Retail Prices To Ease

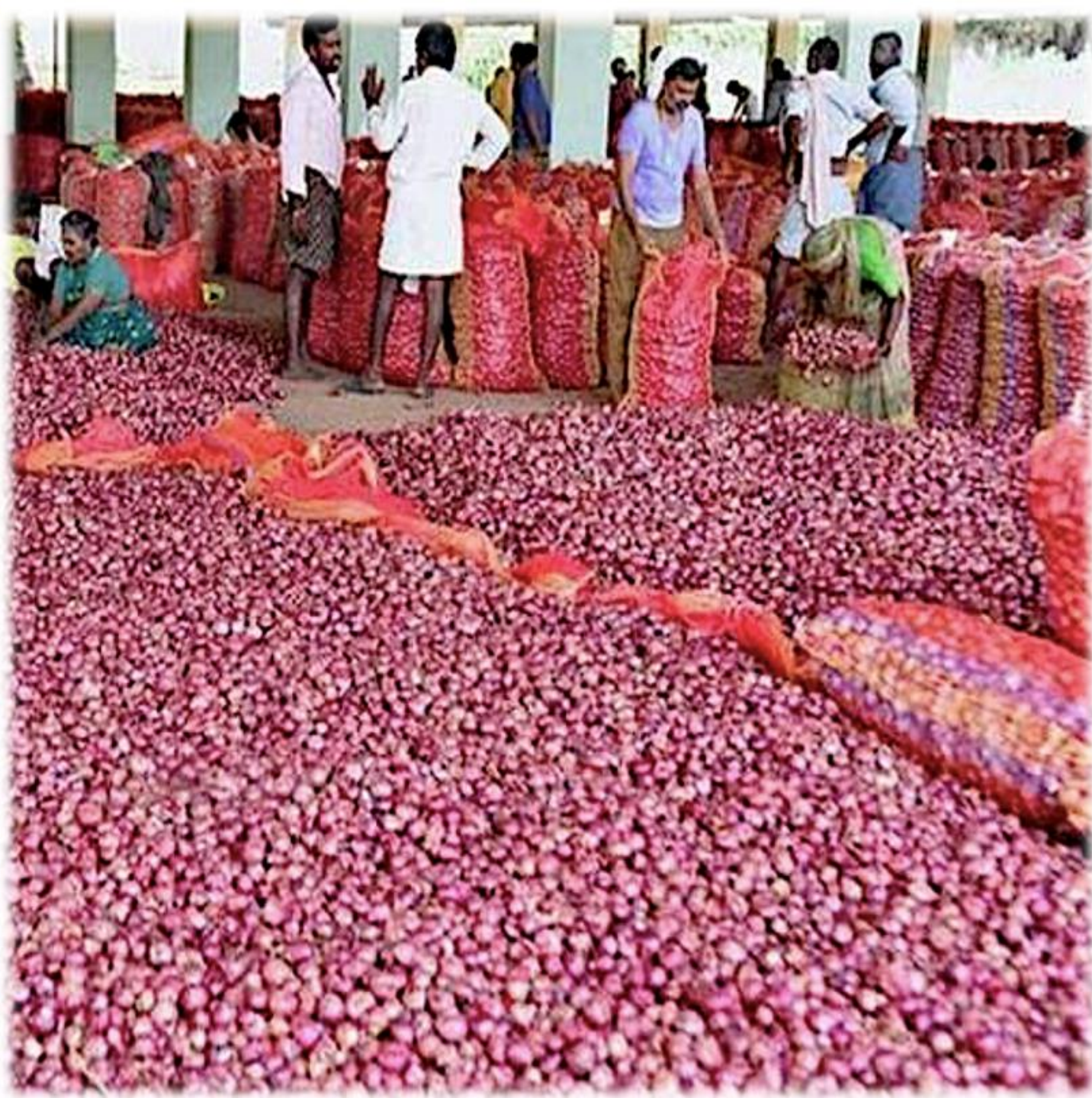
According to data compiled by the department of consumer affairs, the all-India average onion retail price stood at ₹ 38.67 per kg on Friday, while the modal price was ₹ 40 per kg.

Business News | Press Trust of India | Updated: June 22, 2024 4:56 pm IST



केंद्र सरकार ने इस साल अब तक बफर स्टॉक के लिए लगभग 71,000 टन प्याज खरीदा है। प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कीमतों में स्थिरता के लिए सरकार ने टोटल टारगेट 5 लाख टन प्याज खरीदने का रखा है।

सरकार को उम्मीद है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल/खुदरा कीमतों में कमी आएगी।





ET

**'GOVT HAS 5 LAKH METRIC
TONNES OF ONIONS STOCK'**



All Ministry

22 June 2024

President's Secretariat

- [PRIME MINISTER OF BANGLADESH CALLS ON THE PRESIDENT](#)

Prime Minister's Office

- [Gujarat CM meets PM](#)
- [Prime Minister Narendra Modi pays tribute on birth anniversary of Sant Kabir Das](#)
- [Prime Minister condoles the demise of Acharya Laxmikant Dixit](#)
- [Press statement of Prime Minister Shri Narendra Modi during the visit of Prime Minister of Bangladesh to India](#)

AYUSH

- [CCRAS to Organize Landmark National Consultative Meet on "Research Priority](#)

Onion buffer enhanced from 3 lakh MT to 5 lakh MT

From tomorrow (Monday) NCCF will sell onions at retail price of Rs 25 per kg

Posted On: 20 AUG 2023 2:56PM by PIB Delhi

In an unprecedented move the Government raised the quantum of onion buffer to 5.00 lakh metric tonne this year, after achieving the initial procurement target of 3.00 lakh metric tonne. In this regard, the Department of Consumer Affairs has directed NCCF and NAFED to procure 1.00 lakh tonne each to achieve the additional procurement target alongside calibrated disposal of the procured stocks in major consumption centres.

Disposal of onions from the buffer has commenced, targeting major markets in States and UTs where retail prices are above the all-India average and/or are significantly higher than the previous month. As on date, about 1,400 MT of onions from the buffer has been dispatched to the targeted markets and are being continuously released to augment the availability.

Apart from releasing in major markets, onions from the buffer are also being made available to retail consumers at a subsidized rate of Rs.25/- per kg through retail outlets and mobile vans of NCCF from tomorrow ie Monday 21st August 2023. Retail sale of onion will be suitably enhanced in coming days by involving other agencies and e-commerce platforms.

औसत प्याज खुदरा मूल्य 38.67 रुपये किलो

उपभोक्ता मामलों के विभाग के डेटा के मुताबिक, शुक्रवार (21 June) को देशभर में औसत प्याज खुदरा मूल्य 38.67 रुपये प्रति किलो था, जबकि मॉडल मूल्य 40 रुपये प्रति किलो था।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 20 जून तक केंद्र ने 70,987 टन प्याज खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 74,071 टन प्याज खरीदा गया था।

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Government ministry :



The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is a government ministry of India. The ministry is headed by a Cabinet rank minister.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है। कैबिनेट स्तर का मंत्री इसका संचालन करता है। वर्तमान में [पीयूष गोयला|पीयूष गोयला]] इसके मंत्री है और राज्य मंत्री सी०आर० चौधरी है।

Officeholder: C. R. Chaudhary (Minister of State)

Founded: 2 September 1946

Jurisdiction: Government of India

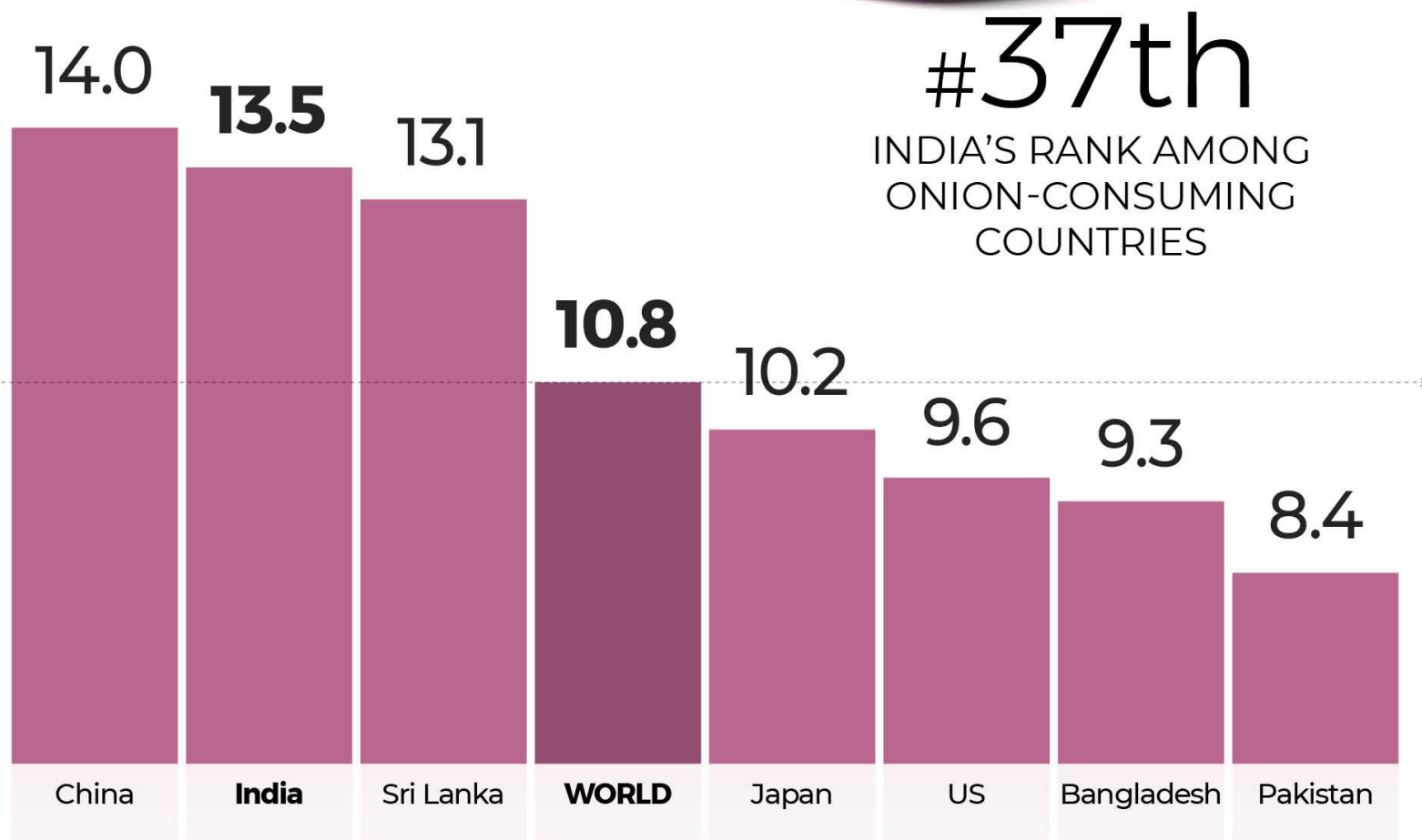
ONION CONSUMPTION

INDIA VS PEERS



Onion consumed per capita per year

KILOGRAM



#37th

INDIA'S RANK AMONG
ONION-CONSUMING
COUNTRIES

LAYERS OF THE INDIAN ONION



- India produces tens of millions of metric tons of onions annually.
- Over the past decade, India has seen an increase in onion production.
- Weather fluctuations and market dynamics can cause significant variations in production.

- The exact figure fluctuates from year to year due to several factors.
- Driven by advances in agricultural technology, improved irrigation, and expanded cultivation areas.



STATES WITH HIGH ONION CULTIVATION

Maharashtra



Leads in onion production in India, accounting for a large share of the country's output.

Karnataka



Known for its onion cultivation, especially in regions like Dharwad and Gadag.

Madhya Pradesh



A growing onion-producing region with districts like Indore and Ujjain.

Gujarat



Important for its onion production, with districts like Bhavnagar and Rajkot.

Rajasthan



A significant producer with districts like Sikar and Alwar.



ONION CULTIVATION SEASONS

KHARIF SEASON

Sown with the onset of the monsoon (**June-July**) and harvested in the autumn (**September-October**). These onions often have a shorter shelf life.

RABI SEASON

Sown in winter (**October-November**) and harvested in early spring (**February-April**). Rabi onions are generally better for storage and have a longer shelf life.)

सरकार ने पिछले साल इसी अवधि में 74,071

टन प्याज खरीदा था

डिपार्टमेंट के एक सिनियर ऑफिशियल ने बताया कि 20 जून तक केंद्र सरकार ने 70,987 टन प्याज खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 74,071 टन प्याज खरीदा गया था।

ऑफिशियल ने कहा, 'इस साल प्राइस स्टेबलाइजेशन बफर के लिए प्याज खरीदने की गति पिछले साल के समान ही है। हालांकि, रबी प्रोडक्शन में लगभग 20% की गिरावट आई है।'

67% RISE IN A FORTNIGHT



* Mahuva is biggest wholesale market for onions

“ We can't remove onions from our dishes as it is the base ingredient. We have to absorb the higher cost and bear the loss. We can't increase prices as the industry is already in a difficult phase”
Rohit Khanna
PROMOTER OF A RESTAURANT



“ The increase in onion prices is affecting the budget of housewives. Not just onions, prices of several other vegetables are very high. Earlier, I used to pay Rs 200 for vegetables for three days, now this is costing Rs 350-400”
Nimisha Vaishna
HOUSEWIFE



BULK OF INDIA'S ONION EXPORT TO BANGLADESH AND MALAYSIA

EXPORT OF ONIONS FROM INDIA TO TOP COUNTRIES IN 2020. RISING DOMESTIC PRICES HAS PROMPTED THE CENTRE TO BAN EXPORTS NOW, WITH THE EXCEPTION OF BANGLADESH

(In 1,000 metric tons)

BANGLADESH	259.37
MALAYSIA	190.69
UAE	152.53
SRI LANKA	125.79
NEPAL	75.19
SAUDI ARABIA	54.86
QATAR	42.3
OMAN	39.74
KUWAIT	38.64
INDONESIA	35.59



As of August 2020
Source: DGCI&S, APEDA



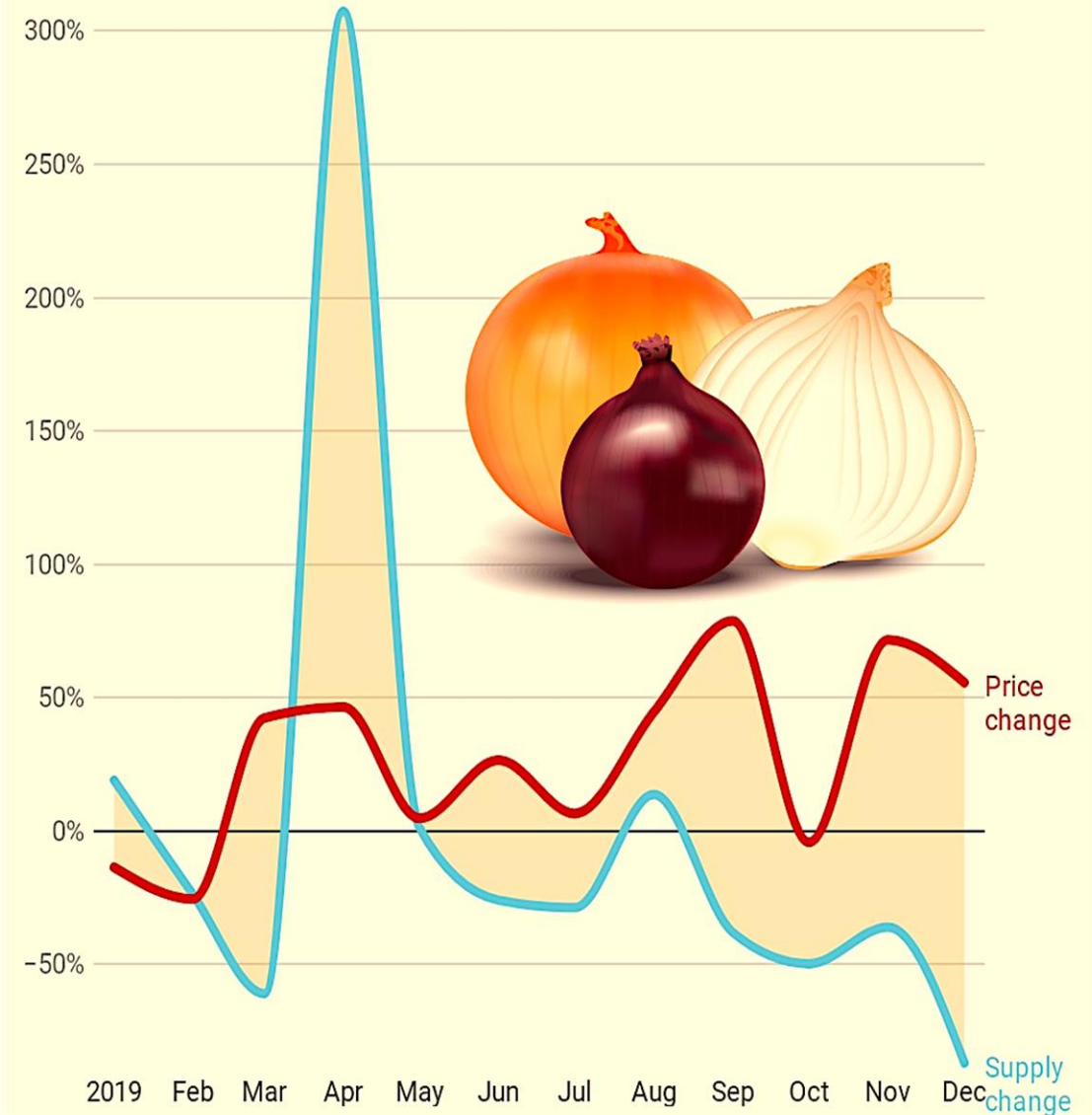
5 लाख टन की खरीद का टारगेट प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार

ऑफिशियल ने कहा कि सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए 5 लाख टन की खरीद का टारगेट प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार बफर स्टॉक से प्याज को रखने या जारी करने का विकल्प अपनाएगी। प्याज का खरीद मूल्य बदलता रहता है, जो मौजूदा मार्केट प्राइस से जुड़ा होता है।

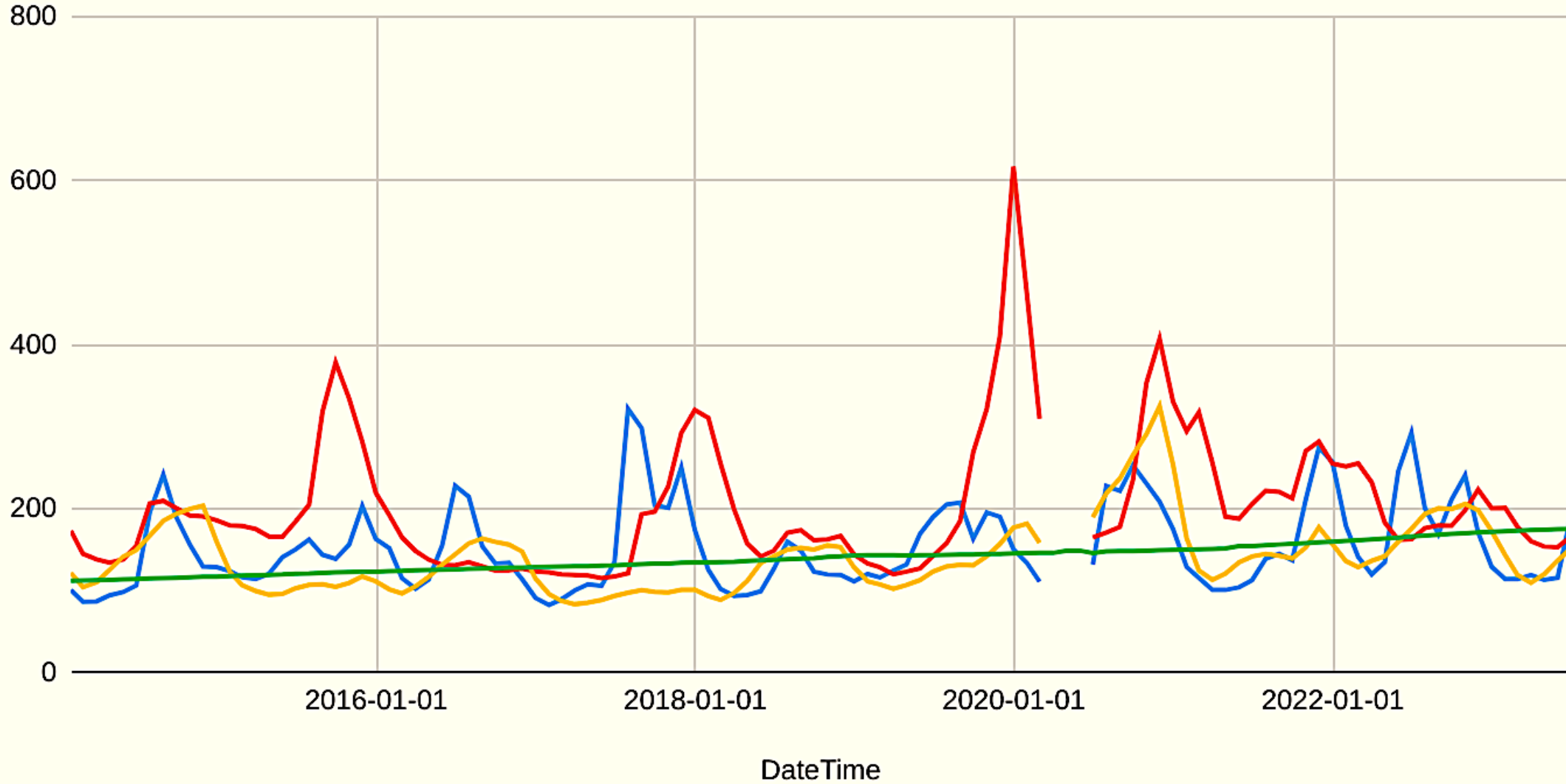
Why onion prices hit eye-watering levels?

Percentage change in onion prices over 12 months



CPI - Tomato, Onion, Potato and Household

Tomato Onion Potato Household



ONION PRODUCTION VS IMPORTS



Production up
by **11.74** lakh
tonnes in past
3 years



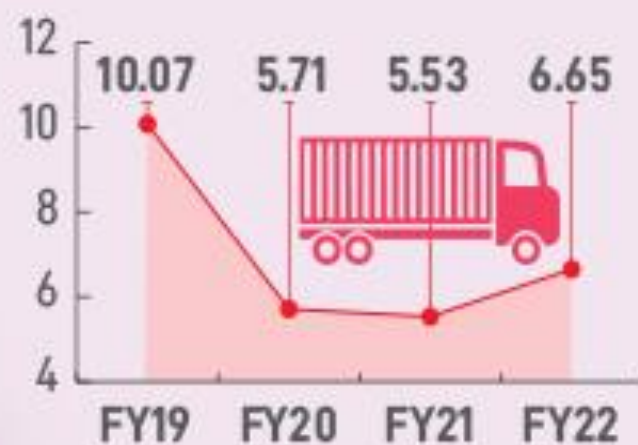
2.592 lakh
hectares of
land used for
cultivation
in **FY22**



Production in lakh tonnes



Import in lakh tonnes



कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही

कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार पिछले साल अगस्त से चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही है। जिसकी शुरुआत 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी से हुई। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) को 800 डॉलर प्रति टन किया गया। वहीं 8 दिसंबर 2023 से प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन उपायों से प्याज की घरेलू उपलब्धता को स्थिर कीमतों पर बनाए रखने में मदद मिली है।

महाराष्ट्र में लासलगांव जैसी प्रमुख मंडियों में पर्याप्त स्थिरता और इस साल सामान्य से ज्यादा मानसून की भविष्यवाणी के आधार पर अच्छे खरीफ उत्पादन की संभावना को देखते हुए 4 मई 2024 से प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटा लिया गया था और 550 डॉलर प्रति टन MEP और 40% निर्यात शुल्क लगाया गया था।

MINIMUM EXPORT PRICE

- **Minimum Export Price (MEP) is the price below which an exporter is not allowed to export the commodity from India.**
- **This measure is implemented when domestic retail or wholesale prices are increasing or when there are production issues. It acts as a quantitative restriction on trade.**
- **The government sets the Minimum Export Price (MEP) for certain commodities to control domestic price increases and ensure sufficient domestic supply.**



नासिक की लासलगांव प्याज मंडी यहीं से दाम में होता है उतार-चढ़ाव



लासलगांव, नासिक प्याज मंडी

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लासलगांव, जि. नासिक
छत्रपती शिवाजी महाराज स्वतंत्र कांदा बाजार आवार, लासलगांव



India's Top Export Destinations of Onions



भीषण गर्मी के कारण हरी सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ

अधिकारी ने कहा, 'देश के बड़े हिस्से में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी के कारण हरी सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

इसके अलावा टमाटर, आलू और प्याज सहित कई सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है।' उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।



IMD की चेतावनी और पूरे देश को झुलसाएगी गर्मी...

जानिए कैसे करे बचाव ?

by Ankit Avasthi Sir



10:09

IMD की चेतावनी और पूरे देश को झुलसाएगी गर्मी... जानिए कैसे करे बचाव? by Ankit Avasthi Sir

454K views • Streamed 2 months ago

Apni Pathshala

IMD की चेतावनी और पूरे देश को झुलसाएगी गर्मी... जानिए कैसे करे बचाव? by ...

WATCH THE RETAIL RATE SPIKE



Onion

MONTH	WHOLESALE
August	18-22
September	10-17
October	35-50
November	35-40

Current retail price

₹ 55-60

Potato

MONTH	WHOLESALE
August	5-7
September	5-8
October	6-7
November	12-13

Current retail price

₹ 25-30

Tomato

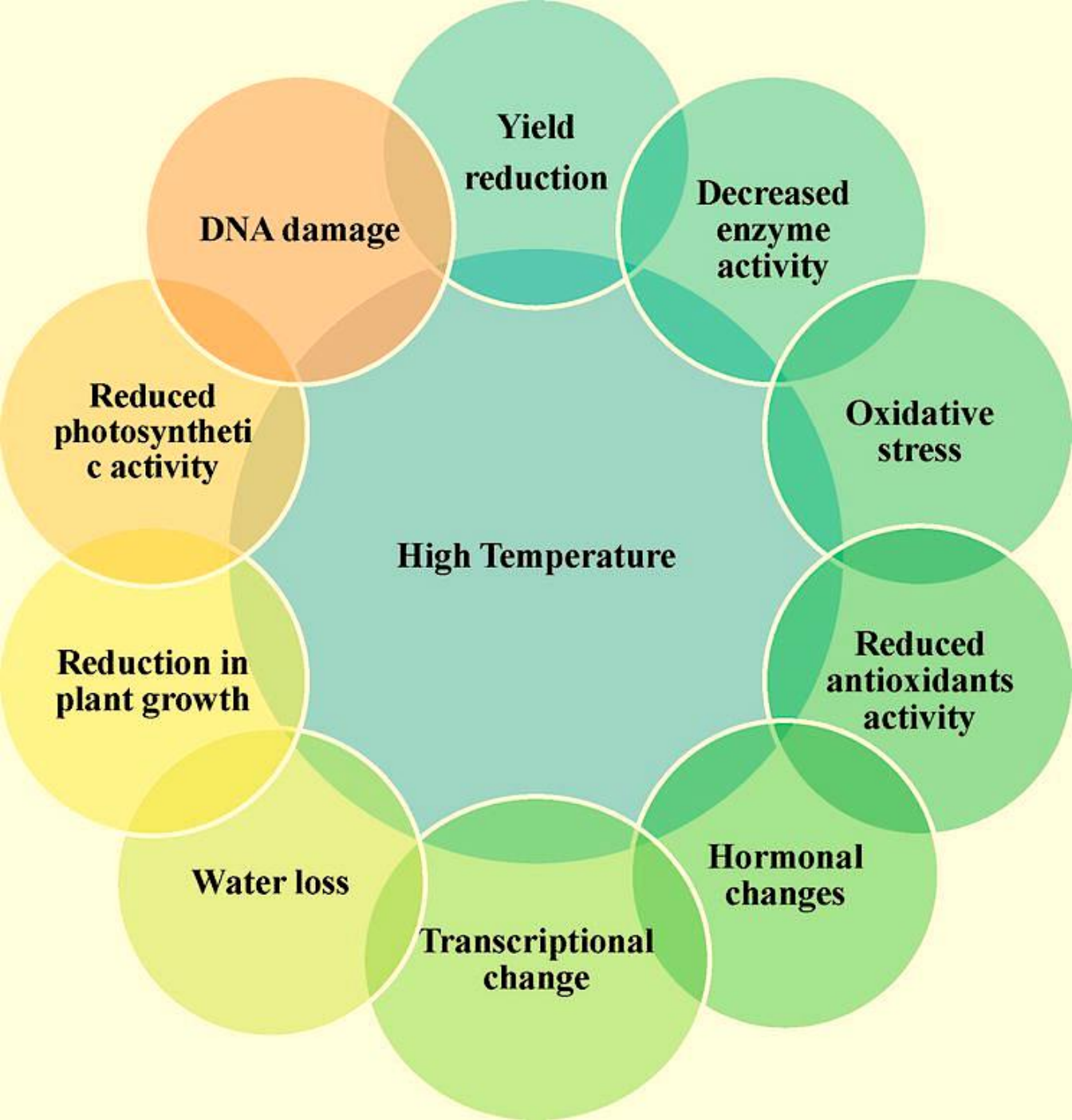
MONTH	WHOLESALE	MONTH	WHOLESALE
August	30-40	October	35-50
September	15-18	November	35-40

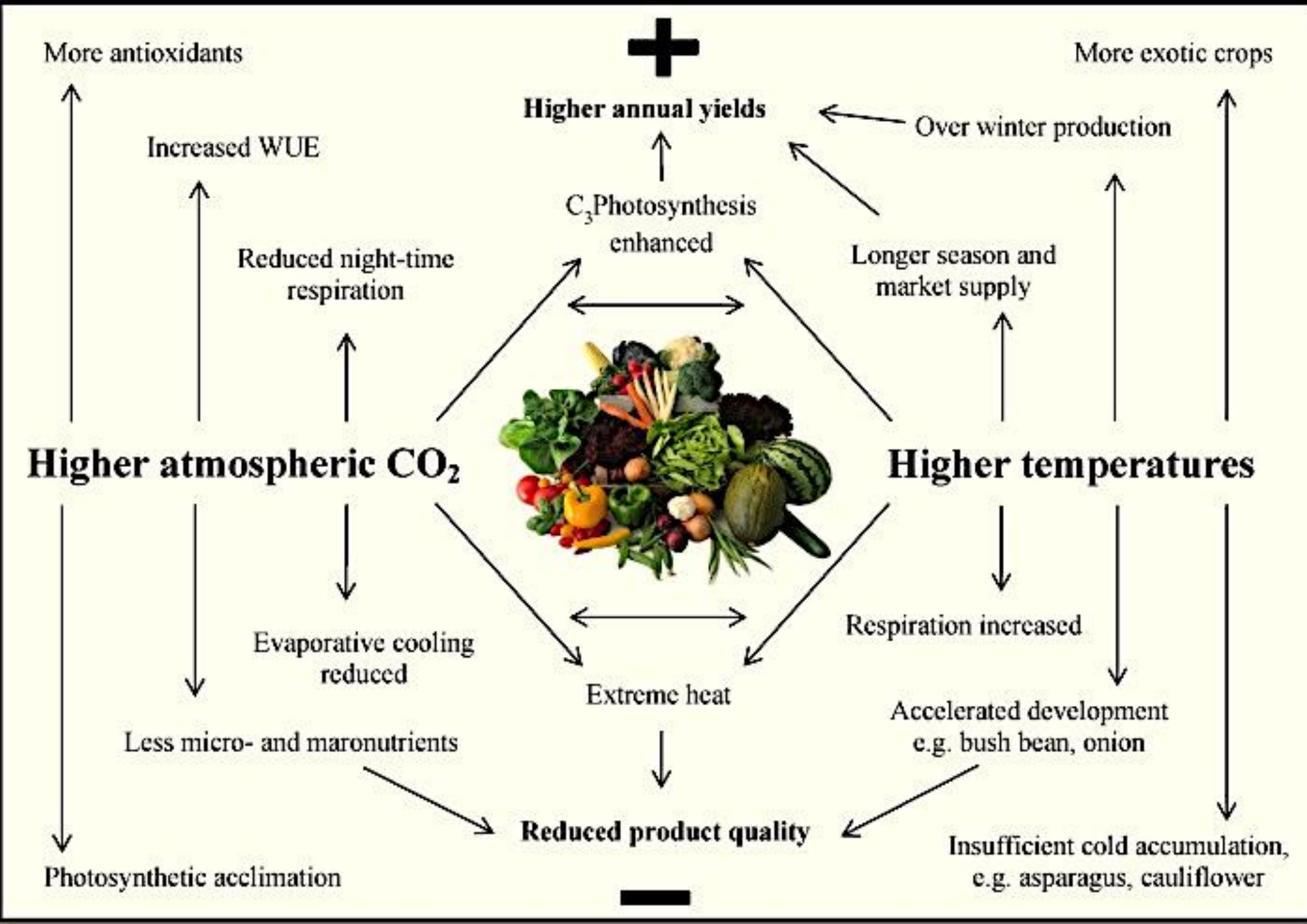
Current retail price | ₹ 60-80



Heat Causes Problems







Top stories :

IMD on heatwave conditions in India >



The Indian Express

IMD warns of heatwave spells lasting 10-20 days in April-June

8 hours ago

India Today

More heatwave days, above-normal temperatures likely in India in April-June



7 hours ago

Hindustan Times

India to witness heatwave conditions during LS poll season, says IMD | 10...

7 hours ago



Times of India

India set to face extreme weather conditions between April-June

8 hours ago



Business Today

Summer is becoming hotter: IMD predicts above-normal temperatures, longer...

6 hours ago



2:38 / 10:08

Pause, Closed Captions, Settings, Full Screen, and other video controls.



IMD की चेतावनी और पूरे देश को झुलसाएगी गर्मी... जानिए कैसे करे बचाव? by Ankit Avasthi Sir

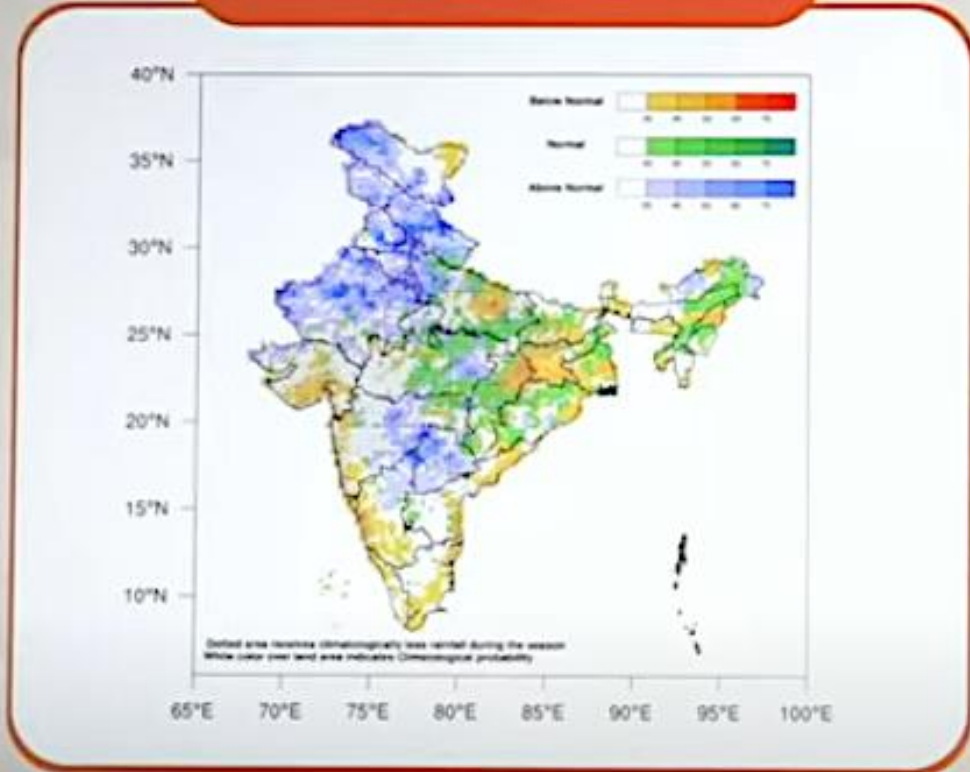


अप्रैल 2024 के लिए संभावित वर्षा का पूर्वानुमान

Issue Date
01-04-24



India Meteorological Department ...
@Indiametdept



पूर्वानुमान से पता चलता है कि उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के कई हिस्सों, उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी तटों, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम मध्य भारत में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है।

Updated Seasonal outlook for hot weather season (April 2024) and Monthly Outlook for Rainfall / ग्रीष्म ऋतु 2024 के लिए अद्यतन पूर्वानुमान और वर्षा के लिए अप्रैल 2024 का आउटलुक 1/5

6:06 PM - Apr 1, 2024



5:19 / 10:08

@Indiametdept

IMD की चेतावनी और पूरे देश को झुलसाएगी गर्मी... जानिए कैसे करे बचाव? by Ankit Avasthi Sir

क्या सच में तापमान 50°C से कम है ?

सरकार कैसे
नापती है तापमान ?
by Ankit Avasthi Sir



क्या सच में तापमान 50°C से कम है ? सरकार कैसे नापती है तापमान ? by Ankit Avasthi Sir #heatwavealert

401K views • 3 weeks ago

Apni Pathshala

क्या सच में तापमान 50°C से कम है ? सरकार कैसे नापती है तापमान ? by Ankit Avasthi ...

बफर स्टॉक का कब इस्तेमाल होगा?

अगर प्याज के भाव में एकाएक बड़ी तेजी आती है, तो उसे संभालने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज जारी करने का विकल्प आजमाएगी। सरकारी अधिकारी का कहना है कि प्याज की कीमतों में वृद्धि 2023-24 में खरीफ, देर खरीफ और रबी में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की कमी के कारण है, क्योंकि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश हुई है।

सरकार प्याज के भाव को नियंत्रित करने के लिए पिछले साल अगस्त से चरणबद्ध तरीके से उपाय कर रही है। इन उपायों से प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ कीमतों को ज्यादा बढ़ने से रोकने में मदद मिली है।

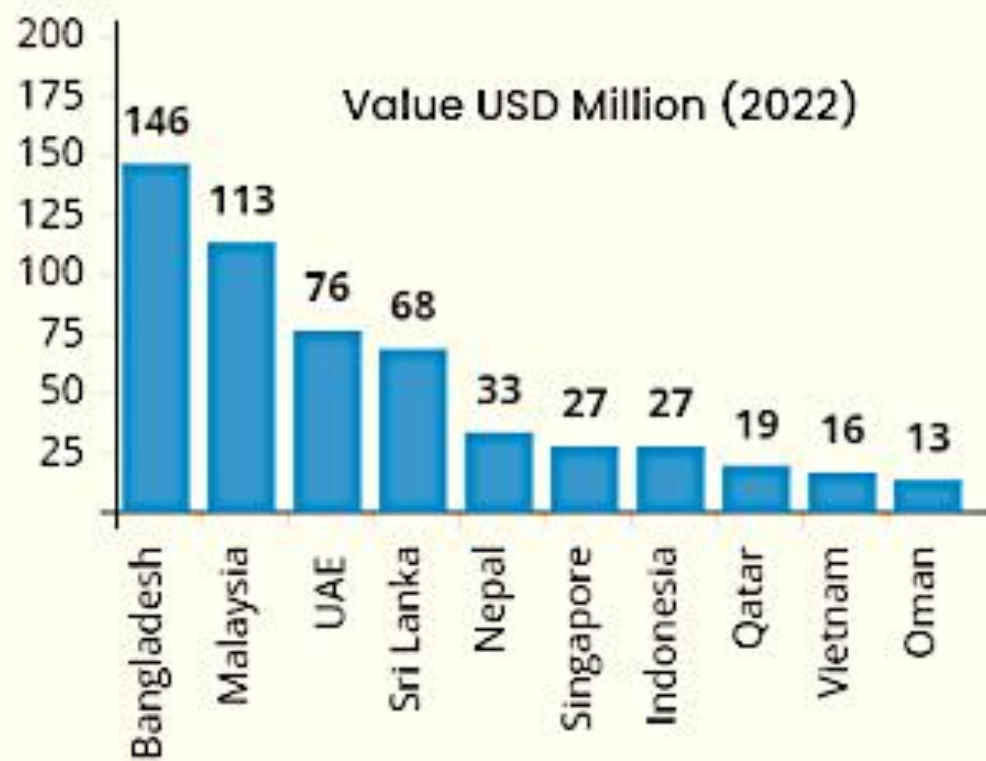


2023-24 में प्याज उत्पादन 254.73 लाख टन होने की उम्मीद

मार्च में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्याज उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे। **आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 (फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स) में प्याज उत्पादन लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल लगभग 302.08 लाख टन उत्पादन हुआ था।**

आंकड़ों के अनुसार, ऐसा महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में 3.12 लाख टन उत्पादन में कमी के कारण हुआ है।

India's Top Export Destinations of Onions



मानसून से होगा स्थिति में सुधार

अधिकारी ने कहा, "देश के बड़े हिस्से में अत्यधिक गर्मी से हरी सब्जियों का उत्पादन घटा है। इसका असर सब्जियों की कीमतों पर भी दिख रहा है।

टमाटर, आलू और प्याज सहित सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है।" उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

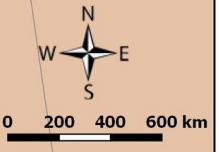
Will the Indian Monsoon in 2024 Be the Monsoon of Hopes?

Indian agriculture system Completely depending on Mansoon

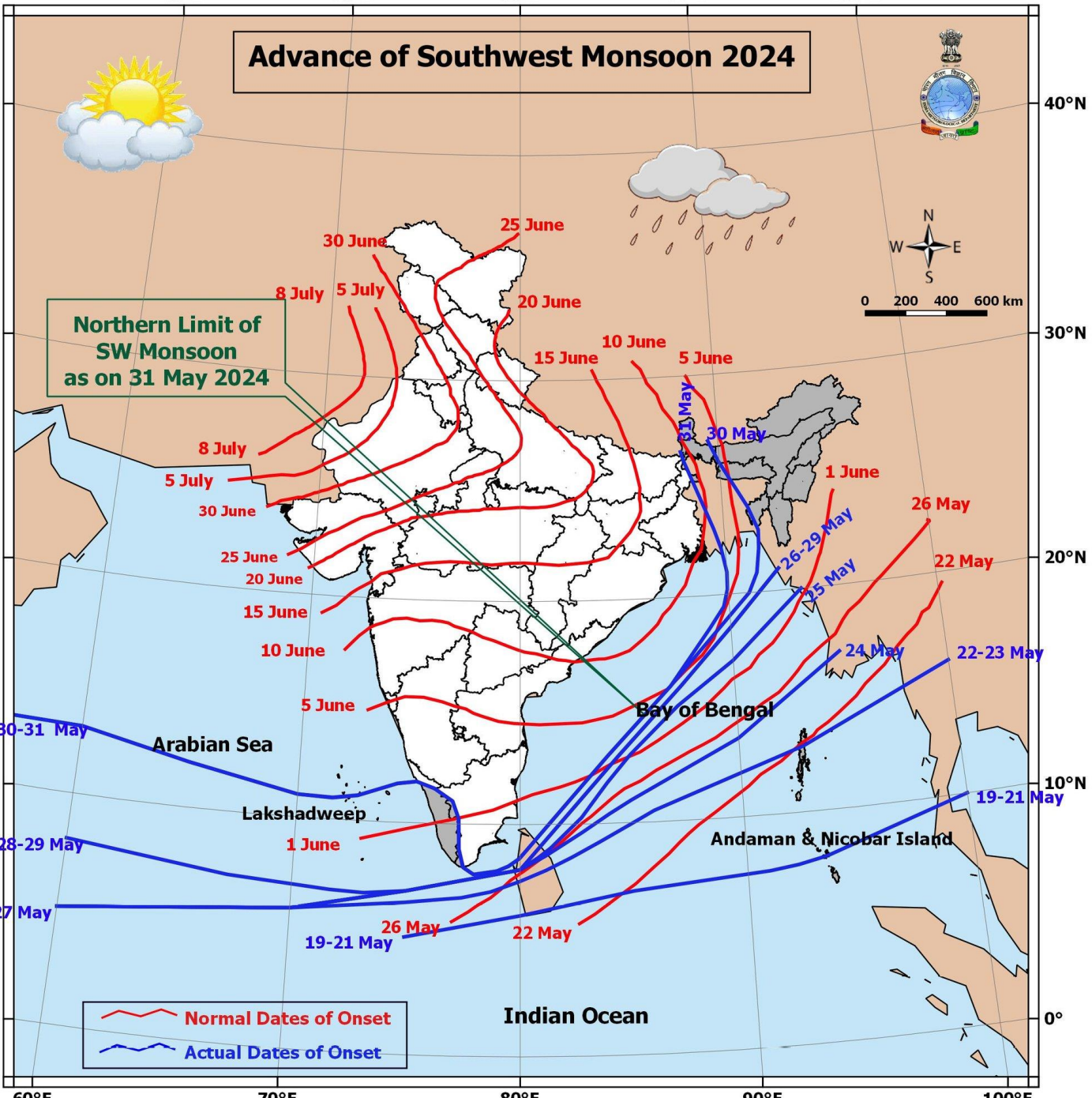
Advance of Southwest Monsoon 2024



Northern Limit of SW Monsoon as on 31 May 2024



Normal Dates of Onset
 Actual Dates of Onset



SUBSCRIBED





NCERT

FOUNDATION BATCH

EMI

OPTION AVAILABLE

OFFER PRICE
4999 Rs

Purchase Time to Pay
→ **2500 Rs**

Next Month to Pay
→ **2500 Rs**

EMI OFFER AVAILABLE FOR 24HR ONLY/-

- 1.SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
- 2.SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
- 4.SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
- 5.ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:



T&C APPLY



BY ANKIT AVASTHI SIR

LIMITED SEATS

और **EMI INFORMATION** के लिए

7878158882 अभी कॉल करें

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM



NCERT

FOUNDATION BATCH

**OFFER
FEE
4999 RS**

**LIMITED OFFER
REGISTRATION START**



1. SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2. SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4. SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5. ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6. UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE



FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

BY ANKIT AVASTHI SIR

UPPSC PRELIMS 2024 BATCH

FASTRACK COURSE

विशेषताएं / Features

- 1 300hr+ classes of Complete Syllabus with revision.
- 2 Special Classes for CSAT.
- 3 "Special Mantra" of Apni Pathshala.
- 4 A complete collection of yearly Current Affairs.
- 5 Exams Special Motivational Session by Ankit Avasthi Sir.
- 6 Classes will Available in Recorded Format After Live session with Best Quality.
- 7 Doubt Session for clearing doubt to your subject wise faculties.

Price
799 Rs



अंकित अवस्थी सर
के मार्गदर्शन में

UP PSC PRE 2024

TOTAL TEST 20



- आयोग के बदलते ट्रेंड के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन
- प्रश्न पत्र की पीडीएफ प्रिन्ट फार्मेट में उपलब्ध
- विषय विशेषज्ञों द्वारा रणनीतिक सत्र
- प्रत्येक प्रश्न की सटीक व सारगर्भित व्याख्या

Price 299Rs



By Ankit Avasthi Sir

Download Apni Pathshala
Application  **7878158882**

7D

28D

90D

365D

Apr

Mar

Feb

Percenta

31 Mar – 27 Apr 2024

Watch time (hours)

Not subscribed

52.1%



Subscribed

47.9%



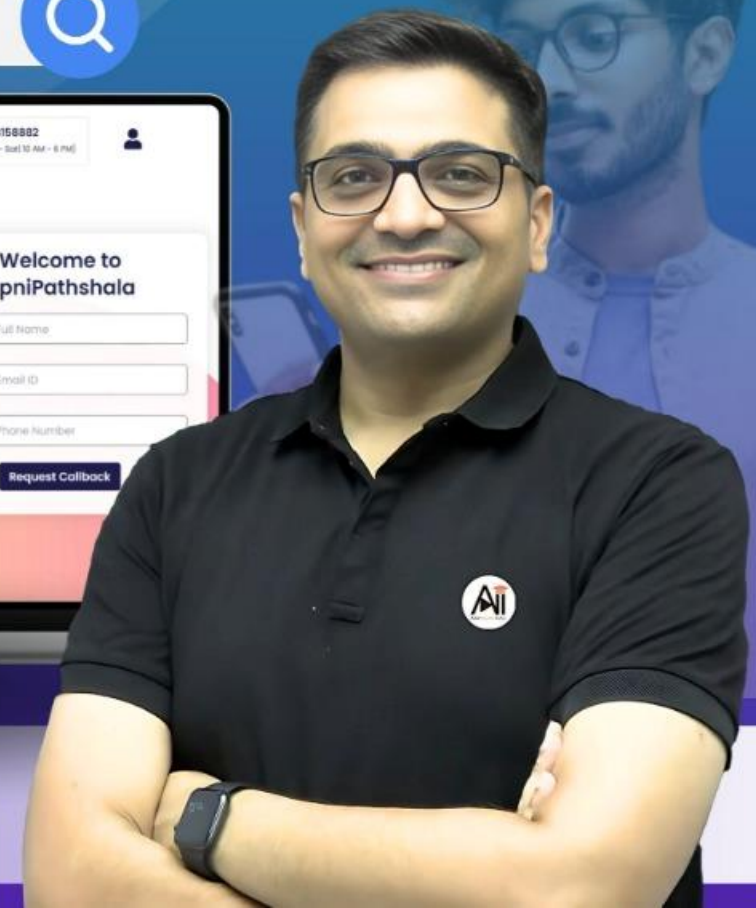
Uttara
x
PPTX +



visit Our Website :-

WWW. apnipathshala.com

- 1) BPSC Courses
- 2) RPSC Courses
- 3) UPPSC Courses
- 4) RNA And Class Pdf
- 5) video lecture
- 6) Daily Current Affairs
- 7) Infographic
- 8) Test series , Quiz



अब तैयारी हुई और आसान



1

अब तैयारी हुई और आसान

Download lessons and learn anytime, anywhere with Apni Pathshala

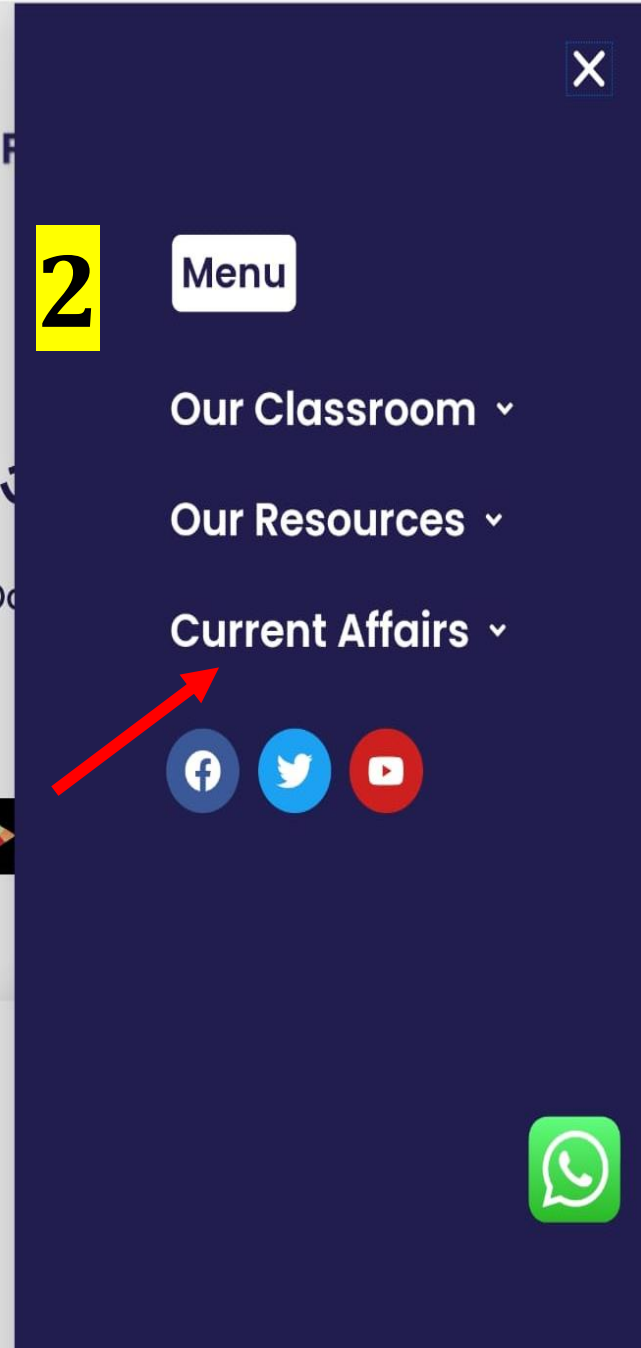
GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it on Windows 10

Welcome to ApniPathshala

Enter Your Full Name

Enter Your Email ID

Enter Your Phone Number



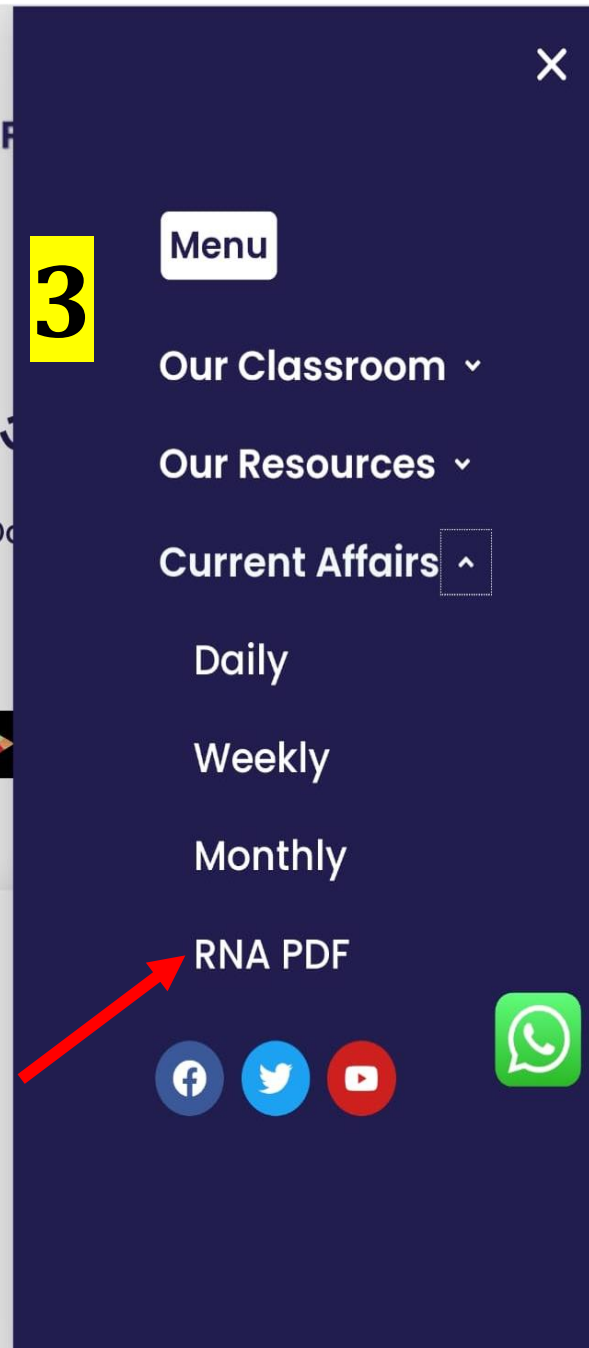
2

Menu

- Our Classroom ▾
- Our Resources ▾
- Current Affairs ▾

Facebook | Twitter | YouTube

WhatsApp



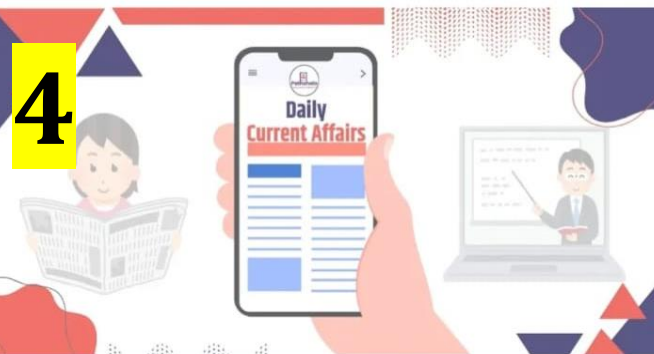
3

Menu

- Our Classroom ▾
- Our Resources ▾
- Current Affairs ▾
 - Daily
 - Weekly
 - Monthly
 - RNA PDF

Facebook | Twitter | YouTube

WhatsApp



4

Current Affairs | CA Daily

CA Weekly | CA Montly | RNA PDF

RNA (Real news and analysis) 18 may 2024
May 18, 2024

RNA (Real news and analysis) 17 may 2024
May 17, 2024

2024 GA FOUNDATION RECORDED BATCH



By Ankit Avasthi Sir

Price
1499 /-

**FOR रुद्र GS
FOUNDATION
STUDENTS**

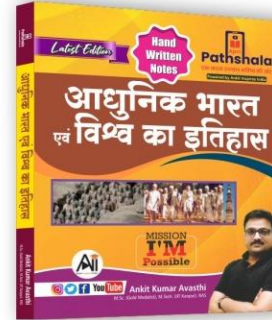
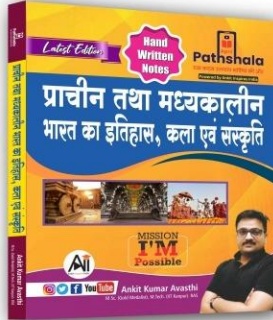
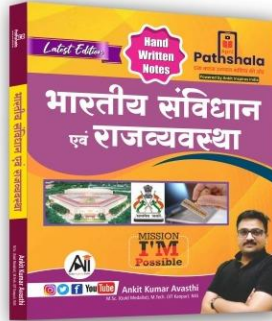
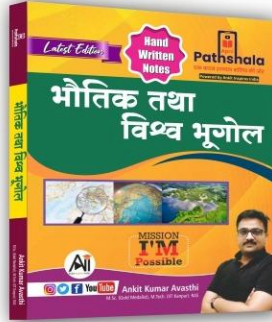
**पुराने विद्यार्थी
को मिलेगा 799 /-**

**Validity
1 Year**

APPLY COUPON CODE
ANKIT50

GA FOUNDATION

Hand Written
Notes



₹ Only
1999

6 पुस्तकों
का
सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**

- सिन्धु नदी का उद्गम कर्लाश पर्वतीय क्षेत्र में बीखर-सू हिमनद से होता है।
- तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।
- यह फमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
- यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
- पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
- पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
- सिन्धु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, रुद्रा, हुनजा, गिलागिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
- इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, पिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द्रास तथा जास्कर पंचनद
- सिन्धु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
- 'लेट' सिन्धु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

- बेरिनाग झील से होता है।
- * यह नदी बल्लर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
- किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
- इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नवीन परियोजना है।
- यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) पिनाब :- पिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालच्छा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (Confluence) से होता है।

- 1962 में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।

उदाहरण :- तुलहस्ती, सलाब, बगलिहार

- यह सिन्धु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम शैलांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

- हिमाचल प्रदेश में इन नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
- पंजाब में इस नदी पर धीन परियोजना स्थित है।

किया। इस सिद्धान्त के अनुसार नती ब्रह्माण्ड का कोई आदि है न ही कोई अंत है। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यद्यपि इस सिद्धान्त में प्रसरणशीलता समाहित है परन्तु फिर भी ब्रह्माण्ड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से सृजित होता रहता है।

3) दौलन सिद्धान्त (Pulsating Universe theory) :-
यह सिद्धान्त डॉ. एलन सैंडिज ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार आज से 180 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्माण्ड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीड़ित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा और यही क्रम चलता रहेगा।

4) स्फीति का सिद्धान्त (Inflationary theory) :-
यह सिद्धान्त अमेरिकी वैज्ञानिक अलेन गुथ ने दिया था। इस सिद्धान्त के अनुसार, विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट के पश्चात् अति अल्पकाल में ब्रह्माण्ड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ और ब्रह्माण्ड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई।

तारों का निर्माण :- तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन-चक्र का आरंभ होता है।

सौरमण्डल

सौरमण्डल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 गुरु, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्कार एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमण्डल कहलाते हैं।

सूर्य (SUN) :- सूर्य एक गैसीय गोलू है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम व 2.5% अन्य तत्व विद्यमान हैं। सूर्य का केन्द्रीय भाग कोर (Core) कहलाता है।

→ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केन्द्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है।

→ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है।

→ सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बीरियालिस कहते हैं।
और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा आस्ट्रेलिस कहते हैं।

₹ 1999

UPPSC, RPSC & BPSC की अपार सफलता के बाद

Apni Pathshala लेकर आया है



SSC | RAILWAY | POLICE

All One Day Competitive Exams के लिए



SUBSCRIBE NOW

By Ankit Avasthi Sir



CALL CENTRE

7878158882



HOW MAY I HELP YOU



AnkitInspiresIndia

➡ Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:

